

CHAPTER-V

ROLE OF THE PRESS AND DEVELOPMENT ISSUES WITH REFERENCE TO THE RAEBARELI DISTRICT

5.1 COVERGAE OF DEVELOPMENT NEWS BY THE NEWSPAPER- ANALYSIS OF NEWSPAPER CLIPPINGS

One of the steps of this study is to explore the coverage of news of Raebareli district in selected newspapers. Two newspapers Dainik Jagran and Amar Ujala are chosen for this study. Randomly clipping are collected for a period of one year and arranged below with their description. The description consists depiction of news content, its language, frequency, size, color scheme, page given to particular news are few legends for this analysis.

The special consideration were given to the news items specially contain info about social development, political development, role of political representative, action and initiatives done by elected political representative, economic development, means use by political representative to enrich the life style of the people of the area of Raebareli and how newspaper presented these items in their reporting through newspapers.

The clippings were selected in a view to get basic information about various aspects of development and fields related to the prospective development of the area of Raebareli.

Collection of clippings-

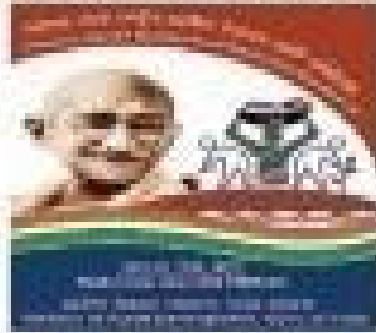
Name of Newspaper	Clipping Collected
Dainik Jagran	85
Amar Ujala	18
Total:	103

Table: 5.1

मनरेगा का काम कराया गया बंद

लखनऊ, 25 सितंबर : मनरेगा की कार्यालयों को बंद करने में लखनऊ विकास तथा विकास विभाग की कार्यवाही जारी है। इससे संबंधित सूचनाओं को मनरेगा की कार्यवाही के अंतर्गत कार्यवाही करने का काम विभागों में बिना किसी प्रकार के रुकावट किए जा रहा है।

इस प्रकार मनरेगा कार्यालयों को बंद करने में लखनऊ विकास तथा विकास विभाग की कार्यवाही जारी है। इससे संबंधित सूचनाओं को मनरेगा की कार्यवाही के अंतर्गत कार्यवाही करने का काम विभागों में बिना किसी प्रकार के रुकावट किए जा रहा है।



* प्रश्न करेंगे श्रम से निवृत्त

लखनऊ, 25 सितंबर : मनरेगा की कार्यवाही को बंद करने में लखनऊ विकास तथा विकास विभाग की कार्यवाही जारी है। इससे संबंधित सूचनाओं को मनरेगा की कार्यवाही के अंतर्गत कार्यवाही करने का काम विभागों में बिना किसी प्रकार के रुकावट किए जा रहा है।

इस प्रकार मनरेगा कार्यालयों को बंद करने में लखनऊ विकास तथा विकास विभाग की कार्यवाही जारी है। इससे संबंधित सूचनाओं को मनरेगा की कार्यवाही के अंतर्गत कार्यवाही करने का काम विभागों में बिना किसी प्रकार के रुकावट किए जा रहा है।

Clipping - 1

The News clipping–1 shown above, taken from Dainik Jagran, 25th September 2015, portrait news related to one of the popular development schemes of government of India - MNREGA. The scheme was facing hurdles in its implementation was reported by the newspaper in color with a picture of Mahatma Gandhi to make aware its readers. The impact was unknown; however the work of MNREGA was resumed later in this area due to this news in Dainik Jagran.

रायबरेली भी बने स्मार्ट सिटी : भाजपा

रायबरेली, लखनऊ : स्मार्ट सिटी चयन को लेकर जारी सियासत में भाजपा ने मेरठ के साथ रायबरेली की पैकेजारी भी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में रायबरेली से प्रत्याशी रहे वरिष्ठ अधिकारक आनंद अग्रवाल ने दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैजेंद्र नायडू से बैठकर रायबरेली को स्मार्ट सिटी की दौड़ से बाहर न करने की गुहार की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सखीकांत खानपेयी का कहना है कि शहर विधायक होने के नाते वह मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रकृत पक्षधर है, लेकिन रायबरेली की अनदेखी भी नहीं होने देगा।

दिल्ली में वैजेंद्र नायडू से मिलकर लॉटि अग्रवाल ने बताया मेरठ के साथ रायबरेली को भी उसका हक मिलना चाहिए। रायबरेली का पिछड़ापन कई प्रधानमंत्री देने के बाद भी खत्म नहीं हो सका। ऐसे में रायबरेली के विकास को स्मार्ट सिटी की सूची में दर्ज करना बहुत जरूरी है। अपने विधानसभा क्षेत्र मेरठ को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में निचले क्रम पर किए जाने से खफा डॉ. सखीकांत खानपेयी के स्वर भी बदले हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री से मिलकर मेरठ की कालत कर चुके खानपेयी ने स्मार्ट सिटी विवाद पनवाने के लिए प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया। उनका कहना है कि चयनित नगरों की पहली लिस्ट में दर्ज मेरठ का नाम रायबरेली के बाद करना प्रशासनिक बेईमानी है।

Clipping-2

Another news item as shown in news clipping-2 depicted other version for the Raebareli Parliamentary constituency. One of the leading political party of India stressed that to Raebareli may be considered for the 'Smart City' a scheme of central government. It may be the idea of political group but consideration of newspaper reflecting this item as important for its publication for the benefit of its reader group. It was observed that political motivation was speeded to masses about development of Raebareli parliamentary constituency. Political party stressed their positive views about the development of Raebareli parliamentary constituency. The reporter collected news with the political representative and published it through newspaper.

स्वच्छता अभियान की तैयारिया तेज

Publish Date:Sun. 28 Sep 2014 07:02 PM (IST) | Updated Date:Sun. 28 Sep 2014 07:02 PM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : देश में स्वच्छता क्रांति का वीणा उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्वच्छता जागरूकता अभियान का आगाज जिले में गंाधी जयंती दो अक्टूबर से प्रारंभ किया जाता है। प्रधानमंत्री के इस अभियान को जिले में निर्मल भारत अभियान के तहत चलाया जाएगा। बता दें कि दो अक्टूबर को जहां इस अभियान को एक साथ बृहद पैमाने पर चलाया जाएगा। वहीं जिले में यह अभियान दो अक्टूबर के पहले जागरूकता के लिए दो चरणों में चलाया गया है।

Clipping-3

Clipping-3 related to the Cleanliness Campaign which was initiated to start in district on 2nd October on birth anniversary of Mahatma Gandhi. The scheme was part of 'Nirmal Bharat Abhiyan'. Although the news item is too short but it capable to fulfill the information needs, one of the aim of newspaper. The clipping denotes that the Nirmal Bharat Abhiyan was implemented in two phases.

समग्र गांव के विकास में लापरवाही

Publish Date:Wed, 27 Aug 2014 07:33 PM (IST) | Updated Date:Wed, 27 Aug 2014 07:33 PM (IST)



समग्र गांव के विकास में लापरवाही

सलोन, संवाद सहयोगी : प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाले डालोहिया समग्र गांव में विकास कार्यों को करने में विभाग लापरवाही बरत रहे है। इसका उदाहरण सलोन ब्लॉक का समग्र गांव बेवली है। यहां आज तक शौचालय अधूरे पड़े हैं।

प्रदेश सरकार ने विकास से पिछड़े गांवों का संपूर्ण विकास कराने के लिए डालोहिया समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गांवों का चयन करने उन्हें शौचालय, सड़क, बिजली, पानी, पेंशन आदि से संतुष्ट किया जाना

था।

इस योजना के तहत वर्ष 2013-14 में ब्लॉक की ग्राम पंचायत बेवली का चयन किया गया था। यहां पंचायती राज विभाग की ओर से निर्मल भारत अभियान के तहत 493 लोगों के यहां शौचालयों का निर्माण कराना था। भले ही विभाग ने ये शौचालय बनवा दिए हैं लेकिन इनका काम अभी भी अधूरा है। इसके चलते गांव के लोग आज भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं।

Clipping-4

The government of local political representative is considered for a smooth development concern. Clipping-4 shows some evidence that some time these political representatives are not taking the developmental issues seriously. The clipping also depict that some of the scheme were initiated but abandoned in between. The newspaper tries to depict some news to inform its prospective readers about the seriousness of the political representatives.

गांवों में नहीं मिल रही बिजली

Publish Date: Mon, 01 Sep 2014 08:51 PM (IST) | Updated Date: Mon, 01 Sep 2014 08:51 PM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : प्रदेश सरकार के गांवों को दस घंटे बिजली देने के आदेश पर जिले में अमल नहीं हो पा रहा है। जगतपुर, खीरों, गुरुबक्शगंज, अटौरा आदि उपकेंद्रों में आए दिन कोई न कोई खराबी आती रहती है। इस कारण एक दो दिन के लिए आपूर्ति पूरी तरह बंद हो जाती है।

रविवार को पानी गिर जाने के बाद गुरुबक्शगंज की लाइन में दिक्कत आ गई देर शाम तक उसे ठीक नहीं किया जा सका था। इसी तरह जगतपुर में पांच एमवीए का ट्रांसफार्मर भी खराबी के कारण बंद कर दिया गया। अटौरा में डबल ग्रुप में बिजली की आपूर्ति की जा रही है। खीरों के फीडर लंबे होने के कारण फाल्ट आ जाता है। इसकी वजह से शेड्यूल के अनुसार बिजली की

आपूर्ति दस घंटे नहीं हो पा रही है।

शहर में अमल शुरू

प्रदेश सरकार के आदेश पर शहर में दो घंटे बिजली कटौती पर अमल शुरू हो गया है। सोमवार को दिन में केवल दस से बारह बजे तक मात्र दो घंटे की घोषित रोस्टिंग हुई। सुबह पांच से आठ बजे तक होने वाली अघोषित कटौती नहीं की गई। इससे लोगों को राहत मिली। अधिशासी अभियंता ग्रामीण वीके खन्ना ने बताया कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र उनके खंड में आता है। उपलब्ध संसाधन व मैन पावर के अनुसार गांवों को बिजली देने का प्रयास किया जा रहा है।

Clipping-5

According to news clipping no. 5 above the newspaper was of the view that the basic facilities like electricity was not available to the residents of Raebareli and peoples are not happy with the regular power breakdown. Newspaper was also in view that the rural areas are adequately supplied with the electricity. Apart from that the state government announced to provide 10 to12 hours of electricity supply to the residents of the parliamentary constituency of Raebareli.

बिजली-पानी से जूझ रहा रायबरेली : सोनिया

Publish Date: Mon, 01 Sep 2014 08:51 PM (IST) | Updated Date: Mon, 01 Sep 2014 08:51 PM (IST)

Jagran News

रायबरेली, जागरण संवाददाता : लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी बार जिले के दो दिवसीय दौरे पर आई सोनिया गांधी ने कहा कि रायबरेली बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार से बात होगी ताकि यहां के लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो सके।

सोमवार को दौरे के पहले दिन सोनिया गांधी ने 13.21 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के तहत बनी चार सड़कों और नौ लाख की लागत से बने एक बारातघर का लोकार्पण किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके साथ ही हरचंदपुर ब्लाक के फरीदपुर, अचलेश्वर रहवां, गुरुबक्शगंज, भीतरगांव व बकुलाही में लोगों से मुलाकात की। हर जगह लोगों ने बिजली, पानी, आवास

जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग की। इस पर सोनिया ने कहा कि रायबरेली में सबसे बड़ी समस्या बिजली-पानी की है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश सरकार के कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यहां के हालात आप खुद देख सकते हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार से बात करने की बात करने का आश्वासन दिया।

Clipping-6

Clipping-6 above suggests that some time political representative remakes of their center part for lacking basic facilities. Newspaper publish their views so that to aware the concern public about the responsibilities of every step of government. The basic amenities like electricity and drinking water was key the concern to make this statement through the newspaper. In a way it's away to make public clear about any issue through the newspaper.

सूरत और सीरत के फर्क पर वीवीआईपी जिले की बेचारगी

Publish Date: Sun, 31 Aug 2014 07:33 PM (IST) | Updated Date: Sun, 31 Aug 2014 07:33 PM (IST)

विमल पाण्डेय, रायबरेली : सोनिया जी सिर्फ योजनाओं से ही बात नहीं बनने वाली है जरा योजनाओं का अक्स और धरातल पर लाने के लिए किए गए श्रम का आंकलन भी कर लीजिए। तस्वीर सामने आ जाएगी। कहीं इंदिरा आवास को लेकर लाचार दर-दर भटक रहे हैं तो कहीं शुद्ध पानी के लिए गरीब लड़ रहा है। आपके प्रयासों से विकास के नाम पर पैसा तो खूब मिला है पर अभी पटरी पर योजनाएं दौड़ नहीं पा रही हैं। सबकी निगाह सिर्फ व्यवस्था पर टिकी हुई है कि शायद अब लंबित कामों को गति मिल जाए।

यह पीड़ा है रायबरेली की, यहा के उन लोगों का दर्द है जिन्होंने रायबरेली के बेहतर विकास के सपने देखे हैं। लोक सभा चुनाव जीतने के बाद सोमवार को दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया

गंधी रायबरेली का दौरा करने आ रहीं हैं। केंद्र में सत्ता भाजपा की आने के बाद रायबरेली में काफी उथल-पुथल हुई। यह बेचारगी आम लोगों के कौतूहल से जुड़ी हुई है कि शायद सत्ता परिवर्तन का दंश अब रायबरेली वासियों को योजनाओं के बदहाली के रूप में न देखना पड़ जाए।

Jagran News

सत्ता परिवर्तन के बाद इन योजनाओं पर है फोकस :

रायबरेली में कांग्रेस कार्यकाल में दस हजार करोड़ से भी अधिक योजनाओं के कार्याकल्प की तैयारी की गई। योजनाओं को शुरू भी किया गया। सरकार बदलने के बाद जिन योजनाओं में थोड़ा मंदी आई है वह एक हजार करोड़ का एम्स अस्पताल प्रोजेक्ट, शहर में 18-18 करोड़ की लागत से बने वाले मिंट पार्क और सिटी रिसोर्स सेंटर प्रमुख है। बता दें कि इन योजनाओं में सोनिया गंधी की प्राथमिकताओं में एम्स अस्पताल का निर्माण प्रमुख है। इन दिनों रंगदारी को लेकर निर्माण कार्यों में भारी भरकम प्रोजेक्ट लंबित हैं। इंदिरा आवास प्रदेश के जिन गिने चुने जनपदों में सर्वाधिक दिए जा रहे हैं उनमें वीवीआईपी रायबरेली एक है। आवास के लिए गरीबों की आने वाली लगातार शिकायतें और आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर सरकारी अमले की कार्यशैली भी सोनिया के दौरे में फोकस के रूप में रहेगा। रायबरेली में अब तक लाई गई योजनाओं के जमीनी हकीकत के सवाल पर गांवों से बहुत सारे सवाल फिजाओं के साथ सरपट दौड़ते मिलेंगे।

Clipping-7

Clipping-7 above is a full story of development with a byline of correspondent. The news raised development issues emphasis in Daink Jagran of dated 31st August 2014 that the political representative was unable to fulfill their promises make to the masses. Masses are still looking for instant action to consider the pending work related to the parliamentary constituency.

संगठनों ने सोनिया को बताई समस्याएं

Publish Date: Tue, 02 Sep 2014 06:31 PM (IST) | Updated Date: Tue, 02 Sep 2014 06:31 PM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : सांसद सोनिया गांधी के दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात के साथ हुई। इनमें आईटीआई कर्मियों, रेल कोच भूमि विस्थापित, बीटी प्रशिक्षु समेत कई संगठनों ने लिखित तौर पर समस्याओं से श्रीमती गांधी को अवगत कराया।

मंगलवार को सुबह भुएमऊ गेस्ट हाउस में सांसद सोनिया गांधी ने जनता दरबार लगाया। इसमें एनआरएचएम के तहत संविदा पर तैनात एमपीडब्लू संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उच्च न्यायालय ने उन लोगों को एक साल के लिए बहाल किया है लेकिन विभाग ने छह माह का ही नवीनीकरण किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेस प्रकोष्ठ का प्रतिनिधि मंडल सांसद से मिला।

संगठन ने सांसद से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति को बनाए रखने का अनुरोध किया। आईटीआई लिमिटेड श्रमिक संघ ने भी मुलाकात कर तीन माह से वेतन नहीं मिलने की बात बताई। इसके साथ ही सेवानिवृत्त की आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष कराने का अनुरोध किया।

भारतीय स्वच्छकार एकता मंच के प्रतिनिधि मंडल ने शहर के एकता विहार में समाज के लिए बारादरी निर्माण कराने की मांग की। बीटीसी 2011 बैच के प्रशिक्षणार्थियों ने सोनिया से मिलकर बताया कि वह लोग पूरे प्रदेश में 15 हजार बीटीसी उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी हैं। जिन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है जबकि टीईटी उत्तीर्ण लोगों की भर्ती की जा रही है। ऐसे में वह लोग बीटीसी करने के बाद भी बेकार हैं। लालगंज रेल कोच फैक्ट्री के भूमि विस्थापित किसानों ने सोनिया से मिलकर बताया कि भूमि देने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। इससे वे लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। खेल प्रशिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मिलकर बताया कि इस बार राजीव गांधी सद्भावना दिवस पर कोई खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कराया गया। उनसे मिलने के लिए रहवां गांव के विकलांग मनोज कुमार भी पहुंचा। सांसद ने उसे बुधवार को तिलक भवन बुलाया। इसके साथ ही उसका इलाज कराने के लिए ओएसडी धीरज श्रीवास्तव को निर्देशित किया। यहां पर व्यापारी नेता भी अपनी समस्या को लेकर मिलने पहुंचे।

Clipping- 8

Reporter related with newspaper clipping above seems regularly follows the political representative and keep eye-on their movement. Dainik Jagran clipping-8 above of dated 2nd September, 2014 depicts the same. Various organizations referred their grievances directly to their apex political representative. The news depicts that every concern who wish to have a face to face got the opportunity. Similarly reporters cover other development related incidents.

एम्स पहुंच जानी रंगदारी मामले की हकीकत

Publish Date: Tue, 02 Sep 2014 06:03 PM (IST) | Updated Date: Tue, 02 Sep 2014 06:03 PM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दरियापुर में रंगदारी मामले की जानकारी पाकर मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वहां पहुंची। उन्होंने कार्यदायी संस्था के मैनेजर एचआर से बात कर मामले की हकीकत जानी। इसके साथ ही परिसर में पुलिस चौकी स्थापना पर बात की। उन्होंने यहां पर श्रमिकों से बात करके परिवार व काम के बारे में भी पूछा।

दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन मंगलवार को सांसद सोनिया गांधी राही ब्लाक के सनही में सौर ऊर्जा संचालित पेयजल योजना का शुभारंभ करने के बाद दरियापुर स्थित एम्स पहुंचीं। विदित हो कि कुछ दिन पहले यहां भाजपा नेता के रंगदारी मांगने को लेकर

विवाद हुआ था। इसमें कार्यदायी संस्था की ओर से भाजपा नेता पुष्पेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। सोनिया ने एम्स के निर्माणाधीन ब्लाक में जाकर कार्यदायी संस्था के मैनेजर एचआर स्वप्नेश तिमोधी से रंगदारी मामले की जानकारी ली। इस पर श्री तिमोधी ने ऐसी किसी भी बात से इन्कार कर दिया। मैनेजर ने बताया कि स्थानीय प्रशासन हर प्रकार की सहयोग कर रहा है। उन्होंने परिसर के अंदर पुलिस चौकी स्थापना की बात करने के बाद श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य के इंतजाम, कार्य पूर्ण होने की स्थिति, काम करने वाले श्रमिकों की संख्या आदि के बारे में पूछा। सोनिया ने यहां कार्यरत श्रमिकों से परिवार, बच्चों आदि के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद कार्यदायी संस्था के कार्यालय का जायजा भी लिया।

Clipping-9

The clipping-9 of Newspaper dated 2nd September 2014 shows the concerned of political leaders of their well known AIIMS project for the benefit of people and grab the information regarding the problems faced during this project. People face problems by different local political leaders and asked to the development manager for the problems occurring in the development of project.

बंदरबांट के भंवर में सोनिया का ड्रीम प्रोजेक्ट

Publish Date: Tue, 02 Sep 2014 07:37 PM (IST) | Updated Date: Tue, 02 Sep 2014 07:37 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : रायबरेली में बड़ी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में अफसरों की अनदेखी के कारण ठेकेदार बंदरबांट कर देते हैं। अलबत्ता योजना सही दिशा में जा ही नहीं सकती है। सोनिया गांधी के अथक प्रयासों से लाई गई योजना सिटी रिसोर्स सेंटर के निर्माण में सियासी अड़चने भले ही न हों लेकिन कार्यदाई संस्था ने कच्छप गति निर्माण कार्य के कारण सब कुछ हासिए पर कर दिया है। ऐसे में लाख टके का सवाल यह है कि क्या यह सिटी रिसोर्स सेंटर बन

कर भी तैयार होगा या नहीं?

Clipping-10

The clipping-10 of 2nd September 2014 Newspaper exposes the failure and careless behavior of government officers on the City Resource Centre scheme development projects. This news with a color Photograph questioned that, how could schemes of development will become successful.

सौर उर्जा आधारित पेयजल योजना का श्रीगणेश

Jagran News

Publish Date: Tue, 02 Sep 2014 07:28 PM (IST) | Updated Date: Tue, 02 Sep 2014 07:28 PM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : मंगलवार को दौरे के अंतिम दिन सोनिया गांधी जहां गईं वहां पर ग्रामीणों ने उन्हें मूलभूत जन सुविधाओं नहीं होने की बात बताई। सोनिया ने सभी की बात गंभीरता से सुनकर सिर हिलाकर समस्या निस्तारण कराने का जबाब दिया।

मंगलवार को सोनिया गांधी सबसे पहले राही ब्लाक के सनही गांव पहुंची। यहां पर एनटीपीसी सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से एक हास पावर की क्षमता वाले सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना की स्थापना की गई है। इसका शुभारंभ सोनिया ने पूजन के साथ किया। यहां पर विकलांग यशवंत सिंह ने उन्हें बताया कि खेतों की सिंचाई करते समय इंजन फटने से उसका बायां पैर कट

गया। इस पर सोनिया ने उसे जयपुर से नकली पैर लगवाने का भरोसा दिया।

यहां पर सांसद ने ग्रामीण राजेश कुमार से गांव की आबादी पूछी और बच्चों से पढ़ाई के बारे में जानकारी लेने ली। यहां पर ग्रामीणों ने उन्हें बिजली कम आने की बात कहते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने की मांग की। यहां से सोनिया का काफिला नहरी चौराहे पर पहुंचा। यहां कल्लू राम ने जगतपुर रजबहा सूखा होने की बात बताई, तो अर्जुन प्रसाद व माई दीन ने उनसे नलकूप लगवाने की मांग कर डाली। औधुनाथ गंज में कांग्रेसी रज्जू सिंह ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए आर्थिक सहायता व एक विकलांग कार्यकर्ता कुसुमा देवी के लिए आवास मांगा।

भदोखर में लोगों ने सोनिया से इंटर कालेज व बिजली की मांग की। यहां पर युवती कृष्णा मिश्रा ने रोते हुए अपने लिए नौकरी मांगी। यहां पर रविकांत गुप्ता ने बताया कि उनके भाई विजयकांत शिक्षक थे। मार्ग दुर्घटना में भाई की मौत के बाद विभाग भाभी नीलम को चपरासी की नौकरी दे रहा है जबकि भाभी पढ़ी-लिखी है, उन्हें शिक्षक की नौकरी मिलनी चाहिए। यहां से निकल कर सोनिया झकरासी गांव पहुंची। जहां अशोक चौरसिया के घर पहुंची। जहां गृहस्वामी ने उनका स्वागत क्रीम वाला बिस्कुट खिला कर किया। यहां मौजूद युवतियों से उन्होंने पढ़ाई व बिजली के बारे में जानकारी ली। गांव में पूर्व विधायक रमेश चंद्र शुक्ला के घर के सामने महिलाओं से समूह के बारे में पूछा, तो महिलाओं ने समूह की जानकारी से इंकार किया। इस पर सोनिया ने गांव के एक युवक को राजीव गांधी समूह बनाने के लिए कहा। गांव के बाहर निकलते समय सोनिया ने काफिला रोक कर खेतों पर काम कर रही रामेश्वरी व फूलमती से भी हालचाल लिए। इसके बाद महिला सीता देवी के झोपड़ी में जाकर परिवार आदि के बारे में जानकारी ली। एम्स गेट पर सोनिया ने छात्र प्रशांत, अभिनव, सचिन से बिजली आपूर्ति व एम्स निर्माण की गति के बारे में पूछा। इस पर छात्रों ने बिजली कम मिलने व एम्स निर्माण की गति धीमी होने की बात बताई। सोनिया यहां से दिवंगत सुरेंद्र कुमार पाठक के घर गईं। जहां परिजनों से मिली और बच्चों के बारे में जानकारी ली। यहां से निकल कर वे कांग्रेस एमएलसी के घर पहुंचीं। यहां उन्होंने इनके परिजनों के साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

Clipping-11

This clipping-11 dated 2nd September 2014 of Newspaper report the minute to minute schedule of the MP's last day in the area in which MP inaugurated the water supply scheme for the farmers so that it will help them in the production of agriculture with the Political representative also listen to the problems faced by common peoples in the area and promises to solve it as soon as possible by doing this she goes to see the construction works in AIIMS.

खुले में शौच जाना मजबूरी

Publish Date:Thu, 04 Sep 2014 07:16 PM (IST) | Updated Date:Thu, 04 Sep 2014 07:16 PM (IST)



रायबरेली जागरण संवाददाता : जिले की अन्य तहसीलों की तरह महाराजगंज तहसील क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है। 118 प्राथमिक व 33 जूनियर विद्यालय हैं। इसी तहसील क्षेत्र के शिवगढ़ विकास क्षेत्र में 103 प्राथमिक और 29 जूनियर स्कूल हैं। बछरावां में 104 प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों की संख्या 33 है। तीनों विकास खंडों में प्राथमिक विद्यालय 325 और 91 जूनियर विद्यालय हैं।

महाराजगंज क्षेत्र में चार सौ से अधिक विद्यालयों में 24 विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें शौचालय ही नहीं बने हैं। आधे से अधिक विद्यालयों में शौचालय होने के बाद भी प्रयोग नहीं हो रहे हैं। शौचालयों की हालत बद से बदतर हो गयी है। महाराजगंज क्षेत्र के कसबे के ही विद्यालय की बात की जाए तो

कूड़े के ढेर के किनारे शौचालय तो हैं इनकी दशा देख कर लगता है कि ये महीनों से बंद पड़े हैं। दरवाजे टूटे हुए हैं, फर्श की हालत बद से बदतर है। सीट का कोई अता-पता नहीं है। विद्यालय की कक्षा पाच की छात्रा शालू, शाहिनी, रिंकी और सूरजवती आदि की माने तो वे विद्यालय समय में दूर खेत में शौच के लिए जाती हैं।

बछरावां के मदार खेड़ा, जजुआ खेड़ा आदि प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय बने ही नहीं हैं। शिव गढ़ विकास खंड के भवानी गढ़ चौराहा प्राथमिक विद्यालय, मनऊ खेड़ा प्राथमिक विद्यालय व देहली जूनियर हाई स्कूल में शौचालय पूरी तरह से निष्प्रयोज्य हो चुके हैं। यहां दरवाजे टूट कर गायब हो चुके हैं, सीट का कोई अता-पता ही नहीं है। छात्र व छात्राएं खुले में ही शौच जाने के लिए मजबूर हैं।

Clipping-12

The clipping-12 of Newspaper 4th September 2014 with an image of a school going girls show the mirror to the facilities provided by the government school in many Tehsil of the District. This report shows that mostly schools do not have toilets and who have are not in situation to use because of which students (especially girls) have to face many problems every day.

नैतिक मूल्यों की कार्यशाला से तैयार हो रहे एकलव्य

Publish Date:Thu, 04 Sep 2014 07:16 PM (IST) | Updated Date:Thu, 04 Sep 2014 07:16 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : सर्वत्रविजय मिच्छेत् पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्। एक गुरु की अभिलाषा पूरे विश्व को जीतने की होती है पर पुत्र और शिष्य के सामने वह हारने की अभिलाषा केवल इसलिए करता है कि उसकी दी हुई शिक्षा ने कुछ नया हासिल किया है।

रायबरेली में शिक्षा की नींव कमजोर होता देख आहत डा. किरन श्रीवास्तव ने मन में ठान लिया कि शिक्षा की अलस जगाने के लिए ही काम करना है। मसलन प्राध्यापक बन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना शुरू कर दिया। एक जुनून है अगर बच्चा बेहतर पढ़ जाए तो समाज की दिशा और दशा दोनों ही बेहतर हो जाएगी।

इनकी लालसा रही कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का ज्ञान होना सबसे आवश्यक है। अगर बच्चे मूल्य और मनुजता का ज्ञान नहीं रख पाएंगे तो वे समाज की मुख्य धारा में कभी आ ही नहीं सकेंगे।

बच्चों में सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि उनमें मौलिक ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। इनकी हर कक्षा नैतिक मूल्यों की सुरक्षा से जुड़ी होती है। बच्चे को अगर कम अंक मिले तो इन्हें इतनी चिंता नहीं होती है जितनी बच्चों में संस्कारों का अभाव इन्हें आहत करता है। ऐसी कमियों को दूर करने के लिए ही डा. किरन श्रीवास्तव की संस्कारशाला नित नए सोपानों का निर्माण करने में सफल रही है।

Clipping -13

The clipping -13 of 4th September predict the motivation and for the better education in which Dr. Kiran Srivastava decided to motivate the students not only in according to course Dr. Kiran wants that the student will get and do more than the books education that can play a major role for the development of society.

'अच्छी पहल और स्वागत योग्य कदम'

Publish Date: Fri, 05 Sep 2014 06:04 PM (IST) | Updated | Jagran News | 2014 06:04 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और प्रबंधकों ने प्रधानमंत्री की पहल को स्वागत योग्य बताया है। कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण सुनने से बच्चों की सोच का दायरा बढ़ेगा। आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस पर भाषण दिया है।

राजकीय बालिका इंटर कालेज सदर की प्रधानाचार्य पार्वती त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए दिशा दिखाएगा। छात्राओं में भी देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुनने को लेकर उत्सुकता दिखी।

वैदिक इंटर कालेज के प्रधानाचार्य शत्रुघ्न सिंह चौहान ने कहा कि देश भर में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा में वित्तविहीन विद्यालयों के पास संसाधन नहीं है। पीएम को पहले मूलभूत संसाधन जुटाना चाहिए। इसके बाद ही जापान, अमेरिका की तरह

शिक्षा व देश को हाईटेक किया जाए। पीएम की पहल अच्छी है प्रधानमंत्री ने स्कूलों में शौचालय बनवाने की बात की है।

राजकीय इंटर कालेज सदर के प्रधानाचार्य मिथलेश कुमार ने कहा कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो शिक्षा, स्कूल, शौचालय, इंटरनेट, कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं। बच्चों से शिक्षक दिवस पर सीधे संवाद किया है। कई बच्चों ने सारगर्भित बातें की हैं, जिनको सभी बच्चों ने सुना है।

एनएसपीएस ग्रुप आफ स्कूल के प्रबंधक शशिकांत शर्मा ने कहा कि वित्तविहीन विद्यालयों के पास भवन, हाल, टीवी, बिजली, इंटरनेट का अभाव है। पहले इसके इंतजाम पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा पीएम का भाषण विद्यालय अवधि में होता तो ज्यादा बच्चे भाषण सुन पाते। एक बार घर जाने के बाद बच्चों को दोबारा बुलाना साधन विहीन स्कूलों के लिए संभव नहीं रहा। प्रधानमंत्री की सोच सकारात्मक है लेकिन संसाधन जुटाना प्राथमिकता होनी चाहिए।

Clipping -14

The clipping -14 of 5th September was based on the speech of Prime Minister on the occasion of teacher day. The group of teachers expresses their positive expression on the provisions and announcement made by the PM for the development of educational sector.

पेंशन खाते में जाते ही मिलेगा एसएमएस

Publish Date: Sun, 07 Sep 2014 06:18 PM (IST) | Updated Date: Sun, 07 Sep 2014 06:18 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : प्रदेश में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक सुविधा शुरू होने वाली है। यह सुविधा है एसएमएस अलर्ट की। इसके तहत पेंशन लाभार्थी के खाते में पैसे आते ही उसके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से सूचना मिलेगी।

प्रदेश में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन योजना व राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ जैसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत लाखों लाभार्थियों को छमाही या सलाना पेंशन खातों में भेजी जा रही है। यह पेंशन उनके खातों में पहुंची कि नहीं इसकी जानकारी नहीं होने से लोग विभाग

या बैंकों के चक्कर काटते रहते हैं। इसी के चलते समाज कल्याण विभाग ने वेब पोर्टल तैयार करने की निर्णय लिया है। जिसके तहत पेंशन धारकों के खाते में पैसे जाते हैं उन्हें एसएमएस पहुंचेगा। विदित हो कि बीते दिनों शासन ने पेंशन लाभार्थियों के खाते सीबीएस करने के साथ ही उनके मोबाइल नंबर भी लिए हैं। इन खाता धारकों को फिलहाल बैंक की ओर से पेंशन आने की सूचना एसएमएस के माध्यम से भेजी जा रही है लेकिन अब विभाग भी अपने स्तर से उन्हें पेंशन जाने की सूचना भेजेगा। इस सुविधा के शुरू होने के बाद पेंशन लाभार्थियों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल विभाग पोर्टल बना रहा है। जैसे ही यह पोर्टल बनकर तैयार होगा। पेंशन लाभार्थियों का पूरा डाटा इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। जिसके बाद यह सुविधा लागू हो जाएगी।

Clipping-15

The Clipping-15 of 7th September 2014 informs that the digitalization is going to enter in the pension department of State which will facilitate to the pensioners. If this will be successful done then pensioners does not have to check there account, the message will automatically send to their number after sending pension in their account. The District social welfare officer also informed that for this the portal is making the data uploaded so that pensioner will received the information at their home.

स्वच्छ पानी का बताया महत्व

Publish Date: Tue, 23 Sep 2014 01:08 AM (IST) | Updated Date: Tue, 23 Sep 2014 01:08 AM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : निर्मल भारत अभियान के तहत सोमवार को राही ब्लाक परिसर में आयोजित कार्यशाला में जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने पेयजल की गुणवत्ता और दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए गांवों में सफाई व्यवस्था को और भी मजबूत करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने गांवों में बेहतर सफाई के लिए ग्राम प्रधानों को सजग किया तो वहीं स्कूल कालेजों से लेकर सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छ पेयजल को लेकर उन्होंने विस्तृत चर्चा की

कार्यशाला का उदघाटन जिलाधिकारी ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। निर्मल भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यशाला में जिला पंचायतराज अधिकारी डा. संजय यादव ने विस्तार से चर्चा करते हुए विद्यालयों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर विस्तार से चर्चा करते हुए जागरुक किया। जिला विकास अधिकारी आर एन सिंह ने कहा कि स्कूल कालेजों में स्वच्छ पानी और स्वच्छता को लेकर शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। परियोजना निदेशक इंद्रसेन सिंह ने कहा कि पानी के महत्व को समझना आवश्यक है पानी के मोल को अगर न समझे तो आने वाले दिनों में इससे बड़ी-बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। कार्यशाला में जिले के विभागीय अधिकारियों समेत ब्लाक के अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया।

Clipping 16

The clipping 16 of Newspaper dated 23rd September 2014 informed about the workshop organized for the importance and benefits of clean water in which District Magistrate assured that this issue is will be taken seriously and mainly in the rural areas the water cleanness system will be stronger.

पाठ्य सामग्री पाकर खिले चेहरे

Publish Date:Sun, 28 Sep 2014 01:06 AM (IST) | Updated Date:Sun, 28 Sep 2014 01:06 AM (IST)



लालगंज संवाद सहयोगी :

सेवा भारती संस्था लालगंज ने दोसर वैश्य धर्मशाला मे शिविर आयोजित कर दो सैकड़ा से अधिक पितृविहीन एवं असहाय बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की। बैग व पाठ्य सामग्री पाकर बच्चे चहक उठे।

कार्यक्रम के आयोजक एवं सेवाभारती के जिलाध्यक्ष के.सी.गुप्ता ने कहा कि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसलिए मानव का धर्म है कि सक्षम होने पर उसे निर्धन व असहायों की यथा सम्भव मदद करनी चाहिए। पूर्व विधि न्याय मंत्री गिरीष नारायण पाण्डेय , भाजपा सुशासन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह संयोजक के.एस.सिंह, पूर्व

प्राचार्य एस.एन.सिंह, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश नारायण सिंह बच्चा बाबू, उमेश चन्द्र श्रीवास्तव आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

Clipping-17

In the clipping-17 of Sunday 28th September inform about the donation given by Seva Bharti organization to the poor children at the same it also persuade that providing school bags and books is so much important and helpful for children in the study.

जल्द बनेगा बैती संपर्क मार्ग

Publish Date:Sun, 28 Sep 2014 09:37 PM (IST) | Updated Date:Sun, 28 Sep 2014 09:37 PM (IST)

शिवगढ़ संवादसूत्र: आये दिन कई लोगों को घायल करने वाले बैती भलभद्रखेड़ा मार्ग का दिन बहुरने वाला है। गृहे और बोलडर से भरे इस मार्ग को विधायक राम लाल अकेला ने जल्द से जल्द बनवाने की बात कही है। यहां कमला देवी हनुमान पटेल महिला डिग्री कालेज का शिलान्यास कार्यक्रम में आए अकेला ने कहा कि क्षेत्र की सड़क को ठीक करने के लिए जल्द ही आदेश दिया जाएंगे। दर्जनों गावों को जोड़ने वाले इस सम्पर्क मार्ग कालेज से पूर्व बनवाने की बात कही। दो दशक पूर्व से बोलडर से भरे बैती बलभद्र खेड़ा सम्पर्क मार्ग पर राहगीर एवं स्कूली छात्र गिरकर चोटिल होते रहते हैं। लोगों द्वारा इसके डमरीकरण के लिए लगातार मांग की जा रही थी। इसकी शिकायत जिलाधिकारी,

सांसद सोनियागांधी और राहुल गांधी के अलावा क्षेत्र प्रतिनिधियों से कई बार की गई।

Clipping 18

In the clipping-18 of 28th September 2014 reporter predict the news of worst condition road by which many people are facing trouble to ride vehicles and reason for accident daily. This road is going to reconstruct as soon possible by the MLA on the demand of resident peoples and students.

एक को फसल विचार गोष्ठी

Publish Date: Sun, 28 Sep 2014 08:34 PM (IST) | Updated Date: Sun, 28 Sep 2014 08:34 PM (IST)

बाजारशुक्ल, संवादसूत्र: क्षेत्र के किसानों के लिए उर्वरक व शोधित फाउंडेशन बीज उपलब्ध कराने के लिए लंबी समय से सतत प्रयत्नशील हरखूमऊ कृषि वानिकी सहकारी समिति पर आगामी एक अक्टूबर बुधवार को पूर्वान्ह 11 बजे से प्रदेश के

प्रगतिशील एवं उन्नतिशील किसानों विभिन्न प्रांतों से आए हुए कृषि विशेषज्ञों की मौजूदगी में एक विशाल रबी फसल विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। रबी फसल विचार गोष्ठी के साथ ही बीज विधान संयंत्र के भंडार गृह का उदघाटन मुख्य अतिथि प्रबंध निदेशक इफको डा. उदयशंकर अवस्थी द्वारा किया जाएगा। रबी फसल विचार गोष्ठी एवं भंडार गृह उदघाटन की अध्यक्षता आईएफएफडीसी के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। हरखूमऊ कृषि

वानिकी सहकारी समिति के सचिव अशोक सिंह ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उन्नतिशील व प्रगतिशील किसान विभिन्न प्रांतों से आए हुए कृषि विशेषज्ञों की मौजूदगी में उर्वरक एवं शोधित फाउंडेशन बीजों के बारे में उपस्थित किसानों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जाएंगी।

Clipping-19

In the clipping-19 of Newspaper of 28th September with sources reporter inform the farmers that there final outcome that is not sold from a long time will be used by government soon and for this a meeting was held of a committee that was inaugurated by Director of IFCO which is lead by the Director of IFFDC.

सरेनी में बनेंगे दस बड़े तालाब

Publish Date: Tue, 30 Sep 2014 06:00 PM (IST) | Updated Date: Tue, 30 Sep 2014 06:00 PM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : सरेनी ब्लाक में जल संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में जिले की सरकारी मशीनरी ने नए कदम उठाए हैं। सरेनी ब्लाक जो भूजल के नजरिए से क्रिटिकल जोन माना जाता है यहां दस नए बड़े तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। बचत भवन में मंगलवार को आयोजित तकनीकी समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने क्रिटिकल ब्लाकों के विभिन्न स्थानों में नए तालाब खुदवाए जाने के निर्देश दिए। जल्द ही इस पर कार्ययोजना मांगी गई है।

Clipping-20

The Clipping 20 of 30th September 2014 is to establish 10 new river bank for the safety of critical zone to safe from the flood and for this DM ordered to start work on this project and desired a report on this matter.

गांवों की स्वच्छता के सूत्रधार बनेंगे ग्राम प्रधान

Publish Date: Tue, 30 Sep 2014 01:02 AM (IST) | Updated Date: Tue, 30 Sep 2014 01:02 AM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : गांव से लेकर शहर तक हर ओर बस एक ही नारा कि स्वच्छ और स्वस्थ रहे देश हमारा। समाज में पंक्ति के रूप में खड़े प्रथम व्यक्ति से लेकर आखिरी व्यक्ति तक स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता के लिए जिला स्तर से कई प्लान तैयार किए गए हैं। ग्राम प्रधान इस अभियान में सफलता के मुख्य सूत्रधारक बनेंगे। ग्राम प्रधान ही गांव की जनता को स्वच्छ गांव बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। ब्लॉकों में अधिकारी गंधी जयंती के पहले ही सबकुछ प्लान बनाकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं।

जिले में स्वच्छता अभियान को सार्थक बनाने के लिए ग्राम प्रधान बनेंगे ब्रांड एंबेस्डर। ब्लॉक क्षेत्र के आने वाली हर ग्राम सभा में ग्राम प्रधानों को गांव की चौपालों में इस बृहद कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी देने को कहा गया है।

ग्राम प्रधान गांव में एक अपनी टीम भी बनाएं जो चिन्हित स्थल में अभियान को चलाए जाने के लिए प्रेरित करेंगे।

आइए जिले को बनाए स्वच्छ और निर्मल

गांव की हर गली साफ रहे, हर मुहल्ला साफ दिखे तो एक स्वच्छ भारत की परिकल्पना साकार हो। इसके लिए हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाए तो मिशन की तरह चलाए जाने वाले इस अभियान को आत्मबल और संबल दोनों ही मिल जाए।

Clipping-21

The clipping-21 of 30th September predicts the news for making the Swachh Bharat Abhiyan a successful mission by announcing that the main role to make it successful is of village head. The village head have to make a team who will persuade in the selected area. The Swachchhta Abhiyan is a mission to make society a clean and beautiful on the 2nd October that is a Ghandi Jayanti.

शहीद स्थलों में चलेगा सफाई अभियान

Publish Date: Tue, 30 Sep 2014 08:07 PM (IST) | Updated Date: Tue, 30 Sep 2014 08:07 PM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : जिले में स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रशासनिक पहल तेज हो रही है। जिले के निकाय क्षेत्रों में बने शहीद स्थलों की सफाई करने का अभियान चलाया जाएगा। निर्मल भारत अभियान की गूँज जहां गांव होगी वहीं नगर पालिका और नगर पंचायतों में शहीद स्थलों को चमकाने का भी अभियान चलाया जाना है। जिलाधिकारी ने सभी अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है गांधी जयंती में शहीद स्थलों की बेहतर सफाई कराई जाए।

निर्मल भारत अभियान के तहत जिले में महापुरुषों और शहीद स्मारक स्थलों को भी साफ कराने का वीणा उठाया जाएगा। हर

नगर पंचायत क्षेत्र में यह अभियान चलाया जाएगा।

शहर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान अंतर्गत शहीद स्थल में अभियान को गति देने के लिए पालिका के अधिशाषी अधिकारी पीएन सिंह ने रुपरेखा तैयार की है।

Clipping-22

The another Clipping-22 is of 30th September is also related to Swachchhta Abhiyan in which peoples are informed to clean the Martyr places in the district on the order of DM to all officers and to work on this a plan is also made.

ग्रीनहाउस से लाभान्वित हों किसान

Publish Date:Thu, 02 Oct 2014 01:11 AM (IST) | Updated Date:Thu, 02 Oct 2014 01:11 AM (IST)

ऊंचाहार, संवाद सहयोगी : कम लागत में अधिक फायदे वाली फसल के लिए विशेषज्ञों ने किसानों का ध्यान आकर्षित कराया है। क्षेत्र के बरसवा गाव में अयोजित आदर्श कृषक क्लब के समारोह में जिलाउद्यान अधिकारी जेपी शर्मा ने कहा कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में अधिक फायदा है।

क्लब के संयोजक रामगोपाल सिंह के आवास पर आयोजित भव्य समारोह में विशेषज्ञों ने तमाम योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी दी उन्होंने बताया कि गंगा के किनारे के गावों में जहाँ सिंचाई के लिए पानी की समस्या रहती है। वहाँ के किसान कम पानी वाली फसल ले सकते हैं। यहाँ नदी नई तकनीकी की टपक सिंचाई का प्रयोग किसान करें। इस योजना में एक एकड़

की भूमि के लिए तीस हजार रुपये लागत का प्रोजेक्ट लगता है इसमें उद्यान विभाग सामान्य कृषकों 60 फसदी दलित वर्ग के कृषकों को 75 फसदी अनुदान देता है। इस प्रकार से एक एकड़ के लिए बमुश्किल 5 से 6 हजार रुपये की लागत से प्रोजेक्ट तैयार हो जायेगा। इसी प्रकार ग्रीन हाउस बनाकर उसमें सब्जी आदि की पैदावार बढ़ायी जा सकती है। इसमें सरकार 50 फसदी का अनुदान देती है। इसके अलावा बागवानी के लिए सरकार से निःशुल्क पौधे दिए जाते हैं। और उनकी रखरखाव के लिए किसानों को धन भी दिया जाता है। समारोह को इन्दिरा गांधी कृषक एवं इद्यमिता विकास संस्थान के निदेशक डा. विनोद कुमार त्रयसवाल एवं डा.सन्तलाल, डा. आर पी मौर्या और डा. सुनील कुमार ने भी सम्बोधित किया। समारोह में क्षेत्र के किसान दीपक कुमार निषाद, रामनरेश पाण्डेय, जगदीश नारायण मौर्या और रामसुमेर सिंह आदि किसान उपस्थित रहे।

Clipping -23

This Clipping -23 dated 2nd October 2014 is for the farmers to do more production in less input by the help of technology. In a function inaugurated in Barsova village district officers says that farming with the help of technology will be beneficial and in the end mentioned the name of peoples presented in function.

कार्यकर्त्रियों को दिया प्रशिक्षण

Publish Date:Thu, 02 Oct 2014 01:03 AM (IST) | Updated Date:Thu, 02 Oct 2014 01:03 AM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को सात दिवसीय पुनर्श्रुया प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में राही, जगतपुर, सरेनी, शिवगढ़, छतोह, महाराजगंज तथा नगर क्षेत्र की कार्यकर्त्रियों को शामिल किया गया। प्रशिक्षण के दौरान गर्भवती महिलाओं व बच्चों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, सफाई, टीकाकरण आदि के बारे में प्रशिक्षकों ने जानकारी दी।

ग्राम्य विकास संस्थान के प्रशिक्षण प्रभारी जय नारायन श्रीवास्तव ने महिलाओं के सशक्तीकरण के बारे में बिंदुवार बताया। कहा कि ग्रामीण महिलाएं समूह से जुड़कर अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी। मुख्य सेविका

अरुणापाल ने नवजात शिशुओं की बाल वृद्धि के बारे में जानकारी दी। बालरोग विशेषज्ञ डा. निशीकांत ने बच्चों में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। कहा कि जन्म के बाद मां का दूध बच्चे के लिए आवश्यक है। मां को अपने बच्चे का दूध ही पिलाना चाहिए। प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी संतोष गुप्ता ने कहा कि घर के आस पास पड़ी खाली जमीन पर हर सब्जी उगानी चाहिए। इससे सब्जी पर होने वाला खर्च कम होता है और जाती शूद्ध सब्जियां खाने को मिलती है।

Clipping-24

The another clipping-24 of 2nd October 2014 predict the news of ‘anganbadi’ women regarding the training given to them for the betterment of women society and how they can start their own small business at home.

स्वच्छता को आगे आएं आवाम

Publish Date: Sat, 04 Oct 2014 06:11 PM (IST) | Updated Date: Sat, 04 Oct 2014 06:11 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता :

राजीव गंाधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान रायबरेली के स्वयं सेवकों ने शनिवार को विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को सफाई अभियान के प्रति प्रेरित किया। संस्थान के छात्र - छात्राओं ने सफाई के प्रति आम लोगों को जागरुक करने का संकल्प लिया।

उत्साह के साथ पांच स्कूलों में यह सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता हेतु ली जाने वाली शपथ के साथ हुई। संस्थान के कार्यकारी निदेशक डा. एसके मिश्र ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई और कहा कि उन्हें

आगे बढ़-चढ़कर सफाई अभियान में योगदान करनी चाहिए ताकि देश की दुनिया भर में एक अलग पहचान बन सके। उन्होंने कहा कि राजीव गंाधी संस्थान रायबरेली के छात्र-छात्राएं ग्रामीण इलाकों में स्थित कुछ प्राथमिक विद्यालयों को नियमित रूप से स्वच्छता बनाये रखने के लिए विद्यालय प्रशासन की मदद करें।

Clipping-25

The other clipping-25 is of 4th October 2014 inform about the work done on the Swachta Abhiyan by Rajiv Gandhi Petroleum Institute in District in which many of the students persuade to common peoples about the swachchhta abhiyan so that our society and country will be clean hygienic. On this occasion working director pledged to all peoples to cooperate in this mission so that our country will make a unique identity in the world.

सियासी भंवर में 434 करोड़ का सीवर प्रोजेक्ट

Publish Date: Sun, 05 Oct 2014 06:51 PM (IST) | Updated Date: Sun, 05 Oct 2014 06:51 PM (IST)



विमल पाण्डेय, रायबरेली

देश भर में अच्छे दिनों की आहट का नारा भले ही गूंज रहा हो पर वीवीआईपी जिले रायबरेली में सब कुछ बुझे चिराग जैसा ही है। सोनिया के संसदीय क्षेत्र में जनता ने पांच सालों तक मुंगेरिलाल के हसीन सपने की तरह जिले के विकास का अक्स देखा पर हासिल कुछ नहीं हुआ। अब तो सोनिया गांधी के लिए भी शहर की 434 करोड़ की सीवर लाइन योजना सपने जैसी हो गई है। योजना सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह गई। फिलहाल प्रदेश सरकार के पाले में योजना दम भर रही है कि शायद कार्याकल्प हो जाए। चुनाव के ठीक पहले भी रायबरेली में इस योजना को लेकर काफी उठापटक रही है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा।

रायबरेली में सीवर लाइन की स्थापना का सपना दशकों पुराना है। सबसे पहले वर्ष 2008 में सीवर लाइन बनाने के लिए संग्राम अध्यक्ष सोनिया गांधी से शहरवासी अपनी मांगों को लेकर मिले थे। पट्टी पर योजना चल चुकी थी, लेकिन इसका प्रस्ताव तैयार कराने में ही पांच वर्ष बीत गए। उसके बाद नगर पालिका ने सीवर लाइन का प्रोजेक्ट तैयार कर शासन को भेजा।

Clipping-26

The Clipping-26 of 5th October 2014 is reporting that how a development scheme is complicating in the politics from many of the years. The political parties are playing with the development of district just opposing to the decision of peoples to select their representative.

विकास कार्यों की परखी हकीकत

Publish Date: Wed, 08 Oct 2014 06:40 PM (IST) | Updated Date: Wed, 08 Oct 2014 06:40 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : कस्तूरबा विद्यालय में चहार दीवारी बनाने के दिये निर्देश। जिलाधिकारी महेन्द्र कुमार ने तहसील सलोन के निरीक्षण के दौरान विभिन्न पटलों जन सुविधा केन्द्र, माल खाना, मतदाता पंजीकरण [Jagran News](#) मुभाग, वरासत के मामलों सहित सभी पटलों का निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील में वरासत सम्बन्धी मामलों को त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि तहसीलदार सोहन लाल एवं उपजिलाधिकारी से कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी। उन्होंने सभी कार्य को दीपावली तक पूरा करने के बाद पुनः निरीक्षण करने का आदेश दिया और कहा कि दिये गये बिंदुओं पर संज्ञान लेते हुए तत्काल

कार्यवाही की जाय। तहसील निरीक्षण के उपरान्त जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय सूची का भी निरीक्षण किया और विद्यालय की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने के साथ ही

Clipping-27

The Clipping-27 of Newspaper Wednesday 8th October shows the focus of DM on the construction work of Kastoorba Gandhi Vidhalya list and says to take it seriously with other officers. In the visit he checks the development work on the scheme.

पशुओं का होगा टीकाकरण

Publish Date:Wed, 08 Oct 2014 06:38 PM (IST) | Updated Date:Wed, 08 Oct 2014 06:38 PM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : जिले में पशुओं के संरक्षण के लिए एक बृहद रूप से टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस क्रम में जिले के 18 विकास खण्डों के अन्तर्गत 07 लाख 44 हजार पशुओं को चिह्नित किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि अभियान में किसी प्रकार की कोताही न की जानी चाहिए। जिन ब्लाक क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही की तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

यह अभियान विशेषकर खुरपका एवं मुंहपका बीमारियों के लिए ही आयोजित किया जा रहा है। जिलाधिकारी महेन्द्र कुमार ने जनपद के 18 विकास खण्डों में पशुओं की विभिन्न बीमारियों से

बचाने के लिए शासन के निर्देशानुसार 10 अक्टूबर 2014 से 15 अक्टूबर 2014 तक अभियान चलाकर टीकाकरण किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने ने कहा कि 836 ग्राम पंचायतों के 1535 राजस्व ग्रामों में 07 लाख 44 हजार पशुओं में टीकाकरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित क्षेत्रीय विधायकों/ब्लाक प्रमुखों ने नागरिकों/पशुपालकों से अपील करते हुए कहा कि सभी पशुपालक अपने-अपने पशुओं को खुरपका एवं मुंहपका के रोगों में नियन्त्रण करने के लिए पशुपालन विभाग रायबरेली द्वारा चलाए जाने वाले इस विशेष अभियान का लाभ उठाएं और ज्यादा से

Clipping-28

The another clipping-28 of 8th October 2014 inform about the vaccination for the animals so that no animals in the district will be infected by any disease with this a date 10 to 15th October is also provided and strictly ordered to all officers to work properly. The target of 7 lakhs 44 thousand is to be taken for five days.

औद्योगिक क्षेत्र के लिए मागी जमीन

Publish Date:Thu, 09 Oct 2014 05:47 PM (IST) | Updated Date:Thu, 09 Oct 2014 05:47 PM (IST)

लालगंज संवाद सहयोगी : कस्बे से जुड़े चादा गाव मे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से किसानों की जमीन लेने को यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर वार्ता की।

बैठक में मौजूद यूपीएसआईडीसी के उप प्रबंधक अजय दीपची व सहायक प्रबन्धक मंशू कटियार ने ग्रामीणों को औद्योगिक क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों से अपनी जमीनें देने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए ग्राम सभा की 52 एकड़ जमीन मिल रही है। उस जमीन से सटी 124 किसानों की लगभग 38 एकड़ जमीन की और आवश्यकता है। अधिकारियों ने कहा कि वह किसानों के

साथ आपसी सहमति को लेकर वार्ता करने आये हैं। जो किसान अपनी भूमि यूपीएसआईडीसी को देगा उसे भूमि

Clipping-29

The clipping-29 of 9th October 2014 Newspaper predicts that officers of UPSIDC requested to peoples of a village Chanda to give their land so that the area will become more developed and industrialized. UPSIDC officers stated that they have 52 acres of land but they want 38 acres more land to provide more service.

फतेहपुर और रायबरेली को जोड़ेगा पीपा पुल

Publish Date: Sat, 11 Oct 2014 06:44 PM (IST) | Updated Date: Sat, 11 Oct 2014 06:44 PM (IST)



ऊंचाहार, संवाद सहयोगी: रायबरेली व फतेहपुर जनपद को जोड़ने वाला स्वरौली गंगाघाट पर पीपा के पुल का निर्माण शुरू हो गया है। पंद्रह दिन में यह पुल बन कर तैयार हो जाएगा। ऊंचाहार व फतेहपुर जनपद के खागा तहसील के लोगों की उम्मीदों का यह पुल बीते वर्ष से बनना शुरू हुआ है। पिछले फरवरी में पुल बन कर तैयार हुआ था। इस बार अक्टूबर में पुल बन कर तैयार हो जाएगा।

निर्माण संस्था लोक निर्माण विभाग खंड द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है। तकरीबन 65 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस पुल पर काम तेजी के साथ शुरू हो गया है। तीन दिनों से गंगा नदी में पुल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस पुल के बन जाने से रायबरेली व फतेहपुर जनपद के लोगों के लिए कई दृष्टिकोण से लाभदायक है। इस पुल के द्वारा दोनों जनपदों में बड़ी संख्या विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों का आवागमन बढ़ जाता है। यही नहीं पुल के निर्माण से दोनों जिलों की दूरियां कम हो जाती है। आवागमन के लिए कोई साधन व सड़क मार्ग न होने के कारण लोग अपनों से भी नहीं मिल पाते हैं। सूत्रों की माने तो इस माह के अंतिम सप्ताह में पुल बन कर तैयार हो जाएगा। इसपर आवागमन एक नवंबर से शुरू होगा।

Clipping-30

The clipping-30 of 11th Octobers 2014 Newspaper informs with a color photographs that a bridge is going to join Raebareli district with the Fatehpur by a *Peepa* bridge so that the people of both are can use it for business or personal purpose. It also stated that the Pull will be ready in next 15 days.

14 को मेला

Publish Date: Sat, 11 Oct 2014 06:54 PM (IST) | Updated Date: Sat, 11 Oct 2014 06:54 PM (IST)

ऊंचाहार: स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 अक्टूबर को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। क्षेत्र के गाँव कोटरा बहादुरगंज में लगने वाले इस मेले में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। ऊंचाहार सी एचसी प्रभारी डा आरबी सिंह यादव ने बताया कि स्वास्थ्य मेले में ग्रामीणों का परीक्षण के साथ साथ उन्हें परामर्श व दवाएं भी दी जाएंगी। इसमें डाक्टरों की दो टीमें काम करेंगी।

Clipping-31

The clipping-31 of Saturday 11th October 2014 informed about the upcoming health fair in the Unchahar area in which Many Specialist will be presented to cater the rural people and provide them medicine with the

घर में लीजिए मुर्गी से 'सोने' का अंडा

Publish Date: Mon, 13 Oct 2014 06:55 PM (IST) | Updated Date: Mon, 13 Oct 2014 06:55 PM (IST)

केशव अग्निहोत्री, रायबरेली: गांव के गरीब किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि की योजना कल्पना रच रही सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए मुर्गी पालन की योजना लागू की है। हालांकि प्रचार प्रसार के अभाव में दो साल से चल रही योजना को अभी तक लक्ष्य से काफी दूर है। दलित बीपीएल परिवारों के लिए ग्राम बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म योजना नाम से चलाई गई यह योजना तो पिछले साल प्रचार प्रसार के अभाव में धड़ाम रही है। इस साल तीन सौ परिवारों को लाभ देने के लक्ष्य रखा गया है।

केंद्र व प्रदेश सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। सरकारी विभाग भी उनके प्रचार प्रसार का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनमें प्रदेश सरकार की बीपीएल

परिवारों के लिए मुर्गी पालन योजना है। जिसमें अति गरीब परिवार को तीन हजार मूल्य के मुर्गी के चूजे दिए जाते हैं। जिन्हें अपने घर के पिछवाड़े पालकर एसी बीपीएल परिवार अपनी दो जून की रोटी का आराम से इंतजाम कर सकते हैं।

Clipping-32

The clipping-32 of 13th October 2014 reports the scheme of poultry farming for backward BPL card holder by the government is discussed in which government will provide a poultry worth rupees 3000 to the poor backward peoples so that they can nourished them and use it for their survivals.

बच्चों को मिली यूनीफार्म

Publish Date: Tue, 14 Oct 2014 08:22 PM (IST) | Updated Date: Tue, 14 Oct 2014 08:22 PM (IST)

Jaqran News



रायबरेली, जागरण संवाददाता : जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने मंगलवार को किला बाजार स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों को निःशुल्क यूनीफार्म वितरित किया। जिलाधिकारी ने बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि अभिभावकों को भी बालिकाओं की शिक्षा पर खासकर ध्यान देना चाहिए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इलियास ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा पर एक के बाद एक शासन स्तर से नई-नई योजनाएं आ रही हैं इन योजनाओं के

क्रियान्वयन में खासकर ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यालय में 161 छात्राओं को ड्रेसें बांटी गईं। इस मौके पर बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप चौधरी, नगर शिक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कनौजिया, साक्षरता प्रभारी दिग्विजय सिंह आदि रहे।

Clipping-33

The clipping-33 of 14th October predicts that on Tuesday DM distributed school uniforms to poor ones. It is important to educate the girls for the betterment of society. The news also mentioned the host of the occasion chairmen of nagar palika who informs that many schemes for girls education is on the way which play an important role for their better education with this they have distributed 161 new school uniforms to the girls in the schools.

गरीबों को मिलेगा मकान

Publish Date:Thu, 16 Oct 2014 09:21 PM (IST) | Updated Date:Thu, 16 Oct 2014 09:21 PM (IST)

ऊंचाहार, संवादसहयोगी: क्षेत्र में 25 फीसदी से अधिक दलित आबादी वाले गावों में गरीब दलितों को लोहिया आवास दिया जाएगा। इन आवासों के लिए समाज कल्याण विभाग धन देगा। इसके लिए ऊंचाहार के 49 गावों में सर्वेक्षण कार्य शुरू होने वाला है।

क्षेत्र के जिन गावों में दलितों की आबादी 25 फ सदी से ऊपर है। उनमें ऐसे गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा, जिनका नाम गरीब होने के बावजूद बीपीएल सूची में नहीं है। उन परिवारों को दो लाख 75 हजार की लागत से बनने वाला लोहिया आवास का लाभ दिया जाएगा। अभी तक लोहिया आवास का लाभ केवल लोहिया समग्र ग्राम में दिया जाता रहा है। 25 फ सदी से अधिक

दलित आबादी के गावों का चयन समाज कल्याण विभाग ने कर लिया है। इसकी सूची ब्लाक मुख्यालय को भेजी गई है। ऊंचाहार में 25 फ सदी से अधिक दलित आबादी के गावों में नेवादा, निरंजन पुर, सलीम पुर भैरों, कोटिया चित्रा, रामचंदरपुर, कन्दरवा, बिकई, मदारीगंज जमालपुर माफ, पट्टी रहस कैथवल, मतरौली, सवैया धनी, किशुन दासपुर, जब्बारीपुर, धमधमा, बहेरवा, बेहरामऊ, गंगश्री, चतुरपुर, नजनपुर, मिजरा इनायतुल्ला पुर, गंधपी, गोकना, पूरे ननकू, सरबहदा, पूरे फूलचन्द्र, सावापुर नेवादा, मुरारमऊ, पचखरा, लाल, चन्द्रपुर, इच्छानिहा, शूरकुरल्ला पुर, कमोली, गंगौली, बाहरपुर, मोखरा, निगोहा,

Clipping-34

The clipping-34 dated 16th October 2014 informs about the house that government will give to the village have more than 25.0% of poor scheduled caste peoples in the Unchahar area. The residents will be given to them by the social welfare department of government and for that 25.0% of poor peoples are selected by the department to provide them house. The lists of village selected are also mentioned in the clipping.

अनुसूचित जाति बाहुल्य गावों का होगा विकास

Publish Date:Sun, 19 Oct 2014 08:46 PM (IST) | Updated Date:Sun, 19 Oct 2014 08:46 PM (IST)

महाराजगंज, संवाद सहयोगी : प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के समग्र विकास के लिए अनुसूचित जाति सब प्लान के अंतर्गत योजना बनाकर विकास का खाका तैयार किया है। ब्लाक में योजना के संचालन की जिम्मेदारी एडीओ शिवदास निर्मल को सौंपी गई है। शासन के प्रमुख सचिव सुनील कुमार के मार्च 2014 को जारी पत्रांक संख्या 664 में कहा गया है कि ऐसे गांवों में जिनमें 25 फीसदी या उनसे अधिक आवादी है। वहा पर इस योजना को लागू किया जायेगा।

बनेंगी सीसी रोड

समाज कल्याण की कल्याण नियोजन के अंतर्गत चयनित ग्रामों में निकट मुख्य मार्ग तक पहुंच के लिए संपर्क मार्ग का निर्माण होगा। वहीं स्वस्थ वातावरण के लिए सफाई व्यवस्था सुनिश्चित रखने के उद्देश्य से सीसी मार्गों के निर्माण की भी व्यवस्था है।

जगमगायेगी सोलर लाइटें

Clipping-35

The clipping-35 of 19th October 2014 informs that state government is going to develop Scheduled caste villages and for that a plan is made also. The schemes are valid for those villages in which more than 25.0% of population is of SC. The scheme will be under the social welfare department which develop the villages and make the CC road also.

बजट मिला लेकिन काम शुरू नहीं

Publish Date: Tue, 21 Oct 2014 01:01 AM (IST) | Updated Date: Tue, 21 Oct 2014 01:01 AM (IST)



महाराजगंज संवाद सहयोगी: लोहिया गाव सारीपुर का सीडीओ अनूप श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गाव मे मिली खमियों पर एई एसपी पांडेय को को जमकर फटकार लगाई। सीसी रोड का बजट आ जाने के बाद भी कार्य शुरू न होने पर सीडीओ नाराज दिखे।

अमावा विकास खंड के सारीपुर गांव में शाम 5 बजे सीडीओ अनूप श्रीवास्तव व बीडीओ कमलेश सोनी की गाड़ी अचानक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद ग्राम विकास अधिकारी, एई एसपी पांडेय

सहित अन्य कर्मचारियों को मौके पर बुलाया। सीडीओ सीसी रोड का निर्माण प्रारम्भ न मिला तो एई को जम कर फटकार लगाई।

Clipping-36

The clipping-36 of 21st October 2014 predict that how CDO of area go to check the village development but they found there are lots of rough edges in the villages and for that they lined up the village development officers.

बैटरी चालित स्प्रे मशीन बन सकती पसंद

Publish Date: Tue, 28 Oct 2014 06:35 PM (IST) | Updated Date: Tue, 28 Oct 2014 06:35 PM (IST)

Share Like 0 0 Tweet 0

A⁻ A⁺



रायबरेली, जागरण संवाददाता : जिला औद्योगिक मिशन में शहर के एफजी कालेज मैदान पर किसानों के लिए कृषि प्रदर्शनी लगाई गई। उर्वरक, बीज, कृषियंत्र, पशुपालन आदि के स्टाल के लगाए गए।

किसान गोष्ठी में बैटरी चालित स्प्रे मशीन आई थी। 17 लीटर दवा का घोल एक बार में भरा जा सकता है। एक बार फल बैटरी चार्ज होने पर मशीन लगातार 150 लीटर दवा का छिड़काव कर सकती है। कीमत मात्र तीन हजार है। पीठ पर

Clipping-37

The clipping-37 of 28th October 2014 informs that in the city an exhibition was organized to inform farmers about new technological machineries that can be helpful. With a color photograph it is mentioned that a battery spray machine will become beneficial for the agriculture purposes.

मरम्मत के छह माह बाद उखड़ीं सड़कें

Publish Date: Mon, 09 Feb 2015 08:41 PM (IST) | Updated Date: Mon, 09 Feb 2015 08:41 PM (IST)



केस - एक

बड़वल बार्डर मुराई पुरवा मजरे बेडारु तक सात किलो मीटर सड़क का निर्माण 70 लाख की लागत से रिपेयर कराया गया था। लेकिन रिपेयरिंग के छह माह बाद सड़क उखड़ गई।

केस-एक

पिंडौली से मचौटी के पुल तक संपर्क चार किमी तक बनाया गया, लेकिन छह माह बीतते ही पूरी सड़क गड्डों में तब्दील हो गई। इस पर विभागीय अफसरों का ध्यान नहीं गया है।

केस-तीन

गोबरे का पुरवा से दहिगवां तक दो किमी सड़क बनवाई गई थी। इस मार्ग से गिट्टी पूरी तरह उखड़ने लगी है। ग्राम सभा बैठती में संपर्क मार्ग तक सड़क उखड़ गई है। इसके बाद काम बंद करवा दिया।

शिवगढ़, संवाद सूत्र : ये तो केवल चंद नमूने हैं। अगर ब्लॉक क्षेत्र की सड़कों की हकीकत देखनी है तो यहां जरूर आइए। क्योंकि कमीशनबाजी के चलते बनने वाली सड़कें एक साल के अंदर की दम तोड़ चुकी हैं। विकास क्षेत्र एक दर्जन से अधिक ऐसी सड़कें ऐसी हैं जो गड्डों में तब्दील हो चुकी हैं। ग्रामीण कमल किशोर रावत, देवनारायण सिंह, ननकरू का कहना है कि विकास क्षेत्र में पीडब्लूडी विभाग द्वारा अक्टूबर नवंबर 2014 में संपर्क मार्गों की रिपेयरिंग कराई गई थी। रिपेयरिंग के कुछ माह बाद ही सड़कें उखड़ने लगी हैं।

Clipping-38

The clipping-38 shows the reality of the work done by the government. This news is indicating to all government officers that how irresponsible they are? At the same time this news predicting that this is just an example, in the area there are many other roads in such conditions present on which no one is there to take an action.

विकास की हकीकत परखी

Publish Date: Tue, 10 Feb 2015 07:24 PM (IST) | Updated Date: Tue, 10 Feb 2015 07:24 PM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : प्रमुख सचिव का काफिला अपरान्ह शहर हरचंदपुर के बाला गांव पहुंचा। गांव में चल रही विकास कार्यों की हकीकत देखी। गांव में बन रहे लोहिया आवास देखे, वहां चार आवासों में अंदर प्लास्टर नहीं था। कारण पूछा तो बताया गया कि लोहिया आवास की निर्धारित धनराशि खर्च हो गई है। अब लाभार्थी को ही स्वयं प्लास्टर कराना होगा।

लोहिया आवास देखने के बाद एक शौचालय व सीसी रोड भी देखी। गांव में चल रहे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन को देखा। प्रमुख सचिव ने कहा कि किसान धीरे धीरे रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम करें। इसकी जगह कंपोस्ट, वर्मी, जैविक खाद का खुद निर्माण कर प्रयोग करें। इससे खेतों की मृदा शक्ति व उत्पादन में वृद्धि होगी।

कुपोषण टीकाकरण की ली जानकारी

प्रमुख सचिव ने अंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर एएनएम का रजिस्टर देखा। कहा कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों का समय से टीकाकरण किया जाए, आशा महिलाओं के प्रसव पीएचसी में ही ले जाकर कराएं। कुपोषित बच्चों को आवश्यक होने पर जिला अस्पताल में सुधार के लिए भर्ती कराएं जाएं।

Clipping-39

The clipping-39 of Newspaper dated 10th February 2015 is predicting the information regarding the round of major secretary in the Bala village of Harchandpur city to check the reality of development work on Lohiya Awaas Yojna as well as toilet and CC road. At the same time Major Secretary gives their suggestions to work better for development. With this he also goes to Aganwadi kendra to check the ANM register and messages to all regarding the vaccination for the pregnant women and children. This news clipping informing as well as showing the seriousness of Major secretary for the development and health of Area.

लोहिया गांवों के विकास में रोड़ा

Publish Date: Tue, 10 Feb 2015 06:53 PM (IST) | Updated Date: Tue, 10 Feb 2015 06:53 PM (IST)



सरेनी, संवादसूत्र: लोहिया ग्राम पंचायत सब्जी बबुरा विकास के कोसों दूर दिख रहा है। विकास की हर तस्वीर यहां धुंधली है। कहीं खड़जे उखड़े हैं तो कहीं नालिया बजबजा रही हैं। 40 फ सदी शौचालय अधूरे हैं। अपात्रों को लोहिया आवास दे दिए गए हैं। जबकि पात्र लाभार्थी आज भी खुले आसमान के नीचे अथवा झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की ओर से की गई अवैध धन उगाही व मनमाने रवैये पर नाराजगी जताई है।

ज्ञात हो कि ब्लाक मुख्यालय से मात्र 5 किमी की दूरी पर सरेनी-सेमरी मार्ग में सब्जी बबुरा ग्राम स्थित है। गाव में 22 लाख 80 हजार रुपये की लागत से 19 लोहिया आवास बनवाये गये तथा 140 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। गाव में 197 बीपीएल

कार्ड धारक, 61 अन्त्योदय कार्ड धारक व 271 जाब कार्ड श्रमिक हैं। इनमें से सिर्फ 05 श्रमिकों को ही साल में सौ-सौ दिन का काम दिया गया है। श्री प्रसाद के अनुसार गाव में 80 वृद्धों, 4 विधवाओं तथा 4 विकलांगों को पेंशन मिल रही है समाजवादी पेंशन के लिये 47 की सूची भेजी गयी है।

Clipping-40

The clipping-40 of 10th February 2015 informed that about the maltreatment of village head on the village peoples as well as the problems facing by them. This clipping is informing the peoples, officers and government about the unfairness on the poor peoples of the area so that any action may occurs to provide them relief.

शौचालयों की जांच अधूरी

Publish Date: Tue, 10 Feb 2015 06:45 PM (IST) | Updated Date: Tue, 10 Feb 2015 06:45 PM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : डीएम ने ग्रामीणों की शिकायत पर खीरों विकास क्षेत्र के बकुलिहा गांव में 7.26 लाख रुपए की लागत से बने शौचालयों की जांच के आदेश पिछले साल नवंबर में दिए थे। लेकिन अब तक जांच के बारे में कोई प्रगति संज्ञान में नहीं है। जहां शौचालय बन भी गए हैं, उनकी गुणवत्ता पर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं।

बकुलिहा के राकेश सिंह सहित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि पिछले वर्ष जिला स्तर से उक्त गांव में शौचालय बनाने के नाम पर सात लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। Jagran News शिकायत

अधिकारी ने मिल कर जालसाजी व हेराफेरी कर धनराशि हड़प कर ली है। जो शौचालय बनाए भी गए वह प्रयोग लायक नहीं हैं। गांव में जाकर इस बात की पुष्टि की जा सकती है। पूर्व में डीपीआरओ से कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

कई ब्लाकों ऐसा ही हाल

बकुलिहा गांव तो बानगी है कमोवेश ऐसे हालात जिले के कई गांवों के हैं। ग्रामीणों के सक्रिय होने पर इक्का-दुक्का मामलों की जांच करा दी जाती है। ऐसे में केवल उन्हीं मामलों की जांच होती है जिनके बारे में हो हल्ला मचता है बाकी सभी मामले ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं।

Clipping-41

The clipping-41 of 10th February 2015 predict that no action is taken by the complaint given to the DM from Bakuliha Villager on the toilet constructed of Rs7.26lacs in the area. The construction of toilets is completed but villagers are pointing on the quality of material used however no such action is taken on it after the complaint. This news clipping is reminding how we can use our right to speech and expression for the betterment of the society so that all will know about the role of DM and other officers on the development work.

अधूरे रहे निर्माण तो गिरेगी गाज

Publish Date: Tue, 10 Feb 2015 06:21 PM (IST) | Updated Date: Tue, 10 Feb 2015 06:21 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : शासन के प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अरुण सिंघल ने दौरे के दूसरे दिन कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। दो घंटे चली बैठक में कब्रिस्तान की चहर दीवारी अन्य सरकारी निर्माणों पर ज्यादा जोर दिया। जिले में 2012 से चल रहे निर्माण कार्य अधूरे होने पर कहा कि लंबित कार्य मार्च तक पूरे कर लिए जाए।

मंगलवार को प्रमुख सचिव अरुण सिंघल ने पेयजल, आरसीसी सड़क, चहरदीवारी,

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि की बिंदुवार प्रगति जानी। जल निगम की सुस्त चाल पर नाराजगी व्यक्त की, कहा कि गर्मी शुरू होने के पहले पेयजल योजनाओं, हैंडपंप स्थापना, रिबोर आदि के काम पूरे कर लिए जाएं। इसके अलावा लोहिया समग्र ग्राम के कार्यों पर चर्चा की, इंदिरा आवास, लोहिया आवास, शौचालय निर्माण की प्रगति पूछी। खास बात यह है कि जिले में सरकारी निर्माण काम कराने की जिम्मेदारी सीएनडीएस को दी गई है। इसकी चाल सुस्त है। प्रमुख सचिव ने कहा वित्तीय वर्ष में मिले विकास के धन का पूरा उपयोग कर लिया जाय।

Clipping-42

The clipping-42 of 10th February 2015 envisage regarding the round of Administration in the area and informing about the meeting taken with the other officers taken by him. Through this news peoples will better know that when will be the government erections will be completed. On the long time pending work the chief Secretary says that it will be completed soon in March. He also checks the PM Grameen Yojna as well as seriously gives the instruction on the Water facilities so that peoples will not have face problems in the summer.

बनने के बाद ही उखड़ जाती सड़क

Publish Date:Wed, 18 Feb 2015 01:07 AM (IST) | Updated Date:Wed, 18 Feb 2015 01:07 AM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : शहर का हृदय स्थल कहे जाने वाले कलेक्ट्रेट के ठीक सामने ओवर ब्रिज बना है। इस पर बनाई जाने वाली तारकोल की सड़क बनने के दो माह ही सिकुड़ जाती है। सड़क पर गह्वे बन जाते हैं। इससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

करीब दो दशक पहले जिले की संसद रही शीला कौल के कार्यकाल में शहर का पहला ओवर ब्रिज बना था। पुल निर्माण की जिम्मेदारी यूपी राज्यसेतु निगम ने बनाई थी। पुल बनने के साथ ही पुल पर बनाई जाने वाली सड़क निर्माण के कुछ दिन बाद यह सिकुड़ जाती है। सड़क की पूरी लेयर ही जगह जगह इकट्ठा हो जाती है। इस पर बाइक व साइकिल से गुजरने पर गाड़ी उछलने व फिसलने की दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

Clipping-43

The clipping-43 of 18th February 2015 informing about the critical condition of bridge because of which peoples are facing many problems. This news is to inform and show problems to the government to reconstruct the bridge so that accident will not happen as well as informing to the peoples to ride very carefully on the bridge for their safety.

केसीसी बनाने में आगे, कामधेनु योजना में पीछे

Publish Date:Wed, 25 Feb 2015 01:13 AM (IST) | Updated Date:Wed, 25 Feb 2015 01:13 AM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता :

प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाली दो योजनाओं में एक केसीसी बनाकर देने में सरकारी बैंक आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी कामधेनु व मिनी कामधेनु योजना में आवेदकों को ऋण देने में आनाकानी की जा रही है।

60 हजार से अधिक केसीसी बने

चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार ने जिले को 56672 किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया था। इसके सापेक्ष अब तक 60891 केसीसी किसानों को जारी करने का बैंक दावा कर रहे हैं। यह लक्ष्य से करीब सात प्रतिशत अधिक है। सरकारी बैंकों ने

51487 व सहकारी बैंक ने 9404 केसीसी बनाकर जारी किए हैं।

कामधेनु योजना को नहंी दे रहे ऋण : चालू वित्तीय वर्ष में शासन से छह काम धेनु व 26 मिनी कामधेनु डेयरी खोलने का लक्ष्य मिला था। चार कामधेनु व 24 मिनी कामधेनु डेयरी खोलने के लिए चयन हुआ था। सभी फाइलें बैंकों को भेजी गईं। लेकिन बैंक सवा करोड़ या 52 लाख का ऋण बिना मजबूत गारंटी के नहंी देना चाहते हैं। आवेदकों से लोन के बराबर अचल संपत्ति की गारंटी मांगी जा रही है। कौन आदमी है जो दूसरे के लिए अपनी एक करोड़ की संपत्ति बैंक में गिरवी रखेगा। यही वजह है कि जिले में अभी एक दो को छोड़कर किसी आवेदक को ऋण नहीं मिला पा रहा है।

सीडीओ ने शासन को लिखा

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. केके चौधरी ने समस्या से सीडीओ को अवगत कराया। सीडीओ ने लीड बैंक अधिकारी को बुलाकर वार्ता भी की। नतीजा न निकलता देख सीडीओ अनूप कुमार श्रीवास्तव ने प्रमुख सचिव को पत्र लिख कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया है।

Clipping-44

The clipping-44 of 25th February 2015 depicts the progress of government bank schemes. Through this news peoples are informed regarding the work on schemes in government banking as well as banks are promoting their schemes through the newspaper.

सोनिया के घर में धुंधला हुआ विकास का अक्स

Publish Date: Mon, 23 Feb 2015 07:28 PM (IST) | Updated Date: Mon, 23 Feb 2015 07:28 PM (IST)



विमल पाण्डेय, रायबरेली : सोनिया के गढ़ में सियासत की बेल परवान चढ़ रही है। इस बार मुद्दा है विकास की धुरी में रायबरेली की तस्वीर। ऐसे में यहां हर सामान्य मुद्दे भी गौण होते जा रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर सोनिया गांधी के प्रयासों पर पानी फेरने का काम जहां सरकारी तंत्र कर ही रहा है वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार की अलग-अलग फांस विकास के लगने वाले पंखों को काट रही है। पिछले वर्ष संसदीय चुनाव के बाद से रायबरेली में विकास की कई योजनाओं को पंख नहीं लग पाए हैं। उम्मीदों की किरण कब जागेगी ? यह सवाल यहां की तीस लाख जनता टकटकी निगाहों के साथ आपस में ही कर रही है।

Jagran N

यूं तो हाईप्रोफाइल रायबरेली में योजनाओं की कमी नहीं रही है। संप्रग सरकार के दौरान यहां उन योजनाओं का ताना-बाना बुना गया जिसके लिए देश के बड़े-बड़े शहर तरसते रहे हैं। मसलन योजनाएं लाई गार्ड और रायबरेली के लोगों को न केवल सपने दिखाए गए बल्कि उनके उनको पूरा कराने का विश्वास भी जताया गया। लेकिन बाद में सियासत की बेल इस कदर चढ़ी कि सपने आखिर सपने बनकर रह गए।

Clipping-45

The clipping-45 of 23rd February 2015 showing that how the development schemes in district are suffering between the state and central government. At the same time it puts a question mark on the hope of the 30lacs peoples who thought for the development of the District.

पर्यावरण का ख्याल कर विकास हो सके

Jagran News

Publish Date:Wed, 25 Feb 2015 01:17 AM (IST) | Updated Date:Wed, 25 Feb 2015 01:17 AM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। यहां देश के विद्वानों और शोधार्थियों बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। संगोष्ठी में शोध पत्र पढ़े जाएंगे और पर्यावरण प्रदूषण पर विचार किया जाएगा। संगोष्ठी का विषय 'आधुनिक समाज पर पर्यावरणीय प्रभाव' रखा गया है।

संगोष्ठी के उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि महर्षि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रो. एचके सिंह और डॉ चंद्र प्रकाश मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ कालेज की छात्राओं ने सरस्वती वंदना के साथ किया। इस मौके पर कालेज की प्राचार्या डॉ सुषमा देवी ने कहा कि पर्यावरण हमारे जन जीवन से जुड़ा है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या प्रतिदिन गहराती जा रही है। संगोष्ठी के आयोजन सचिव डॉ अखिलेश कुमार ने दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में बताया कि पर्यावरण असंतुलन के विषय में जानकारी दी। अध्यक्ष प्रो. एचके सिंह ने कहा पर्यावरण का ख्याल करके विकास की रुपरेखा तय होनी चाहिए। इस मौके पर डॉ चंद्र प्रकाश, डॉ प्रगति अवस्थी, डॉ आरपी वर्मा, शालिनी कनौजिया, शिखा मौर्या, डॉ संदीप कुमार समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे।

Clipping-46

The clipping-46 of 25th February 2015 gives the information regarding Two days National seminar organized in Indira Gandhi girls inter college which was attended by many big personality to save the environment. This news persuades and informs to save the environment

भ्रष्टाचार की हांडी में परवान चढ़ी योजना

Publish Date:Wed, 25 Feb 2015 01:17 AM (IST) | Updated Date:Wed, 25 Feb 2015 01:17 AM (IST)

लालगंज संवाद सहयोगी :

ऊसर सुधार योजना के तहत चादा, मेरुई व बत्रामऊ में खर्च किए गए 57 लाख रुपयों का लाभ चयनित किसानों को मिलना तो दूर, लाभ दिलाने के नाम पर उनसे रुपये ऐंठ लिए गए। देखना यह है कि 25 फरवरी को जाच के लिए आने वाली टीम दूध का दूध और पानी का पानी कर पाती है या फिर जाच के नाम खानापूरी की जाती है।

चांदा गांव निवासी एवं उक्त योजना के लाभार्थी हरिकेश सिंह बताते हैं कि उनके खेत का न तो समतलीकरण कराया गया और न ही जिप्सम ही मिली। खेत में बोरिंग कराने का प्रस्ताव था लेकिन बोरिंग नहीं हुई। खेत में मेड़बंदी के नाम पर पाच हजार रुपये जरूर ले लिए गए।

इसी गांव के अनिल सिंह कहते हैं कि पाच बीघे से अधिक खेत का चयन किया गया लेकिन अन्य खेत छोड़ दिए गए। पूंछने पर अफसरों का कहना था कि एरोप्लेन से सर्वे हुआ है उसमें छूट गया होगा।

वहीं लोधेश्वर कहते हैं कि उन्हे गेहू व खाद तो मिली लेकिन खेत के समतलीकरण या पानी भराने का न तो कार्य कराया गया और न इस बाबत धन ही मिला।

भाकियू ब्लाक अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह कहते हैं कि दो बीघे ऊसर खेत होने के बावजूद चयन नहीं किया गया जबकि उनके खेतों के अगल-बगल स्थित सभी खेतों को चयनित किया गया है। बताया कि 16 बीघे के समूह में एक बोरिंग प्रस्तावित थी। उनमें मानक से कम पाइप डालकर धन आहरित कर लिया गया। मेड़बंदी मनरेगा से कराकर धन डकार लिया गया। पूरा काम एक प्राइवेट आदमी से कराया गया।

Clipping-47

The clipping-47 of 25th February 2015 is plays a major role for the village peoples to revealed the reality of government schemes. This informs that the schemes are developing the area only on Papers but in the reality the corruption is not allowing the schemes to move forward.

भौतिकता की दौड़ में उत्तरदायित्व भूले

Publish Date: Wed, 25 Feb 2015 09:01 PM (IST) | Updated Date: Wed, 25 Feb 2015 09:01 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय प्रगतिपुरम में संगोष्ठी के दूसरे दिन तकनीकी सत्र में वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए।

डॉ. शालिनी अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त करते

हुए कहा कि भौतिकता की दौड़ में हम अपना उत्तरदायित्व भूल गये हैं। डॉ. संदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र हमारे तंत्र से मेल नहीं खाता है, इसीलिए पर्यावरण असंतुलन पैदा हुआ है। इस सत्र में मो. अबरार और सरिता सिंह ने भी अपने शोध पत्रों को पढ़ा।

मुख्य अतिथि डॉ. एसएन सिंह ने कहा कि मनुष्य प्रकृति के सामने स्वयं चुनौती बन कर खड़ा है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने प्राकृतिक परिवेश को विकृत कर दिया। पर्यावरणीय क्षति की समस्या केवल तकनीकी नहीं है इसे आधुनिक विश्व के जीवन चक्र से पोषण मिलता है। हमें ब्रह्मांड, जीव रूपों तथा प्रकृति के अन्तर संबंधों की अनिवार्यता को समझना होगा।

संगोष्ठी के समापन सत्र की अध्यक्षता कालेज की प्राचार्य डॉ. सुषमा देवी ने की और मुख्य अतिथि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागीपुर, प्रतापगढ़ के प्राचार्य डॉ. एस.एन. सिंह थे। समापन समारोह का संचालन डॉ. शालिनी अग्रवाल और श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने किया। इस अवसर पर श्रीमती शिखा मौर्या, डॉ. ऋचा सिंह, डॉ. संतलाल,

Clipping-48

The clipping-48 of 25th February 2015 is to continued news on second day of the National Seminar organized by Indira Gandhi Girls degree college to inform about messaged given by Dr. Shalini Agarwal, Dr. Sandeep Kumar and many others guest on the Technology session.

बजट से लोगों को मिली निराशा

Publish Date: Wed, 25 Feb 2015 08:55 PM (IST) | Updated Date: Wed, 25 Feb 2015 08:55 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : प्रदेश सरकार ने जिले को कृषि यंत्रीकरण योजना में अब तक कोई बजट नहीं दिया जबकि वित्तीय वर्ष बीतने में एक माह ही बचा है। नतीजा किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान ही नहीं मिल पाया। अन्य योजनाओं में जो धन आया था। वह करीब करीब खत्म हो गया है।

इन पर नहीं मिला लाभ

जिले में किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर, चारा मशीन, पंपसेट, इंजन, दवा छिड़कने की मशीन आदि पर चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान नहीं मिला पाया।

ट्रैक्टर पर भी छूट नहीं

पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार ट्रैक्टर करी खरीद पर 48000 रुपए की छूट दे रही थी। चालू वर्ष में अनुदान राशि बढ़ाने के लिए पुराने अनुदान पर रोक लगा दी गई थी लेकिन फरवरी तक सरकार ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान तय करने का निर्णय नहीं ले पाई।

फूल की खेती को बजट नहीं

फूलों की खेती को पिछले साल भी बजट नहीं मिला था। इस साल भी फूलों की खेती के लिए कोई बजट नहीं मिला था। पिछले साल इसी वजह से किसान गुलाब, गेंदा आदि की खेती नहीं कर पाए थे। इस साल भी यही कारण सामने आयेगा।

Clipping-49

The clipping-49 of 25th February 2015 is awareness about the problems that can occur in the future because state government have not given any budget to the district till the end of economic year.

किसान बोले घोषणा हकीकत में बदले तो जानो

Publish Date: Wed, 25 Feb 2015 08:43 PM (IST) | Updated Date: Wed, 25 Feb 2015 08:43 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजट किसानों के लिए तमाम घोषणाएं की हैं। इस पर किसान बोले कि योजनाएं धरातल पर उतर कर हकीकत में बदले तो समझो। सरकार हर साल तमाम घोषणाएं करती है।

ऊंचाहार : बहेरवा गाँव निवासी अमरेश मौर्य का कहना है कि सरकार की घोषणायें तो सुखद हैं लेकिन जब

किसानों को खेत के लिये बिजली, पानी, बीज और खाद के लिये दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं ऐसे में कितनी सुविधाएं और कहाँ तक पहुंचेगी, इसका इंतजार रहेगा। सवैया गाँव निवासी नन्दे छोटे किसान हैं उनका कहना है कि इस बार गेहूँ के लिये उन्हें डीएपी तक नहीं मिली। ऐसे में सरकार की लोक

लुभावनी घोषणायें उन्हें बेमानी लगती हैं। जब फसल को पानी की जरूरत होती है तब नहरों में धूल उड़ने लगती है और बिजली के दर्शन नहीं होते। ऊंचाहार कस्बा निवासी मोहम्मद रुस्तम का कहना है सरकार ने सरकारी अस्पतालों में पांच दिन की मुफ्त दवाएं और ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। सुनने में तो यह चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन अस्पतालों में जब दवा ही नहीं है तो मुफ्त देने की बात ही कहाँ है।

महेशगंज गाँव निवासी पंकज कुमार का कहना है कि चुनाव के समय सरकार ने बच्चों को लैपटाप की घोषणा की। एक साल के बाद बच्चों को लैपटाप नहीं मिला। अब बजट में केवल मेधावी छात्रों को लैपटाप की बात कही गयी है। यह घोषणा भी कब तक चलेगी कहा नहीं जा सकता। गाँव स्तर पर विद्यालयों में अध्यापकों का टोटा है। सरकार प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिये क्या करेगी इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

Clipping-50

The clipping-50 of 25th February 2015 is questioning on the state government. As well as it informs that scheme made by the government are sounds good but in actual it does not work. Statement of villagers shows that how peoples and farmers have face problems because of careless nature of government. This clipping is the example that how newspaper is platform for the common peoples to tell their problems

ग्राम समाज की जमीन गरीबों का आवंटित हो

Publish Date:Wed, 25 Feb 2015 07:39 PM (IST) | Updated Date:Wed, 25 Feb 2015 07:39 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : माकपा के अनुषांगिक संगठन खेत मजदूर यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर विकास भवन में धरना, प्रदर्शन किया। यूनियन ने केंद्र व प्रदेश सरकार से गांवों में खाली पड़ी ग्राम समाज की जमीन को बीपीएल परिवारों को बांटने की मांग की।

बुधवार को विकास भवन में खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता एकजुट हुए। रामदीन विश्वकर्मा ने कहा कि मनरेगा में मजदूरों को कम से कम 200 दिन काम का भुगतान किया जाए। ग्राम समाज की जमीन गरीब परिवारों में बांट दी जाए। बीपीएल परिवार पेट भरने को गैर प्रांतों में जाकर पसीना बहाते हैं। डा. आरबी वर्मा ने कहा कि किसानों पर भूमंडलीकरण की मार पड़ रही है। कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से श्रमिक घट रहे हैं। सरकारें पहले सृजित पदों में लगातार कटौती कर रही हैं। प्रदेश में बाहुबली कमजोर वर्ग पर जुल्म कर रहे हैं। सपा सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारी जमीनों की लूट में सत्ता पक्ष के नेता, विधायक, मंत्री शामिल हैं। जिले में खेत मजदूरों के मिलने वाली जमीन नेताओं के कब्जे में चली गई है। सरकार माफियाओं के हाथों कठपुतली बन गई है। मोदी सरकार भी किसानों के विरोध में काम कर रही है।

इस मौके पर शिवराज, केदारनाथ, सूर्यकली, रामश्री, चांद मोहम्मद, राम सजीवन यादव आदि थे।

Clipping-51

The clipping-51 of Wednesday 25th February 2015 is again an example to their role of newspaper for the peoples. In the clipping with a photograph it shows the protest of labor union for the farmers against the state and central government. Through the newspaper it shows there unity and right to speak for there demands as well as they also informs the critical condition of farmers to the government.

सरेनी की गोद में अधूरे हैं विकास के सपने

Publish Date:Thu, 26 Feb 2015 09:25 PM (IST) | Updated Date:Thu, 26 Feb 2015 09:25 PM (IST)



संवाद सूत्र, सरेनी : शहीदों के खून से रंगी जिले के सरेनी गांव की मिट्टी अपने उत्थान को तरस रही है। केंद्र सरकार की उम्मीदों वाली आदर्श ग्राम योजना से भी इस गांव को न्याय की दरकार है।

सरेनी ग्राम पंचायत के लोगों को स्वाधीन होने के 68 वर्षों के बाद विकास की उम्मीदें तब जरूर दिखीं जब पूर्व पेट्रोलियम मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा ने इस गांव को गोद लेने की घोषणा की किंतु तीन माह बाद भी विकास की किरण न दिखने से लोगों के सुनहरे सपने तार-तार हो गये। इस बीच कई अधिकारी गाव आये सवें भी हुआ किन्तु वो नहीं आये जिन्होंने इसे गोद लेकर गाव के लोगों के मन में विकास के सपने दिखाये थे।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा ने सरेनी ग्राम पंचायत को गत वर्ष 3 दिसंबर को गोद लिया था किंतु दो माह बीत जाने के बाद भी गाव की हालत ज्यों की त्यों है। गाव में पानी

की टंकी तो बनी है मगर इससे जुड़े पुरवे बरदरा, पूरेकुमेदान व गुलाल पुर के लोग ही बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। गाव की सीमा पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य की करोड़ों रुपये की लागत से बनवाई गयी इमारत खड़ी है किंतु यहा न तो एक भी डाक्टर है और न ही फार्मासिस्ट चोट लग जाने या बीमार हो जाने पर लोगों को तीन किमी दूर गोविंदपुर गाव में स्थित सीएचसी में जाना पड़ता है। गाव के आधे हिस्से में बिजली के पोल ही नहीं हैं जबकि पुराने व जर्जर पोल दुर्घटना को ही दावत देते नजर आ रहे हैं। पानी की टंकी के ऊपर से गई विद्युत लाईन भी जान लेवा बनी हुई है।

Clipping-52

The clipping-52 of 26th February 2015 is reporting the reality of the Indian village that after the 68 years of independence a village and there citizens are waiting for the development. At the same it also informs that this village is adopted by the petroleum minister but instead of that the development is like a dream for the village.

सोनिया के क्षेत्र को रेल बजट में कुछ नहीं मिला

Publish Date:Thu, 26 Feb 2015 07:34 PM (IST) | Updated Date:Thu, 26 Feb 2015 07:34 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : संप्रग अध्यक्ष एवं सांसद सोनिया गांधी के क्षेत्र को भाजपा की केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। अमूमन केंद्र में संप्रग कार्यकाल में कुछ न कुछ हर साल मिलता रहा है लेकिन इस बार केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद निराशा हाथ लगने से लोग नाराज दिखे। कहने को रेलवे स्टेशन कागज पर ए ग्रेड घोषित है लेकिन सुविधाएं सी ग्रेड की ही हैं।

शहर के युवा आशीष का कहना है कि जिले से सीधे मुंबई, बंगलूरु, उत्तरांचल, दिल्ली आदि जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। बजट ने निराश किया है।

राकेश ने कहा कि शहर में डबल फाटक के नीचे बने रेल भूमिगत पथ का काम एक साल से बंद चल रहा है। इसके अलावा ऊंचाहार व नेहरु नगर क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज की उम्मीद टूट गई है। जबकि इसके प्रस्ताव पिछले साल ही भेजे गए थे। केंद्र सरकार

का बजट निराश करने वाला है।

समर सिंह ने कहा कि देश में एक भी नई ट्रेन की घोषणा न करना समझ से परे है। हालांकि किराया न बढ़ने से थोड़ी राहत है।

सुमित ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर बना माल कॉम्प्लेक्स गुलजार नहीं हो सका। इसके अलावा रेलवे स्टेशन को एक ग्रेड की सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। केंद्र सरकार रायबरेली की उपेक्षा कर रही है।

गंदगी के बीच ट्रेन का इंतजार

यात्री प्रतीक्षालय में यहां वहां कूड़े का अंबार लगा हुआ है। पान के पीक से पूरा स्टेशन परिसर शर्म से लाल हो गया है। महकमा यात्रियों से बेहतर यात्रा सुविधा के नाम पर मोटी रकम वसूल करता है पर साफ सफाई के नाम सिर्फ कागजी कोरम ही पूरा

Clipping-53

The clipping-53 of 26th February 2015 informs about the situation of the Railways of the district with a statements of many people stating that after a huge budget for Railways the district does not found any profit for their railways. And with the statements it is found that how peoples have facing the problems at the railway station.

लालगंज के कम्युनिटी सेंटर का निर्माण अधूरा

Publish Date: Mon, 02 Mar 2015 01:43 AM (IST) | Updated Date: Mon, 02 Mar 2015 01:43 AM (IST)



लालगंज संवाद सहयोगी : सासद सोनिया गाधी के संसदीय क्षेत्र लालगंज में ही भारत सरकार की ओर से बनवाए जा रहे कम्युनिटी सेंटर का हाल बेहाल है। लगभग दो साल बीतने को है लेकिन अब तक न तो कम्युनिटी सेंटर में प्लास्टर हो सका है न ही फर्श बन सकी है। बरसात में छत अभी से टपकने लगी है।

Jagran News

कस्बे के गाधी चबूतरा स्थल पर भारत सरकार की

ओर से लगभग 35 लाख रुपये की लागत से कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराया जाना था। कार्यदाई संस्था ने जून 2012 में दीवारें खड़ी कर छत डलवा दी उसके बाद से निर्माण कार्य बंद है। दीवारों से लेकर छत तक न ही प्लास्टर हो सका है। और न ही अभी फर्श ही बनवाई जा सकी है। यही नहीं भवन में अभी गेट भी नहीं लगा सका है। शौचालय के नाम पर बनाये गये कमरों की फर्श कई फुट गहरी है। इनमें मिट्टी की भरई तक नहीं कराई गई है। इतना जरूर है कि भवन निर्माण सामग्री लाने वाले ट्रक की टक्कर से गाधी चबूतरे का इकलौता बचा गेट भी टूट कर धराशायी हो गया था, जो अब तक नहीं बन सका है। गेट टूटने से ऐतिहासिक गाधी चबूतरा आवारा जानवरों का चारागाह बन गया है। लाखों रुपये की लागत से अधूरे पड़े कम्युनिटी सेंटर का लाभ स्मैकिये उठा रहे हैं। कम्युनिटी सेंटर की बाबत कुछ कांग्रेसी दबी जुबान कहते हैं कि सासद के संसदीय क्षेत्र में यह योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। उनकी माने तो मानकों की धज्जिया उड़ा कर इसका निर्माण कराया गया है।

क्या बोले जवाबदेह

मामले का पता लगाया जाएगा कि कम्युनिटी हाल का निर्माण कार्य अधर में क्यों लटका हुआ है। शिकायत आई तो कार्यदाई संस्था को नोटिस देकर जवाब भी मांगा जाएगा। -दिलीप कुमार त्रिगुणायक, उपजिलाधिकारी लालगंज।

Clipping-54

The clipping-54 of 2nd March 2015 depicts the lack of government system for the development of the community center. After a long period government fails to construct a community center in the district.

116 बेरोजगारों को मिला रोजगार

Publish Date: Tue, 03 Mar 2015 06:54 PM (IST) | Updated Date: Tue, 03 Mar 2015 06:54 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : जिला सेवायोजन अधिकारियों के संयोजन में कार्यालय पर बेरोजगारों मेले का आयोजन किया गया। जिले भर से करीब डार्ड सौ युवा साक्षात्कार में शामिल हुए। उर्वरक निर्माता कंपनी व सुरक्षा कंपनी ने मिलकर एक सौ सोलह युवाओं को रोजगार देने के लिए चयन किया।

सेवायोजन अधिकारी रामयश मौर्य के बुलावे पर कृषि उर्वरक निर्माता कंपनी के एचआर प्रबंधक अरविंद पटेल व रामफल मौर्य ने 129 युवाओं को चयन के लिए साक्षात्कार लिया। इसमें 78 युवाओं का चयन किया गया। युवाओं को जिले में ही तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक युवा को 8500 रुपए मानदेय के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा ग्रुप फार सिक्योरिटी साल्यूशन कंपनी के शैलेंद्र

कुमार पांडेय ने 48 युवाओं का चयन किया। चयनित युवाओं को गुड़गांव में प्रशिक्षण के बाद काम पर लगाया जाएगा।

जिला सेवायोजन अधिकारी ने कहा कि सरकारी जाब काफी कम हैं। इस कारण युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है। रोजगार मेले के आयोजन में राम सेवक, सर्वेश राय आदि ने सहयोग किया।

Clipping-55

The clipping-55 of 3rd March 2015 of Newspaper stated that the district SevaYojna Officer organized a job fair for the unemployed peoples in which many people are selected. Officer gives a statement that the government jobs are limited so we are trying to provide private jobs

औद्योगिक मिशन के लिए तीन करोड़ का प्रस्ताव

Publish Date:Thu, 12 Mar 2015 07:42 PM (IST) | Updated Date:Thu, 12 Mar 2015 07:42 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : औद्योगिक मिशन की समीक्षा में नई कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। वर्ष 2015-16 के लिए मिशन योजना चलाने को तीन करोड़ सत्रह लाख रुपए की मांग की गई है। इसके अलावा माइक्रो सिंचाई का बजट अलग से मांगा गया है।

उद्यान विभाग में संचालित औद्योगिक मिशन की समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट के बचत भवन में की। सीडीओ ने समाप्त होने जा रहे वर्ष के बजट व कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। सीडीओ ने कहा कि किसानों को फल सब्जी उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाय। प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी किसानों को दी जाय। इसके बाद पात्र

किसानों को योजना का लाभ दिया जाय। सीडीओ [Jagran News](#) की वार्षिक योजना का अनुमोदन कर शासन के पास स्वीकृत के लिए भेजा। इसके अलावा माइक्रो सिंचाई के लिए 34 लाख रुपए की मांग की गई है।

बैठक में उद्यान विभाग के उप निदेशक वाहिद अली ने टिशू कल्चर, केला व अनार उत्पादन के लिए लिए बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। डीएचओ गया प्रसाद ने चालू वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य गिनाए। बताया कि 21 किसानों को ड्रिप सिंचाई के लिए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इस मौके पर डीडी डा. अजय कृष्ण, जिला कृषि अधिकारी इसके पांडेय, सीवीओ केके चौधरी, उद्यान निरीक्षक नागेंद्र सिंह, राजश्री आदि मौजूद रहे।

Clipping-56

The clipping-56 of 12th March 2015 newspaper is to inform that 1.17cr is demanded for the Industrialization mission 2015-16 in the meeting held at the end budget session. In the meeting CDO says that we have to support the farmers and provide the knowledge regarding the schemes provided by the state and central government. So that the farmers produce more and earn more profit.

सपा ने प्रदेश का किया चहुंमुखी विकास

Publish Date: Sun, 15 Mar 2015 08:24 PM (IST) | Updated Date: Sun, 15 Mar 2015 08:24 PM (IST)



रोहनियां, संवाद सूत्र : समाजवादी पार्टी की सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष डा. मनोज कुमार पाण्डेय ने रविवार को अपनी ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में विकास महारैली की।

Jagran News

बोधित करते हुये श्री पाण्डेय ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र में सरकार की विश्वसनीयता को बढ़ाने का काम किया है। यूं तो चुनाव से पूर्व सभी वायदे करते हैं

लेकिन वायदों को निभाने एवं योजनाओं को लागू करने का काम सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। वादों को पूरा करके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनता के द्वारा दिये गये मतों का सम्मान रखा है। साथ ही समाजवादी पार्टी की विश्वसनीयता को और मजबूत करने का काम किया है। भाषण तथा वायदों से देश की जनता को लगातार मिल रहे धोखे से बेहाल किसान को किसान बीमा दुर्घटना योजना का लाभ मिला। किसानों के लिए सरकार का खजाना खोलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जनता में यह विश्वास जाग्रत हुआ है कि सबको छत मिलेगी एवं सबको रोजगार मिलेगा। अब किसान को भी विश्वास हो गया है कि इलाज से कोई वंचित अब नहीं रहेगा। सबके इलाज के लिए आर्थिक सहायता की योजना को लागू किया गया है। ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र को चारागाह के रूप में बना दिया गया था।

Clipping-57

The clipping-57 of 15th March 2015 informs that Samjwadi Party has completed their 3 years in the state successful in the government. The news published with a photograph of cabinet Minister Dr. Manoj Kumar celebrating in the Unchahar area. On this occasion Dr. manoj Kumar informs about the work done by the government in the three years and also makes the other parties guilty by his views.

ग्राम स्वच्छता समितियों में धन नहीं हो सका खर्च

Publish Date:Wed, 18 Mar 2015 08:55 PM (IST) | Updated Date:Wed, 18 Mar 2015 08:55 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : एक ओर मौसम में परिवर्तन होने के बाद संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। वहीं जिले में स्वाइन व बर्ड फ्लू के प्रकोप से लोग भयभीत हैं। इसके बाद सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए गठित ग्राम स्वच्छता समितियां सुस्त पड़ी हुई हैं। हाल यह है कि सालों पहले गांव की सफाई व्यवस्था के लिए दिया गया पैसा अभी तक खर्च नहीं हो सका है।

गांवों में स्वास्थ्य समितियों का गठन किया गया था। इस समिति में प्रधान को अध्यक्ष व एएनएम को सचिव बनाया गया था। समिति के खाते में प्रति साल दस हजार रुपए देकर गांवों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने की योजना थी। वर्ष 2011-12 प्रत्येक गांव पंचायत को पैसा भेजा गया था, लेकिन यह पैसा अभी तक खर्च नहीं किया जा सका है।

इधर, गर्मी शुरू होने के साथ ही गांवों में संक्रामक बीमारियों का दौर शुरू हो गया है। रोजाना दर्जनों की संख्या में बुखार, जुकाम, उल्टी-दस्त के मरीज जिला अस्पताल व निजी चिकित्सकों के यहां इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इसके बाद भी गांवों में सफाई कार्य नहीं कराया जा रहा है। वैसे तो गांवों में सफाई करने के लिए पंचायतराज विभाग ने एक कर्म को राजस्व गांव के हिसाब से तैनात कर रखा है।

सीएमओ डा. एलबी सिंह ने बताया कि ग्राम स्वच्छता समितियों में जमा रुपया अब तक क्यों नहीं खर्च हो सका है। इसके बारे में जानकारी की जाएगी।

Clipping-58

The clipping-58 of 18th March 2015 depicted that in the district many diseases are targeting the people. The Swachta Samities are found that the grant provided by the government is not used. This news brings the prime of the villages and other officers to be shameful as well as informs the peoples that what their leaders are doing for their health.

ग्रामीण आबादी को नसीब नहीं शुद्ध पेयजल

Publish Date:Thu, 19 Mar 2015 08:53 PM (IST) | Updated Date:Thu, 19 Mar 2015 08:53 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : केंद्र व प्रदेश की सरकारों ने कर्ज ले कर ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने के लिए जिले में तक 77 पेयजल बड़ी परियोजना का जाल बिछाया था। इसके अलावा छोटे नलकूप व पेयजल परियोजना अलग हैं। एक पेयजल परियोजना से पांच किलोमीटर दूरी तक शुद्ध पेयजल के लिए पाइप लाइन बिछाई गई थी। वर्तमान में किसी परियोजना में दो किलोमीटर दूरी में भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। जिले में जल निगम की इकाई में अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता, आपरेटर, पंपचालक, तकनीशियन सहित कर्मचारियों की फौज है। कई कर्मचारी तैनाती स्थल पर महीनों नहीं जाते हैं। यह देखने वाला कोई नहीं है।

Clipping-59

The clipping-59 of 19th March 2015 is informing that state and Central government has taken loan to provide the clean water for the rural areas but after the construction till no such facilities are provided to them. There are many officers in the District but still no one have is there to take care on this issue.

कैसे पाएं शिक्षा जब अधूरी हैं कक्षा

Publish Date: Sun, 22 Mar 2015 05:45 PM (IST) | Updated Date: Sun, 22 Mar 2015 05:45 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : वर्ष पर वर्ष गुजरते जा रहे हैं लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग 161 विद्यालयों का निर्माण पूरा नहीं कर सका है। निदेशालय विभाग के खाते में बजट भेज चुका है। इन स्थितियों के चलते दो वर्षों से विभाग एक भी स्कूल बनवाने का लक्ष्य पूरा नहीं कर सका है। विभागीय अफसरों का कहना है कि महंगाई बढ़ने के कारण जो रकम भेजी गयी है, वह 48 फीसदी कम पड़ रही है।

जिले में वर्ष 2011-12 में 400 विद्यालयों के निर्माण का लक्ष्य बेसिक शिक्षा विभाग को सौंपा गया था। इस लक्ष्य के सापेक्ष में विभाग ने जिले में 450 स्कूलों का निर्माण भी करा दिया था लेकिन 2011-12 के 50 विद्यालयों का निर्माण आज तक नहीं हो

सका। इसी तरह वर्ष 2012-13 में 129 विद्यालयों का लक्ष्य स्वीकृत किया गया था। इस लक्ष्य के सापेक्ष 18 विद्यालय बनें जबकि 111 स्कूलों का निर्माण आज भी अधर में लटका है। इन 161 स्कूलों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके चलते विभाग को 2013-14 और 2014-15 के सापेक्ष स्कूल बनवाने का कोई लक्ष्य नहीं मिल सका है। बेसिक शिक्षा विभाग में निर्माण से जुड़े काम देख रहे राशिद का कहना है कि शासन से मिले बजट और महंगाई को देखा जाए तो करीब 48 फीसदी का अंतर आ रहा है।

बीएसए संदीप चौधरी का कहना है कि बजट के सापेक्ष महंगाई को देखते रिपोर्ट शासन स्तर पर भेजी गई है। निर्देश मिलने के बाद ही विद्यालय निर्माण का काम शुरू हो जायेगा।

Clipping-60

The clipping-60 of 22nd March 2015 is to inform that after long time basic Education department is failed to construct 161 schools. In the two years the department does not construct a single school where as on this officials says that the budget provided by the department is 48.0% short.

विकास कार्यों को लेकर सभासदों ने जताई नाराजगी

Publish Date:Thu, 26 Mar 2015 01:13 AM (IST) | Updated Date:Thu, 26 Mar 2015 01:13 AM (IST)



लालगंज संवाद सहयोगी : लंबे असें बाद नगर पंचायत लालगंज बोर्ड बैठक तो हुई लेकिन विकास कार्यों के लिए प्रस्तावों की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबकुछ कोरम पूरा करने के लिए ही कर दिया गया।

बोर्ड बैठक प्रारंभ होते ही सभासदों में पुराने कार्यों को पूरा न कराए जाने एवं कई कार्यों को शिकायतों के बाद भी शुरू न कराए जाने पर आक्रोश जताया। इसके चलते 15 सभासदों में से 10 सभासदों ने पुराने कार्यों की पुष्टि करने से ही इंकार कर दिया। पार्किंग शुल्क का ठेका उठाने की बात पर अधिशाषी अधिकारी सुरेश मौर्य ने कर्मचारियों की कमी की Jagran News सभासद वाहनों से वसूली के नाम पर ठेकेदारों द्वारा दबाई करने की बात

कहकर ठेका उठाने पर तैयार नहीं हुए। वहा मौजूद आधे से अधिक सभासदों ने ठेका न उठाने के पक्ष में अपनी सहमति दर्ज कराई। हड्डी-चमड़ा का ठेका उठाए जाने की बात पर जब सभासदों ने यह जानना चाहा कि वर्तमान में यह ठेका किसके पास है और इसे कब उठाया गया था तो बताया गया कि ठेका पिछले साल उठाया ही नहीं गया। टेंडर कराने के नाम पर कहा गया कि जितने का ठेका उठता है उससे ज्यादा विज्ञापन प्रकाशन में खर्च होता है। सभासद रामनारायण, अवधेश तिवारी, संगीता, कंचन सूर्यवंशी, पुष्पादेवी, रामदुलारी आदि ने नगर में दो साल के अंदर एक भी इंडियामार्क नल व सोलर लाइट न लगवाए जाने समेत सामुदायिक शौचालय न बनवाये जाने पर नाराजगी जताई। वहीं अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने बताया कि नल के लिए टेंडर कराये जा चुके हैं और शीघ्र लग जाएंगे।

Clipping-61

The clipping-61 of 26th March 2015 is informing about the meeting held in Lalganj after a long period. It informs that new development schemes are not announced for district. In the meeting many complaint against the previous pending works only.

विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने को लगा मेला

Publish Date:Wed, 08 Apr 2015 07:13 PM (IST) | Updated Date:Wed, 08 Apr 2015 07:13 PM (IST)



ऊंचाहार, संवाद सहयोगी : बुधवार को ऊंचाहार ब्लाक संसाधन केंद्र में नामांकन मेला आयोजित हुआ जिसमें स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों को स्कूल भेजने के लिये लोगों में जागरूकता पैदा की गई और शिक्षा के महत्व से संबंधित कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

नामांकन मेले में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने भाग लिया। इस मेले में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने शासन द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। यही नहीं बाल शिक्षा अधिकार के बारे में भी वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की।

वक्ताओं ने कहा कि खुशहाल जीवन के लिये शिक्षित होना जरूरी

है बिना शिक्षा के जीवन व्यर्थ है। अशिक्षित लोग पशुओं की जिंदगी जीते हैं। इस मौके पर ब्लाक प्रमुख पंचम मौर्य, लक्ष्मीर शुकल, बीडीओ जे एन राव, एबीएसए जैनेन्द्र गुप्ता के अलावा प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश सह विशेष रूप से उपस्थित थे। मेले के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया जिसमें कस्तूरबा विद्यालय के बच्चों ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

Clipping-62

The clipping-62 of 8th April 2015 is to inform about the fair on the importance of school for the children. In the fair many people give their views that how important for the children to go in the school with this they say that we have to send our children in the school so that the numbers of the student for the admission should be increased.

कृषि योजनाओं को धरातल पर लाएं

Publish Date: Fri, 29 May 2015 05:52 PM (IST) | Updated Date: Fri, 29 May 2015 05:52 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : जिला पंचायत सभागार में आयोजित जिलास्तरीय किसान गोष्ठी में डीएम प्रेमनारायण ने शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा किसानों को बेहतर जानकारी देने के लिए विकास खंड व तहसील स्तर पर भी किसान गोष्ठियों का आयोजन कराया जाए।

डीएम ने कहा कि आज किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती करने तथा नए-नए उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग कर पैदावार बढ़ाने की

आवश्यकता है। साथ ही किसानों के पास सभी आधुनिक कृषि यंत्र भी होने चाहिए। किसान ज्यादा से ज्यादा नकदी फसल उगाएं तथा सभी किसान, किसान क्रेडिट कार्ड अवश्य बनवाएं। किसान अपनी-अपनी जमीनों का मृदा परीक्षण के उपरांत ही संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। उप निदेशक कृषि अजय कृष्ण ने बताया कि किसानों को प्रायः कृषि संबंधी जानकारी दी जाती रहती है। उन्होंने आश्वासन दिया की खाद व बीज की समस्या नहीं होनी दी जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि कृषि विभाग से अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान टोल फ्री नंबर 1800-200-1050 पर मिस्ट काल करके पंजीकरण नंबर प्राप्त कर उन्नत सील बीज विभिन्न कृषि यंत्र, कृषि रक्षा रसायन आदि सुगमतः से प्राप्त कर सकते हैं। जिला पंचायत के प्रांगण में कृषि विभाग द्वारा कृषि से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाए गए।

Clipping-63

The clipping-63 of 29th May 2015 with a photograph shows that a meeting is held for the development of the farmers in the district so that they should know better about technology used for the farming. With this they provided a toll free number on which they can register themselves for getting the seeds and tools etc.

करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं बदली सूरत

Publish Date: Sun, 23 Aug 2015 06:20 PM (IST) | Updated Date: Sun, 23 Aug 2015 06:20 PM (IST)



ऊंचाहार, संवाद सहयोगी : 32 साल पुरानी ऊंचाहार नगर पंचायत के निवासियों को आज भी मूलभूत जरूरतों के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इन 32 सालों में विकास के नाम पर बड़ी-बड़ी बाते हुई और करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन नगर के मोहल्लों की सूरत नहीं बदल सकी है। खासकर वार्ड दस की दशा बेहद खराब है।

रविवार को जागरण आपके ~~संवाद सहयोगी~~ तहत जागरण की टीम नगर के वार्ड संख्या 10 के मोहल्ला भित्री गांव पहुंचा कहने को तो नगर पंचायत के वार्ड दस को आदर्श वार्ड का दर्जा मिला है। इस मोहल्ले में खासी मुस्लिम आबादी है। मोहल्ले के लोग सड़क, पानी तथा साफ सफाई जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। बताया जाता है कि इस मोहल्ले में विधायक निधि, निकाय निधि एवं डूडा से काम

कराए गए हैं। इनमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया लेकिन लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। असल में विकास के नाम जमकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

नहीं बना आवागमन का मार्ग

भित्री मोहल्ले में गंदा नाला के किनारे अधरी गांव से लेकर डा. अजहर के घर तक नाला की पटरी से आम रास्ता बना हुआ है। लखनऊ-इलाहाबाद राजमार्ग पर स्थित गंदा नाला पुल से जैसे ही कस्बे की ओर मुड़ते हैं भित्री मोहल्ला शुरू हो जाता है। मोहल्ले के लिए विधायक निधि द्वारा इंटर लॉक रास्ता बनाया गया था लेकिन अतरी गांव के बाद रास्ता का निर्माण कस्बे के अंदर चला गया और नाले की पटरी का रास्ता आज भी कच्चा और कीचड़ से सना हुआ है। इस रास्ते पर पड़ने वाले मकान के लोग शहर में रहने के बावजूद गांव से बदतर जीवन जी रहे हैं।

Clipping-64

The clipping-64 of 23rd August 2015 with photograph of villager informing that newspaper is a very important tool for common man to speak and spread their situation to many others. In the news it is described that after a 32 years establishment of Unchahar nagar Panchayat villagers have to do very struggle for their important life resources. As well as no such action is taken to improve the water, irrigation, roads like problems.

27 सौ स्कूल, 2.79 लाख छात्र पर खेल मैदान नहीं

Publish Date:Thu, 08 Oct 2015 11:44 PM (IST) | Updated Date:Thu, 08 Oct 2015 11:44 PM (IST)

रायबरेली : सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों की संख्या 27 सौ हैं। इन स्कूलों में 2.79 लाख छात्र पंजीकृत हैं। छात्रों में बैटिक विकास और योजनाओं में शासन द्वारा अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इन 27 स्कूलों में से किसी स्कूल में खेल मैदान नहीं बना है। खेल मैदान न होने के कारण स्कूलों की वार्षिक प्रतियोगिताएं भी 'किराए' के मैदानों में संपन्न कराई जाती हैं। इससे न तो छात्र ठीक से अभ्यास कर पाते हैं और न ही उनकी प्रतिभा में निखार आ पाता है। जबकि विभाग द्वारा शासन से पर्याप्त मात्रा में बजट की मांग प्रत्येक वर्ष की जाती है।

Jagran New

सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष बेसिक स्कूलों के लिए अरबों रुपए की योजनाएं बनाकर छात्रों को लाभान्वित करने का

प्रयास किया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से निःशुल्क कापी-किताबें, यूतीफार्म, मध्याह्न भोजन समेत कई अन्य योजना हैं। ताकि छात्रों की संख्या बेसिक स्कूलों में बढ़ सके। लेकिन पूर्व में राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से कराए गए सर्वे में बेसिक स्कूलों की हालत बहुत खराब मिली। इनमें प्रमुख रूप से पाया गया था कि विभाग के पास खेल मैदान ही नहीं है। वहीं विकलांग छात्रों के लिए स्कूलों में रैंप तक नहीं बनवाई गई है। परियोजना के जारी किए गए बजट को मनमर्जी तरीके से खर्च किया गया। इसके अंदाजा लगाया जा सका है कि शिक्षाधिकारी छात्रों के प्रति कितनी सक्रियता बरतते हैं। हकीकत यह है कि बेसिक स्कूलों में खेल मैदान न होने के कारण 2,79,925 छात्र-छात्राओं की प्रतियोगिता कराने के लिए राजकीय इंटर कालेज का खेल मैदान या फिर मोती लाल नेहरू स्टेडियम को अक्सर 'किराए' पर मांगा जाता है। बेसिक शिक्षा विभाग के पास खुद का खेल मैदान न होने से छात्र-छात्राओं के अंदर छुपी खेल प्रतिभाओं में निखार नहीं आ पा रहा है। इसके बाद भी जिले के शिक्षाधिकारियों द्वारा कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा है।

Clipping-65

The clipping-65 of 8th October 2015 is showing the reality of schools condition in the news paper. This news reports that there are 27 primary and junior schools in which 2.79 lacs of students registered but instead of that no schools have their own ground for the students because of which schools have to borrow the other ground to organize any sports event. This news help to impact higher authority about the critical conditions of the schools so that children's will use and do practice on their own schools ground.

रायबरेली को स्मार्ट सिटी बनाने पर सीएम की हामी

Publish Date: Mon, 19 Oct 2015 11:12 PM (IST) | Updated Date: Mon, 19 Oct 2015 11:12 PM (IST)



रायबरेली : रायबरेली और मेरठ में कौन स्मार्ट सिटी बनेगा इसका फैसला केंद्र सरकार को करना है लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री रायबरेली को स्मार्ट सिटी बनना देखना चाहते हैं। इसके लिए वह अपना वीटो भी लगा सकते हैं। असल में यह बात उभर कर उस समय सामने आई जब रायबरेली स्मार्ट सिटी संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ में उनसे भेंटकर हस्ताक्षर अभियान की

प्रति सौंपी। सीएम ने समिति के सदस्यों से कहा कि रायबरेली को स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए।

समिति के संयोजक बृजेन्द्र सिंह ने सीएम अखिलेश यादव से कहा कि मेरठ तो एनसीआर का हिस्सा है वहीं रायबरेली लखनऊ के पास है ऐसे में रायबरेली स्मार्ट सिटी बने तो बेहतर होगा। सीएम ने समिति की हौसलाअफजाई करते हुए कहा कि सभी को केंद्र से लड़ना होगा तभी रायबरेली को उसका तमगा मिलेगा। समिति की प्रवक्ता शबिस्ता बृजेश ने कहा कि रायबरेली स्मार्ट सिटी बनेगी तो उसका और विकास होगा। इस मौके पर सीएम ने शिक्षा, नगरपालिका तथा समाजवादी पेंशन पर भर्चा की। इस अवसर पर संरक्षक अवतार सिंह छाबड़ा, हरिहर सिंह, सोनू गांधी, पारुल बाजपेई, जगजीवन शुक्ला आदि मौजूद रहे।

Clipping-66

The clipping-66 of 19th October 2015 inform about decision of UP chief minister to select district Raebareli for the central government scheme to make it Smart City. This news informs the detail about the selection of the district to make it smart City.

रैली के जरिए बताए एचआइवी से बचाव के उपाय

Publish Date: Tue, 01 Dec 2015 11:25 PM (IST) | Updated Date: Tue, 01 Dec 2015 11:25 PM (IST)



रायबरेली : विश्व एड्स दिवस पर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल, कालेज और संस्थाओं के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाली गई रैली में हिस्सा लिया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अफसरों द्वारा एड्स/एचआईवी से रोकथाम के इलाज बताए। उन्होंने कहा कि एड्स/एचआईवी से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है।

विश्व एड्स दिवस के मौके पर अपर मुख्य

चिकित्सा अधीक्षिका डॉ निशा सोनकर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में एड्स की बीमारी किस प्रकार समाज में फैल रही है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें स्वयं में जागरूकता लानी होगी और दूसरे को भी जागरूक करना होगा। इसके साथ ही एड्स/एचआईवी रोकथाम के उपाय भी बताए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गली-गली निकाली गई विश्व एड्स दिवस की रैली में स्कूल और कालेज के छात्र कागज पर लिखे स्लोगन की तक्तियां लेकर चल रहे थे। जिससे एड्स/एचआईवी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। डॉ एसके चक ने कहा कि विभाग द्वारा जागरूकता को लेकर समय-समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रैली में आईसीटीसी ग्रामीण शिक्षण संस्थान, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), ग्रामीण विकास संस्थान, मरियम बीबी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, आचार्य द्विवेदी इंटर कालेज, वैदिक इंटर कालेज, एमजीआईसी, लाल ऋषि कन्या इंटर कालेज, राजकीय इंटर कालेज, स्काउट-गाइड समेत अन्य कालेजों के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। रैली में चल रहे छात्रों ने लोगों को जागरूक किया। वहीं नुककड़ नाटक के कार्यक्रम में आईटीबीपी रायबरेली को प्रथम पुरस्कार के रूप में दो हजार रुपए, द्वितीय पुरस्कार ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान को 1500 रुपए और ग्रामीण विकास संस्थान बछरावां को तृतीय पुरस्कार 1000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। प्रभारी सीएमओ एनके श्रीवास्तव ने कहा कि जागरूकता के आभाव में अब उठने वाले कदमों को रोकना है। ताकि एड्स/एचआईवी से बचाव किया जा सके। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अफसर समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे।

Clipping-67

The clipping-67 of 1st December 2015 gives information regarding the precautions of AIDS and how to ignore the disease. In the clipping a report with a Photograph shows the step taken by the Health department which was supported by schools, colleges and other organization to stop the disease in the society on World AIDS Day. This clipping plays an important role to inform about this to other peoples of the District.

जिला न्यायाधीश ने लगाई जेल में पाठशाला

Publish Date: Tue, 19 Jan 2016 12:11 AM (IST) | Updated Date: Tue, 19 Jan 2016 12:11 AM (IST)



रायबरेली : विधिक साक्षरता से जिला कारागार में बंद बंदी भी अवगत हो इसके लिए शिविर लगाया गया। जिला न्यायाधीश ने बंदियों को समाजिक व्यवस्था तथा कानून से रुबरू कराया। उन्होंने बैरक व भोजनालय का निरीक्षण किया गया। दो बैरक ठीक न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई।

जिला न्यायाधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने कहा कि अपराधी भी इसी समाज का हिस्सा हैं। कानून

अपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का साधन है। उन्होंने बंदियों की समस्याएं सुन निस्तारण का आश्वासन दिया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तेज प्रताप तिवारी ने कहा कि जिन कैदियों के पास वकील नहीं हैं उन्हें सरकारी वकील की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुकदमों का शीघ्र निपटारा हो इसलिए लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सीजेएम इफराक अहमद खान ने कहा कि कैदियों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। शिविर के बाद जिला न्यायाधीश ने जेल के भोजनालय तथा बैरक का निरीक्षण किया। इसमें बैरक संख्या 1 व 1बी की स्थिति ठीक न मिलने पर जेल अधीक्षक अमिता दुबे से कारण पूछा। जेल अधीक्षक ने बताया कि बैरकों की मरम्मत के लिए शासन से बजट के लिए पत्र लिखा गया है। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एसपी सिंह, एडीएम प्रशासन सुभाष चंद्र चौधरी, एसपी राम मूरत यादव, जेल अधीक्षक अमिता दुबे आदि मौजूद रहे।

उन्होंने न्यू स्टैंडर्ड इंटर कालेज, त्रिपुला में भी शिविर लगाया। उन्होंने बच्चों से कहा कि चरित्रवान बनो और खुश रहो। प्राधिकरण के सचिव तेज प्रताप तिवारी ने कहा कि बच्चे अवसाद में न आएं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इफराक अहमद ने कहा कि संविधान में कानून के शासन की व्यवस्था है।

Clipping-68

The clipping-68 of 19th January 2016 informs about a class of prisoners taken by the District Magistrate in the prison as he listen the problems faced by the prisoners in the jail and assure to solve it as soon as possible. All the prisoners are a part of our society DM added.

पीएम रोजगार योजना के पंपलेट तक नहीं

Publish Date: Mon, 27 Oct 2014 09:27 PM (IST) | Updated Date: Mon, 27 Oct 2014 09:27 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : खादी ग्रामोद्योग विभाग में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम व प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार योजना चल रही है। सरकार से मिले मामूली लक्ष्य में बेरोजगार युवाओं को कुटीर उद्योग लगने के लिए चार प्रतिशत व्याज दर पर पचास हजार से लेकर पच्चीस लाख रुपए की यूनिट लगाने के लिए के बैंकों को ऋण स्वीकृत करने के लिए फाइल भेजी जाती है। इतना करने में ही पूरा विभाग अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक काम के बोझ से दबा महसूस कर रहा है।

सोमवार को ग्रामोद्योग अधिकारी एस ए जैदी कुछ युवाओं के साक्षात्कार करने में लगे थे। कार्यालय के अन्य बाबू भी फाइलें पलटने में मशगूल थे। दो योजनाओं की जानकारी करने के लिए

तीन लोगों से संपर्क करना पड़ा। इसके बाद भी आधी अधूरी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की जानकारी करने आए एक युवक को प्रधानमंत्री योजना की जानकारी देने के लिए एक पंपलेट तक नहीं दिया गया। वहां आए एक युवक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री योजना में फाइल भेजने के लिए अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को खुश करना पड़ता है।

भाजपा जिलाध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजेंगे। चारागाह समझकर जिले में लंबे समय से डटे अधिकारियों को हटाया जाए। इसके लिए केंद्र तक पैरवी की जाएगी।

Clipping-69

The clipping-69 of 27th October 2014 depicts that the drawbacks of central and state government schemes. It informs that in the District the youths are not getting the any profit on the employment schemes. It also informs that youth have to do struggle to know about the both central and state government schemes.

कहीं पी गए पूरा खड़जा

Publish Date: Fri, 31 Oct 2014 01:24 AM (IST) | Updated Date: Fri, 31 Oct 2014 01:24 AM (IST)

ऊंचाहार, संवाद सहयोगी: मनरेगा व गांवों के विकास की योजनाओं में अरबों रुपए खर्च होने के बाद विकास से गांव दूर क्यों है। इसका उदाहरण ऊंचाहार के रोहनियां ब्लाक के रायपुर में देखने को मिला। यहां इंदिरा आवास में लूट हुई तो सड़क और खड़जे का निर्माण कागजों पर हो गया। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में गांव के विकास की पूरी कहानी खुल गई। गांव में एनटीपीसी द्वारा बनवाए गए खड़जे को मनरेगा से भुगतान व इंदिरा आवास में बंदरबांट ही नहीं हुआ बिना बनी सड़क का भुगतान हुआ है और खड़जों की लंबाई चौड़ाई अधिक दिखाकर लूट की गई।

घोटाले की जननी बनी मनरेगा गड़बड़ियों के कारण सीबीआई जांच के दायरे में लेकिन इसमें जेब भरने का काम नहीं रुक रहा है। रोहनिया विकास खंड के रायपुर गांव में सूचना का अधिकार से हुए खुलासे के बाद अब जिम्मेदार लोगों पर तलवार लटक रही है। रायपुर गाँव के निवासी चन्द्र मौलि पाण्डेय द्वारा सूचना का अधिकार के तहत मागी गयी जानकारी के बाद विभिन्न स्तर पर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। गांव में एक दर्जन से ज्यादा लोगों अपात्रों को दूसरे की बीपीएल कार्ड धारकों को मकान दे दिया गया। इतना ही नहीं एनटीपीसी द्वारा बनाए गए खड़जे को मनरेगा से बना दिखाकर भुगतान करा लिया गया है। इसको लेकर जांच टीम को नए नए खुलासे दिखाई दे रहे हैं। डीआरडीए के सहायक अभियंता द्वारा की जा रही जांच में कई खड़जे का या तो कागजों पर निर्माण मिला या तो उनकी लंबाई चौड़ाई कम मिली।

जांच में पाया गया कि गांव में सन 2010-11 में सड़क से शिवबालक के घर तक खड़जा बनवाया गया था। इस काम में बड़ी गड़बड़ियाँ हैं। पक्की सड़क से डेलोली बार्डर तक इसी वर्ष बनवाए गए खड़जा मार्ग की लंबाई चौड़ाई में खेलकर लूट हुई। इसकी लंबाई दो सौ पचास मीटर और चौड़ाई तीन मीटर दर्शा कर भुगतान किया गया है। जबकि लंबाई 177 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर ही है। यही नहीं 2011 में पूरे ठकुराइन में खड़जा से लेकर राज बहादुर के घर तक निर्माण कार्य दर्शाया गया है। मौके पर काम ही नहीं हुआ है। गाँव के जंगल से मेन रोड तक 2011-12 में मार्ग का निर्माण दर्शाया गया है, जबकि यह काम पाँच साल पहले एनटीपीसी द्वारा कराया गया है।

Clipping-70

The clipping-70 of 31st October 2014 opens the truth of the development done in the Unchahar Area. It informs that lots of money used in the development but no such outcome is there. The roads are still in critical condition. After the RTI it is found there are lots of corruption in the MGNRGA for which CBI is investigating but it does not affect anything still the corruption is on the top because of which common peoples are facing the problem every day.

पांच करोड़ खर्च फिर भी न सुधरी सड़क

Publish Date: Tue, 04 Nov 2014 07:53 PM (IST) | Updated Date: Tue, 04 Nov 2014 07:53 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : शहर की सड़कें अब गांव के गलियारे के सरीखे हो गई हैं। हर ओर सिर्फ बंदहाली ही दिख रही है। डिग्री कालेज चौराहे से घोसियाना और निराला नगर आदि को जाने वाली रोड लाख कवायदों के बाद भी बनने को नहीं तैयार हो सकी। अनेकों शिकायतें हुईं लेकिन लोगों की बातें हमेशा अनसुनी की गईं। नगर पालिका ने कभी बजट न होने की बात कही तो कभी जल्द ही रोड बनने का आश्वासन देकर आम लोगों से पल्ला फुड़ाया। मसलन बस आम लोगों को आह करने के लिए यह मार्ग मासूल उड़ाता रहा।

जिले में शहर की सड़कों के निर्माण के लिए ही

पांच करोड़ से अधिक की पूंजी अनेक निधियों और पालिका श्रोतों से मिले लेकिन कमीशन खोरी का दर ओर जलवा रहा नतीजन रोड बनती गई और बिगड़ने में वक्त न लगा।

वीवीआईपी जिले के नाम से मशहूर जिले के मुख्यालय की कई सड़कें भी चलने लायक नहीं हैं। घोसियाना होकर गुजरने वाले मार्ग में जलनिकासी की भी व्यवस्था नहीं है। इस कारण घोसियाने का पानी सड़क पर ही भरा रहता है।

कीचड़ सूखकर धूल के रूप में उड़ता है। सड़क किनारे बने मकानों दुकानों में दर समय इतनी धूल रहती है कि देखना मुश्किल हो जाता है।

Clipping-71

The clipping-71 of 4th November 2014 informs about the critical conditions of the district. It also informs about the careless behavior of Nagar Palika that after a so many complaint by the peoples no such action is taken the roads of the city is same as in the villages after the getting 5crore rupees from many schemes.

विकास योजनाओं में धाधली, कागजों पर जांच

Publish Date: Tue, 04 Nov 2014 05:42 PM (IST) | Updated Date: Tue, 04 Nov 2014 05:42 PM (IST)



ऊंचाहार, संवाद सहयोगी : रोहनिया विकास खंड के रायपुर गांव की विभिन्न विकास योजनाओं में धाधली की जांच करने वाली टीम ने अभी तक अपनी जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को नहीं दी है। जिससे दोषी लोगों के विरुद्ध आगे की कार्यवाई रुकी हुई है।

रायपुर गांव पंचायत में मनरेगा व इन्दिरा आवास में बड़े पैमाने पर अनियमितता का खुलासा सूचना का अधिकार के तहत हुआ था। गांव के शशंका पाण्डेय द्वारा सूचना के अधिकार तहत मागी गयी सूचना से तकरीबन बीस लाख रुपये की गड़बड़ी पायी गयी थी। जिसमें केवल मनरेगा के तहत सन 2010 से लेकर 2014 तक

बनवाए गए आठ खड़जा मार्गों में धाधली का आरोप है। यही नहीं इस गांव में एनटीपीसी द्वारा बनवाए गए एक खड़जा मार्ग का भुगतान मनरेगा से फर्जी अभिलेख लगाकर कर दिया गया था। एक अन्य खड़जा मार्ग जो सन 2010 में बनवाया गया था। उसका दोबारा भुगतान सन 2011.12 वित्तीय वर्ष में करवा लिया गया है। इसके अलावा इन्दिरा आवास के सोलह मामलों में गड़बड़ी पायी गयी है। कई इन्दिरा आवास दूसरे के बी पी एल क्रमांक पर अपने चचेतों को दे दिये गए हैं। मामले की शिकायत जब उच्चाधिकारियों को की गयी तो डीआरडीए के सहायक अभियंता एसके त्रिपाठी के नेतृत्व में दो सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया और जांच टीम ने तकरीबन बीस दिन पहले गांव पहुंचकर पूरे मामले की गहन छानबीन की है। जिसमें ग्रामीणों के सामने अधिकतर आरोप सही पाये गए हैं। अब ग्रामीणों को कार्यवाई का इंतजार है।

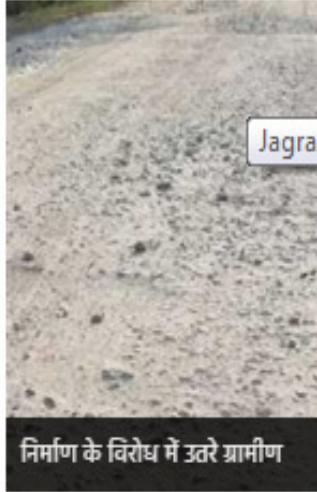
लेकिन जांच टीम ने अभी तक उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट नहीं सौंपी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जांच टीम से जब जांच रिपोर्ट मागी जाती है तो कोई न कोई बहाना करके मामले को टाल दिया जाता है। उधर जांच अधिकारी का कहना है कि कई बिन्दुओं पर जांच रिपोर्ट तैयार करनी है बीच में अवकाश के कारण व्यवधान आया है जांच रिपोर्ट शीघ्र ही उच्चाधिकारियों को सौंप दी जाएगी।

Clipping-72

The clipping-72 of 4th November 2014 is a big example on the role of newspaper for any one. In the clipping it is described that after getting RTI information regarding corruption in the MANREGA and Indira Awaas Yojna no such action is being taken by any one. In the clipping with a name of the person who puts the RTI provides the whole information of the corruption but such action is taken, the investigation are going on the papers only.

निर्माण के विरोध में उतरे ग्रामीण

Publish Date: Mon, 03 Nov 2014 09:38 PM (IST) | Updated Date: Mon, 03 Nov 2014 09:38 PM (IST)



शिवगढ़ : विकास क्षेत्र के संपर्क मार्गों के रिपेयरिंग में हो रही धाधली को लेकर क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। इसको लेकर क्षेत्रीय लोग विरोध में उतर आए हैं। विधायक से लेकर विभाग तक से शिकायत करके थक चुके ग्रामीणों ने सोमवार को जमकर की।

क्षेत्र के संपर्क मार्ग बाराबंकी सीमा बार्डर से देहली होते हुए मुराई का पुरवा तक 4 किमी व बेडारु से चन्द्रापुर संपर्क मार्ग 3.5 किमी में रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनवाया जा रहा संपर्क मार्ग देहली से मुराई पुरवा तक 4 किमी जिसकी लागत लगभग 30 लाख है। बेडारु रोड से चन्द्रा पुर तक 4 किमी की सड़क बन रही है। इसकी रिपेयरिंग राशि लगभग 35 लाख रुपये है, लेकिन इसमें मानक को दरकिनार कर केवल खानापूर्ति की जा रही है। देहली से मुराई पुरवा तक के

संपर्क मार्ग का कार्य पूरा हो चुका है। इसपर मानक के हिसाब से तारकोल न डालने को लेकर क्षेत्र के लोगों ने संपर्क मार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग पर धाधली का आरोप लगाते हुए जमकर नारे बाजी की। उनका कहना है कि रिपेयर के मानक के हिसाब से कार्य के किया गया तो जिलाधिकारी से शिकायत करेंगे।

सभा बेडारु के ग्रामीण सुबह 10 बजे चन्द्रापुर में रिपेयरिंग हो रहे संपर्क मार्ग पर पहुंच गए। मानक के हिसाब से तारकोल न डालने को लेकर लोगों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि संपर्क मार्गों के एक किमी मरम्मत में लगभग 10 लाख रुपया विभाग द्वारा स्वीकृत होता है, लेकिन दलाली और बंदरबांट के चलते ठेकेदार व सम्बन्धित अधिकारियों का पेट भरता है। इसके कारण एक तरफ सड़कों की मरम्मत होती है, तो दूसरी तरफ सड़क का उखड़ना शुरू हो जाता है। इसकी शिकायत क्षेत्रीय विधायक राम लाल अकेला से भी कि जा चुकी, लेकिन सड़क रिपेयरिंग में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है।

Clipping-73

The clipping-73 of 3rd November 2014 shows the demonstration of the villagers on the construction in the Shivagarh area. The aim of this protest was to inform the people about lapses in the road construction in which charcoals was not used properly. The newspaper as a medium of information depicts such important news for the betterment of the peoples.

266 करोड़ खर्च कर के भी नहीं मिटा अंधेरा

Publish Date:Thu, 06 Nov 2014 05:43 PM (IST) | Updated Date:Thu, 06 Nov 2014 05:43 PM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : सांसद सोनिया गांधी के प्रयास से जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के दो चरण पूरे हो चुके हैं। ढाई अरब से ज्यादा खर्च होने के बावजूद हजारों पुरवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी। जबकि काम कराने वाले मालामाल हो गए। पूरे धन का सदुपयोग हो जाता तो आज यह हालत न रहती। केंद्रीय योजनाओं में कांग्रेसियों का जोर ठेका हथियाने तक सीमित रहता है।

क्या है आरजीजीवीवाई

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की नींव 2004 में संप्रग सरकार बनने के बाद हुई थी। भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय पंत्रांक संख्या

44-19-2004-डी-आरई-18-51- 2005 में रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन को योजना संचालन के लिए पत्र लिखा था। 14 जुलाई 2004 को भारत सरकार और रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन के बीच एमओयू साइन हुए।

- इसका उद्देश्य 2012 तक पूरे देश के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाना था।
- सभी बीपीएल परिवारों को एक बत्ती का कने Jagran News
- गांवों के स्वास्थ्य उपकेंद्र, सीएचसी, पीएचसी, पंचायत घर, स्कूलों तक बिजली पहुंचाना।
- भविष्य की बिजली जरूरत को ध्यान में रखकर बिजली ढांचा तैयार करना।
- गांवों में कृषि सिंचाई, कोल्डचेन , एग्रो प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना ।
- हर ब्लॉक में कम से कम एक 33केवी उपकेंद्र

Clipping-74

The clipping-74 of 6th November 2015 has the whole details regarding the Rajiv Gandhi schemes of electricity. In the clipping it is mentioned that 266 crore of rupees are consumed but no such result is found the meaning is same that may be possibly a big corruption.

कागजों पर विकास की इबारत

Publish Date: Sat, 08 Nov 2014 08:53 PM (IST) | Updated Date: Sat, 08 Nov 2014 08:53 PM (IST)



कागजों पर विकास की इबारत

Jagran News

ऊंचाहार, संवाद सहयोगी: गावों में विकास कार्यक्रमों को लेकर बड़े-बड़े सरकारी दावों की जमीनी हकीकत क्या है, इसकी बानगी ऊंचाहार देहात ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले 30 गावों में देखी जा सकती है। लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित इन गावों में अभी तक विकास की ईंट भी नहीं रखी गई है। गावों की राजनीति के दावपेच में विकास उलझा हुआ है। फाड़लों के जाल से निकल कर गावों

तक विकास की रोशनी कितने साल में आएगी प्ाश्च अनुत्तरित है।

विश्व की 10 सबसे बड़ी विद्युत कंपनियों में शामिल एनटीपीसी के लिए मशहूर ऊंचाहार में विकास की सरकारी कल्पनाएं फाड़लों की जाल में उलझ गई है। सामान्य गांव क्षेत्रों की क्या कहे विकास असीम कल्पना के साथ मुख्यमंत्री द्वारा समाजवादी राम मनोहर लोहिया के नाम पर शुरू की गई महत्वकांक्षी लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना यहां दम तोड़ती नजर आ रही है। चालू वित्त वर्ष में लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के लिए चयनित तहसील क्षेत्र के 30 गावों में आठ महीने के दौरान केवल कागजों पर विकास की बातें हो रही हैं। इन गावों के लोगों को कायाकल्प की उम्मीद बंधी थी। अगले साल होने वाल ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर गावों में शुरू हुई राजनीतिक दावपेच ने अभी तक कोई भी विकास कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया है।

इन गावों का होना है विकास

ऊंचाहार देहात ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले 30 गावों में लोहिया ग्राम विकास योजना के तहत कार्य होने हैं ये गाव है पिपरहा, संकठा, खमरिहा, गढी, राजापुर, बरगदही, नउनहार, गौसपुर, मातादीन का पुरवा, जमुनिहाहार, मास्टरगंज, कजराबाद, नरवापार, चौहानन का पुरवा, छोटे मिया का पुरवा, बड़ा मिया का पुरवा, हसन गंज, नौधतलाल का पुरवा, गुलाम हसन का पुरवा, दुलीपुर, राठौरन का पुरवा, गड़रियन हार, अमलिहा का पुरवा आदि गाव है।

Clipping-75

The clipping-75 of 8th November 2014 informing about the critical condition of the Unchahar area in which development is trapped only on Papers but in reality no such work is started. The Newspaper is showing the reality of development work under Lohiya Gram Yojna to the government.

निकाली रैली, फैलाई जागरुकता

Publish Date:Wed, 12 Nov 2014 01:24 AM (IST) | Updated Date:Wed, 12 Nov 2014 01:24 AM (IST)



महाराजगंज क्षेत्र के जवाहर नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर जागरुकता रैली निकाली गई। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य जीपी मिश्रा ने हरी जंजी दिखाकर जागरुकता रैली को जगृत किया। सचालन संदीप त्रिचारी ने किया। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद के 126वें जन्म दिन पर विद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया। विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी जागरुकता रैली में भाग लिया। विद्यालय में शिक्षा के महत्व विषय पर निबंध लेखक प्रतियोगिता, बधाई संदेश प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, भावना प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। विद्यालय के विज्ञान शिक्षक संदीप त्रिचारी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन पर

प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक महान् क्रांतिकारी, देशभक्त, शिक्षा मर्मण के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। इतिहास शिक्षक अशोक कुमार व बिंदी शिक्षक डीपी विश्वकर्मा ने कविता के माध्यम से शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

Clipping-76

The clipping-76 of 12th November 2014 informs about the march on the occasion of National Children's day done by Jawahar National School to make people aware about importance of education and about the first education Minister in which students with the teachers was present.

कुपोषित बच्चों को संजीवनी देंगे डीएम-सीडीओ

Publish Date:Wed, 12 Nov 2014 01:24 AM (IST) | Updated Date:Wed, 12 Nov 2014 01:24 AM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता :

राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम के दौरान सूबे मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के हर डीएम और सीडीओ को दो-दो ग्राम पंचायतों के गोद लेने के निर्देशों को अमलीजामा रायबरेली जिले में पहनाना शुरू किया गया है। शासनादेश आ जाने के बाद जिले से चार ग्रामों को चयन मंगलवार को देरशाम किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अनूप कुमार ने उक्त ग्रामों के चयन में सभी ब्लकों के ग्राम सभाओं का आंकड़ा दो दिन पहले मांगा था।

ज्ञात हो कि हर जिले से दो-दो ग्राम सभाओं को डीएम और सीडीओ गोद लेंगे यह शासनादेश जारी हुआ था। इसके बाद जिले

से चार ग्राम सभाओं का चयन प्रारंभ किया गया।

रायबरेली जिले से अति कुपोषित ग्राम सभाओं का चयन मुख्य विकास अधिकारी अनूप कुमार ने किया है। इसके लिए इन्होंने जिले के हर ब्लक से 4-4 ग्राम सभाओं का चयन करते हुए कुल 72 ग्राम सभाओं का ब्योरा मंगवाया था।

Clipping-77

The clipping-77 of 12th November 2014 relates to the poor child. This news informs that the Instructions of CM of state are being taken seriously and according to the instructions details are desired by the concerned officers to start the work as soon as possible.

क्षेत्र पंचायत की बैठक में विकास रहा मुद्दा

Publish Date:Wed, 12 Nov 2014 01:24 AM (IST) | Updated Date:Wed, 12 Nov 2014 01:24 AM (IST)



डीह संवादसूत्र: विकास क्षेत्र के ब्लाक मुख्यालय डीह के मलिक मोहम्मद जायसी सभागार में मंगलवार को क्षेत्र पंचायत की बैठक की गयी जिसकी अध्यक्षता ब्लाक प्रमुख

विवेक सिंह ने की। बैठक में ब्लाक प्रमुख विवेक सिंह ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्रामप्रधानों को

संबोधित करते हुये कहा कि भारत सरकार व राज्य सरकार से जो

योजनायें चल रही है उनका लाभ पात्रों को दिलायें। बैठक के दौरान मऊ ग्राम सभा के विकास अधिकारी की शिकायत की गयी लोको को आवास मिल सके, बैठक में ग्राम प्रधानों ने पैतालिस हजार वाले आवासो की द्वितीय किस्त न जारी होने की समस्या बतायी जिस पर बीडीओ जंगबहादुर ने दिक्कतें जल्द दूर करवाने का भरोसा

Clipping-78

According to the clipping-78 above the block level elected members meet for the implementation of the various schemes of development by the state and central government. The matter related to the installment of housing schemes was discussed and reported by the newspaper. The role of newspaper persists strong in such kind of reporting.

कोर बैंकिंग से जुड़ा डाक घर

Publish Date: Mon, 17 Nov 2014 05:52 PM (IST) | Updated Date: Mon, 17 Nov 2014 05:52 PM (IST)



महाराजगंज संवाद सहयोगी :

महाराजगंज उपडाक घर में बैंकिंग सेवा की शुरुवात हो गई है। अब डाक घर के खाताधारक देश के किसी भी कोने में जमा निकासी कर सकते हैं। सोमवार को डाक अधीक्षक पी एन यादव ने दीप जलाकर सीबीएस सेवा का उदघाटन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुये अधीक्षक श्री यादव ने कहा कि अब खाताधारक अपने खाते का लेन देन भारत देश कि किसी भी सीबीएस डाक घर में कर सकते है। इस अवसर पर डाक निरीक्षक तारकेश्वर शुक्ला, सुशील कुमार बाजपेई, अरुण

कुमार, राकेश कुमार, छोटेलाल, विशंभर पाल, रामयश आदि लोग मौजूद रहे।

Clipping-79

Newspaper reported about various new innovations in public convenience by the postal department using IT for the access of user account from anywhere in the country. The clipping number 79 depicts the development in the fields of small scale banking.

जिले में विज्ञान प्रदर्शनी आज

Publish Date: Fri, 06 Feb 2015 09:05 PM (IST) | Updated Date: Fri, 06 Feb 2015 09:05 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता: प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डा. मनोज कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को शहर के एक होटल में पत्रकार वार्ता कर शनिवार को राजकीय इंटर कालेज रायबरेली के मैदान में आयोजित विज्ञान

Jagran News

पुरस्कार व प्रदर्शनी एवं मेला कार्यक्रम की रूप रेखा रखी। कबीना मंत्री कहा कि गत एक माह से विद्यार्थियों को कालेज आयोजित की गयी विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों सहित

प्राधानाचार्य व विज्ञान शिक्षकों को मिलाकर लगभग 400 लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें जनपद व राज्य स्तर की विभिन्न शोध प्रयोगशालायें, फि रोज गांधी पालीटेक्निक कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, एवं निफ्ट, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट सहित अनेको विद्यालय के छात्र-छात्राओं के विज्ञान माडल तथा विकास व कल्याण विभाग सहित लगभग 60 स्टाल लगाये जा रहे हैं। मुख्य आकर्षण ड्रोन का सजीव प्रदर्शन, सचल नक्षत्र शाला के माध्यम से दिन में तारे दिखाने, सेट लाइट माडल, जैव उर्वरक, एवं कीटनाशक तकनीकियों का सजीव प्रदर्शन किया जायेगा। उद्घाटन कैबनेट मंत्री डा. मनोज कुमार पाण्डेय करेंगे। विधान सभा के अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय के भाग लेने की संभावना है। इसमें सपा जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी रामबहादुर यादव, उपाध्यक्ष राम सेवक वर्मा, विभाग के संयुक्त निदेशक आईडी राम, रणधीर सिंह समन्वयक जिला विज्ञान क्लब रायबरेली, अंशू बाजपेयी प्रदीप मिश्रा, दिनेश रावत आदि उपस्थित रहे।

Clipping-80

Clipping no. 80 of Dainik Jagran Newspaper published on 6th February 2015 depicts the developmental initiatives taken by the local MLA. The occasion was science exhibition with a motto to aware public towards benefits of science in daily life and its role in development of human being.

जिले में पहुंची डीएपी की रैक

Publish Date: Sat, 07 Feb 2015 07:38 PM (IST) | Updated Date: Sat, 07 Feb 2015 07:38 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : प्रदेश सरकार ने जिले को इफको की एक रैक यूरिया व एक रैक डीएपी पिछले सप्ताह भेजी थी। इसको जिले की समितियों में भेजा गया। किसान समितियों से यूरिया उठा लें।

जिला कृषि अधिकारी एसके पांडेय ने बताया कि इफको की 2200 मीट्रिक टन यूरिया पिछले सप्ताह आ गई है। इसके अलावा एक रैक डीएपी भी आई है। इसे बफर गोदाम में भरा गया है। इफको की 2200 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण सहकारी समितियों को गया है। जिले में यूरिया की कोई कमी नहीं है। निजी दुकानदार के कहने पर उसके साथ अन्य कोई खाद न लें।

जिला कृषि अधिकारी एसके पांडेय ने कहा कि किसान गेहूं की सिंचाई रोक दें। नमी कम होने के बाद ही यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। बरसात से खेतों में पानी भर गया हो, उसे तत्काल निकाल दें। पानी सूखने के बाद ही किसान यूरिया का प्रयोग करें।

घोल का छिड़काव करें

किसान भाई मौसम साफ होने के बाद यूरिया छिड़कने की जगह यूरिया का मशीन से स्रो करें। इससे यूरिया की मात्रा कम लगेगी असर ज्यादा रहेगा। गीली जमीन में किसान खेत में न जाएं और न ही यूरिया का छिड़काव करने की कोशिश करें। अभी मौसम खराब होने के कारण कुछ दिन इंतजार कर लें।

Clipping-81

Clipping no. 81 of Dainik Jagran Newspaper published on 7th February 2015 reported that the fertilizers were supplied to the farmers of the district which is a clear indication that the production of food grains are considered as special items and for the welfare and support of the villagers this action reported by the newspaper will help at large.

एक दशक बाद भी नहीं बदलीं तस्वीर

Publish Date: Sun, 07 Sep 2014 05:58 PM (IST) | Updated Date: Sun, 07 Sep 2014 05:58 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : विकास की राह देखते-देखते एक दशक बीत गया, लेकिन देवानंदपुर मोहल्ले की तस्वीर नहीं बदली। यहां जाने वाले मुख्य मार्ग के साथ ही गलियों में टूटे खड़जे दिखते हैं। जल निकासी की व्यवस्था का आलम यह है कि बन रहा नाला अधूरा पड़ा। ऐसे में लोगों को अपने घरों में आने-जाने के लिए लकड़ी का पुल बनाया है। मार्ग प्रकाश की व्यवस्था ध्वस्त है। वहीं बिजली की लाइनें अभी तक खुली पड़ी है। कई घरों में बिजली कनेक्शन के लिए बल्लियों के सहारे लाइन खींची गई है। देवानंदपुर के लोगों को बारिश की बात सोचकर डर लगता है। इसका कारण ये है कि भले ही बारिश लोगों के लिए सुहानी होती है लेकिन यहां के लोगों के लिए जल निकासी न होने के कारण पानी गलियों और आसपास के इलाके में भर जाता है।

यहां के राजन ने बताया कि शुरु से ही यहा कच्ची गलिया और जलभराव देखते आए हैं। एक दशक पहले ईंटों का खड़जा डलवाया गया तो पक्के रास्ते और जल निकासी को लेकर विकास की उम्मीद जगी। लेकिन कोई अगला काम नहीं हुआ और समय बीतने पर यह खड़जा भी टूट गया।

सुनील कहते है कि कुछ दिन पहले जल निकासी के लिए नाला बनाया गया था। जो अधूरा छोड़ दिया गया पेयजल व्यवस्था के लिए लगे हैंडपंप खराब पड़े है। सफाई कर्मी पंद्रह दिन में एक बार ही आता है। इसलिए मजबूरन खुद नालियों की सफाई करनी पड़ती है।

सुरेश कुमार शुक्ला कहते है कि मार्ग प्रकाश व्यवस्था नहीं है रात के समय आने वाले लोगों के खासी परेशानियां होती है। कई विद्युत पोल टूटे हुए है, इस कारण बल्लियों के सहारे विद्युत कनेक्शन लाइन डाले हुए है।

यहां की मिथलेश मिश्रा कहती है कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। घरों के सामने गंदगी व कूड़ा जमा रहता है। सभासद के घर के बगल में कूड़े के ढेर जमा है। ऐसे में वह मोहल्ले का विकास व सफाई क्या करायेगी।

Clipping-82

Clipping no. 82 of Dainik Jagran newspaper published on 7th September 2014 was a story done by the journalist depicting the development story of decade and reporting about poor pace of work sanctioned by the government under various schemes. Newspaper reported that electricity lines were damaged, roads are broken severely and water logging is a big problem. Various residents were interviewed by the reporter and every person was of the view

that development was never considered by the political representative to upgrade the life of locals.

इसी माह चालू होंगे नए विद्युत उप केंद्र

Publish Date:Wed, 10 Sep 2014 01:04 AM (IST) | Updated Date:Wed, 10 Sep 2014 01:04 AM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : प्रदेश सरकार की तहसील मुख्यालयों को अलग 33केवी उप केंद्र से जोड़ने की मंशा मूर्त रूप लेने जा रही है। सितंबर माह के अंत तक डलमऊ और महाराजगंज तहसील मुख्यालय नए उप केंद्रों से जुड़ जाएंगे। ऊंचाहार तहसील मुख्यालय साल के अंत तक नए उप केंद्र से जुड़ पाएगा। यहां निर्माण काम प्रगति पर है।

पिछले साल प्रदेश सरकार ने तहसील मुख्यालय को अलग उप केंद्र से जोड़ने के लिए प्रस्ताव मांगे

थे। इसके साथ जिलाधिकारी से उप केंद्र निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया था। यहां से लालगंज, डलमऊ, महाराजगंज, ऊंचाहार व सलोन तहसील के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे। इसके बाद सरकार ने नए उप केंद्र निर्माण के लिए स्वीकृति दी। सभी तहसीलों में उप केंद्र निर्माण का काम चल रहा है।

Clipping-83

Clipping no. 83 of Dainik Jagran Newspaper published on 10th September 2014 reported a plan of government to segregate the electrical sub stations for every tehsil. The work related to the electrical facilities to each tehsils was started in Lalganj, Dalmau, Maharajganj, Unchahar and Salon. Newspaper

reported that district magistrate has provided the land for such development in the district.

लालगंज में बनेंगे नए तालाब

Publish Date: Sat, 25 Oct 2014 06:51 PM (IST) | Updated Date: Sat, 25 Oct 2014 06:51 PM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : सरेनी ब्लाक में जल संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में जिले की सरकारी मशीनरी ने नए कदम उठाए थे कि अब लालगंज ब्लाक में भी भूजल स्रोतों को बेहतर करने की कार्ययोजना जिला प्रशासन ने बनाई है। जल्द ही लालगंज तहसील क्षेत्र में नए तालाबों की खुदाई कराई जाएगी। प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि जल्द ही लालगंज में तालाबों का चयन किया जाएगा।

Clipping-84

The clipping-85 of 25th October 2014 informs about the steps taken by the government to avoid flood in the Sareni block and at the same DM says that ponds will be selected very soon. The step taken by local administration will for sure help the environment in the area of water conservation.

माइक्रो कामधेनु योजना का हुआ साक्षात्कार

Publish Date: Fri, 28 Aug 2015 05:48 PM (IST) | Updated Date: Fri, 28 Aug 2015 05:48 PM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल माइक्रो कामधेनु योजना में दूध डेयरी खोलने के लिए कलेक्ट्रेट के बचत भवन में मुख्य विकास अधिकारी की अगुवाई में योजना के आवेदकों का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, परियोजना निदेशक, लीड बैंक प्रबंधक ने भी आवेदकों से सवाल किए। चयनित लोगों को बाद में सूचना भेजी जाएगी।

शुक्रवार को सीडीओ अनूप श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आवेदकों का साक्षात्कार शुरू हुआ। यह अपराह्न चार बजे तक चलता रहा। माइक्रो कामधेनु योजना की लागत 27.99 लाख है। इसमें 25 गाय भैंस का पालन किया जाता है। आवेदक को 6.70 लाख रुपए की

मार्जिन मनी जमा करनी होगी। इसके अलावा आवेदक को डेयरी खोलने के लिए पानी की व्यवस्था व शेड का निर्माण अपने संसाधन से करना होगा। आवेदक के पास कम से कम एक बीघे जमीन भी होनी चाहिए। सरकार की कामधेनु योजना सवा करोड़ व मिनी कामधेनु योजना 52 लाख की होने के कारण आरोप लग रहा था कि सरकार केवल बड़े किसानों के लिए योजना चला रही है। इसलिए सरकार ने 25 जानवरों वाली माइक्रो कामधेनु योजना की शुरुआत इसी साल की है। मुख्य विकास अधिकारी ने आवेदकों की दूध व्यवसाय की जानकारी, मार्जिन मनी का इंतजाम, दूध बेचने का बाजार, बैंक की किस्त भरने आदि सवाल किए। इसमें कई आवेदकों ने संतोषजनक जवाब दिए। जबकि कई जवाब देने में संकोच कर रहे थे।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. केके चौधरी ने आवेदकों से पशु पालन का अनुभव, रखरखाव के संबंध में प्रश्न पूछे। परियोजना निदेशक इंद्रसेन सिंह, लीड बैंक प्रबंधक मनोज सिन्हा ने भी युवाओं से जानकारी हासिल की। सुबह दस बजे ही कई पुरुष व महिला आवेदक आ गए थे।

Clipping-86

Clipping no. 86 of Dainik Jagran Newspaper published on 28th August 2015 reported implementation and initiation of micro dairy scheme in the district. The applicants seeking benefit under this scheme were interviewed by the district magistrate in presence of CDO. The expected budget of this scheme was rupees 27.99 lacks.

खेत की मिट्टी लेकर आने वाले का मृदा परीक्षण मुफ्त

Publish Date: Sat, 08 Nov 2014 06:51 PM (IST) | Updated Date: Sat, 08 Nov 2014 06:51 PM (IST)



रायबरेली, जागरण संवाददाता : खेती से ज्यादा उपज लेने के लिए मृदा परीक्षण जरूरी है। इससे खेत में मौजूद मुख्य पोषक तत्वों की जानकारी हो जाती है। जिन तत्वों की कमी है सिर्फ उनका संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इससे फसल की लागत घटती है और पैदावार बढ़ती है।

खेतों का मृदा परीक्षण दो प्रकार का होता है। एक मुख्य पोषक तत्वों की जांच तथा दूसरी सूक्ष्म तत्वों की जांच। उप निदेशक कार्यालय पर खुद मिट्टी लेकर आने वाले लघु व सीमांत किसानों के मुख्य पोषक तत्वों की जांच निशुल्क क जाती है। ब्लाक में जमा करने पर एक जांच का सात रुपये शुल्क देना पड़ता है।

उप कृषि निदेशक डा. अजय कृष्ण ने बताया कि मिट्टी के सूक्ष्म तत्वों की जांच का शुल्क तीस रुपये निर्धारित है। किसानों को सूक्ष्म तत्वों की जांच करानी चाहिए, रिपोर्ट के अनुसार ही आवश्यक तत्वों से संबंधित उर्वरक खेत में डालना चाहिए। बिना जांच के उर्वरक डालने पर खर्च की बरबादी होती है। उन्होंने कहा कि किसान अधिक से अधिक किसान जैविक खादों का प्रयोग करें। जिससे कम लागत में अच्छी पैदावार हो सके और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो।

रबी सीजन में गेहूं बुआई का समय शुरू हो गया है। किसान पहले मिट्टी परीक्षण करा लें। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही कमी वाले रासायनिक तत्वों का प्रयोग करें।

Clipping-87

The clipping-87 of 8th November 2014 reported the initiatives taken by agriculture department and soil sample taken by the farmers were tested free of cost by the department. The basic properties of the soil were demonstrated to the farmers and importance of the micro organism was informed to the present. The adequate proportion of fertilizers used in field crop was also told to the farmers.

प्रधानों को विकास के लिए मिलेंगे 11.70 करोड़

रायबरेली

अमर उजाला ब्यूरो

मंगलवार, 22 दिसंबर 2015

Updated @ 11:40 PM IST

हालांकि नए ग्राम प्रधानों के खुशखबरी है। जिला पंचायतराज विभाग नए ग्राम प्रधानों को विकास कार्यों के लिए 11 करोड़ 70 लाख दे रहा है। यह किस्त अगस्त व नवंबर में ही आ गई थी।

लेकिन पंचायत चुनाव के कारण यह धनराशि ग्राम पंचायतों को नहीं भेजी गई थी। ग्राम पंचायतों को 80 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक भेजे जाएंगे।

ग्राम पंचायतों में पक्के कार्यों के साथ ही पेयजल की व्यवस्था समेत अन्य जरूरी कार्यों के लिए जिला पंचायतराज विभाग की ओर से राज्य वित्त एवं तैरहवें वित्त के तहत बजट दिया जाता है।

ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष में चार किस्तें दी जाती है। पहली किस्त मई में ही ग्राम पंचायतों को भेज दी गई थी। पांच करोड़ 85 लाख की दूसरी किस्त अगस्त में आ गई थी।

- > पीएम से मिले प्रदेश के चारों सांसद, उठाई ये मांग
- > ...हर हिंदुस्तानी को याद रखना पड़ेगा

लेकिन पंचायत चुनाव की शुरुआत होने के कारण ग्राम पंचायतों के खातों यह धनराशि नहीं भेजी गई। तीसरी किस्त भी नवंबर में पांच करोड़ 85 लाख रुपये की आ गई है।

पंचायत चुनाव के बाद 989 ग्राम पंचायतों में नए प्रधान चुने गए हैं। 26 दिसंबर को समितियों का गठन भी पूरा हो जाएगा। जिसके बाद ग्राम पंचायतों में विकास का कार्य आरंभ होगा।

खास बात यह कि 80 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों के खातों में फूटी कौड़ी तक नहीं है। इससे नए ग्राम प्रधान हैरान भी हैं, लेकिन जिला पंचायतराज विभाग ने नए प्रधानों के लिए बजट पहले से ही रोके है।

दोनों किस्त एक साथ ग्राम पंचायतों को भेजी जाएगी। करीब 11 करोड़ 70 लाख रुपये ग्राम पंचायतों को भेजे जाएंगे। 18 ब्लॉकों की क्षेत्र पंचायत निधि के खातों से विकास कार्य कराने के लिए दो करोड़ 34 लाख रुपये दिए जाएंगे।

Clipping-1

The News Clipping-1 shown above, taken from Amar Ujala, 22nd December 2015, informs about the financial support that will be provide by the District Gram Panchayati Raj department to the heads of the village for the development. It is also informs that four installments are already disbursed by the department to the villages and this is the third installment that was not used because of the election in the area. According to the news all Gram Panchayati will use the money for the development.

सांसद निधि से विकास के लिए मिले रु पांच करोड़

रायबरेली

अमर उजाला ब्यूरो

शुक्रवार, 1 जनवरी 2016

Updated @ 11:06 PM IST

सांसद निधि से जिले में विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपये मिले हैं। सांसद सोनिया गांधी और राज्यसभा सदस्य कैप्टन सतीश शर्मा की निधि को ढाई-ढाई करोड़ मिले हैं। इसमें राज्य सभा सदस्य को तीन साल बाद निधि में बजट मिला है।

बजट मिलने के बाद सांसद से कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो प्रस्ताव पहले आए थे, उनमें धन आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में सांसद सोनिया गांधी को निधि से विकास कार्य कराने के लिए पहली किस्त के रूप में ढाई करोड़ रुपये मिले हैं।

हालांकि सांसद निधि के लिए कई पत्र भारत सरकार को लिखा गया था, जिसके बाद पहली किस्त जिले को मिली है। राज्यसभा सदस्य कैप्टन सतीश शर्मा को कई वर्ष से विकास कार्यों के लिए निधि नहीं मिली है। वर्ष 2013-14 की पहली किस्त के रूप में ढाई करोड़ रुपये दिए गए हैं।

करीब दो करोड़ के प्रस्ताव पहले से डीआरडीए को मिले थे। अन्य बजट के सापेक्ष भी सांसद से कार्यों के प्रस्ताव व अनुमोदन मांगे गए हैं। परियोजना निदेशक इंद्रसेन सिंह ने बताया कि सांसद निधि में बजट आया है। सांसद से प्रस्ताव व अनुमोदन आने के कारण कार्य आरंभ कराए जाएंगे।

Clipping-2

The clipping-2 of 1st January 2016 in Amar Ujala informs about the first installment given by the government to the Member of Parliament in the District for the welfare and development. The clip also depicts that after a long period DRDA received proposals of rupees two crore related to the development work in the district. It is clearly indicated that the provision of funds for the district was adequate.

435 करोड़ की सीवरेज परियोजना को केंद्र की हरी झंडी

रायबरेली

अमर उजाला ब्यूरो

मंगलवार, 12 जनवरी 2016

Updated @ 11:58 PM IST

नगर पालिका परिषद के बाशियों को सीवर की समस्या से जल्दी ही निजात मिल जाएगी। जल निगम की प्रस्तावित सीवरेज परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है।

इसके लिए 435 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर लिया गया है। इसके तहत शहर के सभी मोहल्लों की सीवर लाइन, चेंबर के अलावा जगह-जगह सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आदि कार्य कराए जाएंगे।

पहले फेज में कार्य के लिए जल्द ही टेंडर निकाले जाएंगे। इससे लोगों को समस्या से निजात मिल सकेगी। नगर पालिका परिषद के 31 वार्ड में करीब 250 मोहल्ले हैं।

इनकी कुल आबादी एक लाख 91 हजार 56 है। वर्तमान में सीवर की समस्या से नागरिकों को दो-चार होना पड़ रहा है। करीब 70 फीसदी क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं पड़ी है।

वहीं पुरानी सीवर लाइन जर्जर हो चुकी है। साथ ही उसकी क्षमता भी कम है। ऐसे में सीवर के ओवरफ्लो होकर सड़क पर गंदा पानी भरता है।

सभी मोहल्लों में सीवर डालने के लिए लेकर जल निगम की ओर से सीवरेज परियोजना का मसौदा तैयार कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजा गया था।

हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से रायबरेली नगर पालिका परिषद का 'अमृत योजना' में चयन कर लिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश जल निगम द्वितीय लखनऊ की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है।

सीवरेज परियोजना के लिए 435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शहर क्षेत्र में सीवर लाइन को दुरुस्त करने के लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है।

इसके तहत सभी वार्ड में करीब 268 किमी सीवर लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही करीब 82 हजार कनेक्टिंग चेंबर बनेंगे। जरूरत के मुताबिक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा।

नगर पालिका परिषद के चेयरमैन इलियास ने बताया कि शहर में सीवर की समस्या काफी बड़ी है। 'अमृत योजना' के तहत शासन स्तर से मंजूरी मिल चुकी है।

> अब आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के पास मिली पाकिस्तानी करंसी

> चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पायलटों की ट्रेनिंग के लिए बनेगा सेंटर

Clipping-3

The clipping-3 of Amar Ujala 12th January 2016 brings happiness by getting news about the provision of funds for sewerage of the area by the central government. The government released fund to repair old sewer plants so that peoples who are facing problem in the area will get some relaxed. Water department got 435 crore for this and will start work for every locality just like sewage line treatment and many more. The clipping have details about how much money will be spend on the whole work and the Amrit Yojna' for which approval from the government has been obtained.

'अमर उजाला' और 'मैक्स ब्लॉक्स' के संयुक्त तत्वावधान में होगी पर्यावरण चौपाल

रायबरेली
अमर उजाला ब्यूरो

सोमवार, 18 जनवरी 2016
Updated @ 11:58 PM IST

साल दर साल खराब पर्यावरण के बढ़ते खतरे ने लोगों की मुस्किलें बढ़ाई हैं। न सिर्फ लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, बल्कि मौसम में भी परिवर्तन हुआ है। हालात यही रहे तो सांस लेना तक दुश्वार हो जाएगा।

ऐसे में सुखद जीवन जीने लायक धरती बनाने की मुहिम का आगाज होने जा रहा है। 'अमर उजाला' और 'मैक्स ब्लॉक्स' के संयुक्त तत्वावधान में 21 जनवरी को 'अमर उजाला पर्यावरण चौपाल' का आयोजन होगा।

जहां हम सब मिल बैठकर साफ-सुथरा पर्यावरण बचाने पर विचार करेंगे। कचहरी रोड स्थित दीप पैलेस निकट एचडीएफसी बैंक के सामने पूर्वाह्न 11.30 बजे होने वाली इस चौपाल में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ही निर्माण कार्य से संबंधित लोग भी शिरकत करेंगे।

- > चौपाल में स्वास्थ्यकर्मियों की खामियां मिलीं
- > चमक उठा सरकारगढ़ का सचिवालय, चौपाल 20 को

इसमें पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए पर विचार किया जाएगा, ताकि धरती पर जीवन के अस्तित्व को जारी रखने के लिए प्रकृति का संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।

डीएम सुर्यपाल गंगवरी ने कहा कि अमर उजाला की ओर से आयोजित की जाने वाली पर्यावरण चौपाल एक सराहनीय कदम है। पर्यावरण खराब हो रहा है।

ऐसे में हर व्यक्ति को बैठकर पर्यावरण को बचाने के लिए निश्चित तौर से विचार करना चाहिए। अमर उजाला की इस पहल से लोग आगे आएंगे, जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिल सकेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रायबरेली डॉ. एके सिंह ने कहा कि निश्चित तौर से देखा जाए तो पर्यावरण का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में धरती को हरा भरा बनाने की जरूरत है।

अमर उजाला की ओर से इस कार्य की पहल किया जाना वाकई में एक अच्छा प्रयास है। सब लोग मिलकर बैठकर विचार करेंगे तो निश्चित तौर से ऐसी बातें सामने आएंगी, जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिल सकेगी।

एंड्रॉइड ऐप पर अमर उजाला पढ़ने के लिए क्लिक करें. अपने फ़ेसबुक पर अमर उजाला की खबरें पढ़ना हो तो यहाँ क्लिक करें.

Clipping-4

The Clipping-4 of 18th January 2016 is to inform about importance of Environment and how to secure the environment. With this it also depicted that the positive initiatives has been taken by the Amar Ujala in collaboration with 'Max Blox' to secure environment. In the clipping it is mentioned that how every day human beings are neglecting environment in various ways and how to instant measures have to be initiated do something to secure environment. The Amar Ujala and 'Max Blox' is planning to organize a joint action for environment, the initiative was appreciated by the district of the district.

लखनऊ, शुक्रवार, 27 नवंबर 2015

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ₹ 766.50 करोड़ की योजना मंजूर

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्य सचिव आलोक कुमार ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 766.50 करोड़ रुपये की फिले बजटी अतिरिक्त राशि की अनुसूचक (सर्वांगीण) कार्य योजना का अनुमोदन दे दिया है। इसे तत्काल भारत सरकार के लिए व्यय है।

मुख्य सचिव गुरुवार की राखी भवन स्थित अपने कार्यालय कम के सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उच्च स्तरीय शासकीय कार्य 16वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्धारित विकास कार्यक्रम से संबंधित योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। इसके लिए सभी ब्लॉक स्तरीय कोऑरडिनेट मॉड्यूल पर इलेक्ट्रॉनिक्स नेबर्स डेटिलीनेंस नेटवर्क दुरुस्त किया जाए। कोऑरडिनेट मॉड्यूल पर इलेक्ट्रॉनिक्स नेबर्स डेटिलीनेंस नेटवर्क की प्रेरणा

मुख्य सचिव ने दी अनुसूचक कार्ययोजना को पेश योजना के निर्देश

मिशन के राज्य स्तरीय ब्लॉक विषय की दिशा

में तीन चरणों में लागू किया जाएगा। इसके पहले चरण में आठ जनपदी लखनऊ, आगरा, फैजाबाद, पंजाब, कानपुर, गौधुमपुर, बदायूं एवं बाराबंसी में आवश्यक उपकरण खरीदे जा चुके हैं।

अनुसूचक कार्य योजना में प्रेरणा में 100 एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत 200 और एम्बुलेंस के लिये भी प्रस्ताव पेशा जा चुका है। उन्होंने राष्ट्रीय बजट स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बजटी में वृद्धि दी। भाषा जरी पर चर्चा उपलब्ध कराने के लिए 200 रुपये प्रति चर्चा की दर से कुल 2 करोड़ रुपये की राशि जनपदी की तत्काल अनुमोदन कर पंजाब की चर्चा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

Clipping-5

The clipping-5 of 27th November 2015 is to inform that rupees 766.50 crore passed has been sanctioned under the scheme of National Health Mission. The funds will be spending for the betterment and development in health sector so that directly benefit the people of the area.

64 गांवों में 10 हजार प्रसाधन कक्ष बनवाएंगे दूत

शनिवार, 29 नवंबर 2014

Raebareli

Updated @ 5:30 AM IST

रायबरेली। पतित पावनी गंगा नदी को साफ करने से पहले किनारे बसे 27 गांवों के साथ ही 37 लोहिया गांवों में स्वच्छता दूत 10 हजार से अधिक प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराएंगे। दूत बने सफाई कर्मचारी निर्मल भारत मिशन के तहत गांवों के सभी घरों में प्रसाधन बनवाने के साथ ही उनके उपयोग के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे। इसके बदले में स्वच्छता दूतों को प्रति व्यक्ति को जागरूक करने पर दो-दो सौ रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले चरण में जिले के 64 गांवों को योजना के तहत चयनित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा पर गंगा के पुनर्जीवन व विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गंगा कटरी के क्षेत्रों के गांवों की दशा सबसे खराब है। खुले में नित्यक्रिया होने के कारण गंगा किनारे गंदगी रहती है। इसी के साथ ही साफ सफाई के भी बंदोबस्त नहीं हैं। प्रदेश सरकार ने गंगा किनारे बसे गांवों में स्वच्छता सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया है। प्रयास को सफल करने के लिए गंगा किनारे गांवों में स्वच्छता कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। लोहिया गांवों व कटरी के गांवों में तैनात सफाई कर्मियों को स्वच्छता दूत का नाम भी दे दिया गया है। ये दूत गांवों में लोगों को प्रसाधन निर्माण और उसके उपयोग के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा दो महीने तक उन्हें पर्यवेक्षण भी करना होगा। यदि इसमें सफल होंगे तो उन्हें प्रति केस दो सौ रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। दूतों को गांवों को साफ सुथरा रखने के संबंध में अन्य कार्य भी करने होंगे। निर्मल भारत मिशन के तहत जिले के 64 गांवों के 10297 घरों में स्वच्छता दूत प्रसाधन निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। उन्हें सरकार की मंशा की भी जानकारी देंगे। इसमें गंगा किनारे 27 गांवों में 5429 और लोहिया गांवों में 4868 प्रसाधनों का निर्माण होगा।



Clipping-6

The clipping-6 of 29th November 2014 is the news informing the readers about central scheme of financial assistance to district which will be used for development of sanitation that will be useful for Ganga cleaning Programme. With the help of peoples residing nearby areas and within the Ganga river banks the initiative will be implemented. It is said that for this step sanitation facilities will be developed by the State government. It's a clear indication that development initiatives have been taken by the government and people was well aware by the help of newspapers.

होम	समाचार	आपका शहर	राज्य	खेल	टेक वर्ल्ड	ऑटो वर्ल्ड	मनोरंजन	18+	से
ब्लॉग	ज़रा इधर भी	नौकरी	क्राइम ब्यूरो	कारोबार	लाइफस्टाइल	विचार	फोटो गैलरी	Games	

City > Raebareli

तीन तहसीलों को मिली बिजली उपकेंद्रों की सौगात

मंगलवार, 9 दिसंबर 2014

Raebareli

Updated @ 5:30 AM IST

रायबरेली। जिले के ऊंचाहार, डलमऊ और महाराजगंज तहसील मुख्यालयों में सोमवार को नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण हुआ। ऊंचाहार में काबीना मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने लोकार्पण किया। वहीं महाराजगंज में सपा विधायक रामलाल अकेला और डलमऊ में सरेनी विधायक देवेन्द्र प्रताप सिंह ने लोकार्पण किया।

ऊंचाहार प्रतिनिधि के अनुसार, जलालन हार खोजनपुर में आयोजित लोकार्पण समारोह में काबीना मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजली सुधार के लिए जो कदम उठाए, वह इससे पहले कभी नहीं हुए। प्रमुख कस्बों की आपूर्ति सुधारने के लिए तहसील मुख्यालयों पर नए उपकेंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है, तो वहीं वर्ष 2016 से गांवों को 18 और शहरों को 20-22 घंटे बिजली देने की तैयारी चल रही है।

डीएम महेंद्र कुमार ने कहा कि बीती गर्मी में बिजली की जो समस्या रही, उपकेंद्रों के बनने के बाद उससे छुटकारा मिल जाएगा। एसडीएम सत्येंद्रनाथ शुक्ला, आशीष तिवारी, राम बहादुर यादव, जगदेव प्रसाद, अधीक्षण अभियंता अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि अब आम उपभोक्ताओं को आसानी से बिजली मिल सकेगी। डलमऊ प्रतिनिधि के अनुसार, महुआहार गांव में बिजली उपकेंद्र का लोकार्पण करते हुए सरेनी विधायक देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार जो कार्य कर रही है, उससे आने वाले समय में जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश से ही बिजली संकट दूर हो जाएगा। उपजिलाधिकारी भूपेंद्र मिश्रा, बीडीओ चंद्रपाल, एक्सईएन विवेक खन्ना, कंचन श्रीवास्तव, बृजेश दत्त गौड़ आदि मौजूद रहे। महाराजगंज प्रतिनिधि के मुताबिक, जिहवा गांव में सपा विधायक रामलाल अकेला ने उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इससे अब लोगों को आसानी से बिजली मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि शिवगढ़ के ओसाह में 50 करोड़ रुपये की लागत वाला 220 केवीए के पारेषण केंद्र को मंजूरी मिल चुकी है। महाराजगंज में चंदापुर, शिवगढ़ में ओसाह व बछरावां के बिशुनपुर में भी 33/11 के नए उपकेंद्र स्वीकृत हो गए हैं। डीएम-एसपी के अलावा एसडीएम राकेश गुप्ता, अधिशासी अभियंता अशोक कुमार, जगदीश त्रिपाठी, माताफेर सिंह, प्रभात साहू मौजूद रहे।



1

Clipping-7

Clipping-7 of 9th December 2014 will bring a hope to the residents of the district which informs about selection of three tehsil in the district for the establishment of sub-stations of electricity. For the project cabinet minister announced that in the year 2016 all villages will get up to 18 hours of electricity supply and city area of Raebareli will be given 20-22 hours of electricity. One of the local MLA praised this action by the government and expressed that it will resolve the pending request of the residents.

विकास कार्यों को परखेंगे प्रमुख सचिव

गुरुवार, 11 दिसंबर 2014

Raebareli

Updated @ 5:30 AM IST

रायबरेली (ब्यूरो)। ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव लोहिया गांवों की जमीनी हकीकत को जांचने के लिए 12 दिसंबर को दो दिवसीय दौरे पर आएंगे। पहले दिन बचत भवन में विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद शहर के सरकारी दफ्तरों में पहुंचकर कर्मचारियों व अधिकारियों की कार्यशैली को जांचेंगे। 13 दिसंबर को भी कई अन्य लोहिया गांवों में विकास की प्रगति को भी जांचेंगे।

प्रमुख सचिव का कार्यक्रम आने के बाद कागजी खानापूरी करने का काम शुरू हो गया है। खासकर लोहिया गांवों में अधूरे कार्यों को पूरा कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। बचत भवन में होने वाली बैठक में गाज गिरने से बचने के लिए भी अधिकारी काम को निपटाने में जुट गए हैं। डीएम ने सभी अधिकारियों को आदेश जारी करके कार्यों को पूरा करने के आदेश दिए हैं।

लोहिया गांवों में तकनीकी कार्यों की जांच के लिए भी डीएम ने दो टीमों गठित कर दी हैं। ये टीमों प्रमुख सचिव के साथ रहेंगी और उनका निर्देश मिलने के बाद कार्यों की जांच करके उन्हें स्थिति से अवगत कराएंगी। उधर, ब्लॉकों में लोहिया गांवों की दशा को सुधारने का काम भी शुरू हो गया है। डीडीओ आरएन सिंह का कहना है कि सभी बीडीओ को लोहिया गांवों से संबंधित कार्यों को पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

Clipping-8

The clipping-8 of 11th December 2014 is giving information that principal secretary of Rural Development is planning to visit district on 12 of December to observe the development work done in Lohiya Villages. The one of the motto to judge the work patterns of concerns. The report will be prepared accordingly about the how much work is done by the department. After hearing this news the whole department is engaged to complete all the work assigned to them.

‘नई किरण’ से साक्षर बनेंगे कैदी

गुरुवार, 11 दिसंबर 2014

Raebareli

Updated @ 5:30 AM IST

रायबरेली। साक्षर भारत मिशन के तहत जिला जेल में बंद कैदियों व बंदियों को साक्षर किया जाएगा। साक्षर करने के लिए नई किरण नाम की किताब भी आ गई है। सभी 47 कैदियों और बंदियों में किताबें वितरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किताब को पढ़ने के बाद कैदियों की परीक्षा आगामी मार्च महीने में कराई जाएगी। परीक्षा पास करने के बाद ही उन्हें साक्षर माना जाएगा।

साक्षर भारत मिशन के तहत जिले में निरक्षरों को साक्षर बनाने का काम किया जा रहा है। गांवों में प्रेरक निरक्षरों को साक्षर बना रहे हैं। जेल में भी बंद कैदियों को भी साक्षर करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान समय में जिला जेल में 47 कैदी व बंदी ऐसे हैं, जो निरक्षर हैं। इन्हें साक्षर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कैदियों को साक्षर बनने के लिए केंद्र से किताब भी आ गई है।

बेसिक शिक्षा विभाग किताबों के वितरण के लिए जेल प्रशासन को पत्र भेजा है। जल्द ही नई किरण नाम की किताब जेल पहुंचेगी और निरक्षरों को साक्षर बनाने में सहयोग देगी। चार महीने पढ़ने के बाद आगामी मार्च महीने से साक्षरता की परीक्षा होगी। परीक्षा पास होने के बाद निरक्षर कैदियों-बंदियों को साक्षर होने का प्रमाणपत्र दिया जाएगा। परीक्षा पास न होने पर दोबारा उन्हें पढ़ाई करके परीक्षा पास करनी होगी। बीएसए संदीप चौधरी ने बताया कि किताबें आ गई हैं। जल्द उनका वितरण कराया जाएगा।



Clipping-9

The clipping-9 of 11th December 2014 is predicting the development of the prisoners in the jail of district. This clipping informs that a new book will be launched for the prisoners to provoke them to develop positive changes in their behavior. As well as it also informs that there are 47 prisoners who are illiterate and to educate them this step has been initiated. BSA informed that books will be distributed to the prisoners very soon.

स्वास्थ्य विभाग में दो दिन में 54 लोगों को मिलेगी नौकरी

रायबरेली

अमर उजाला ब्यूरो

मंगलवार, 28 जुलाई 2015

Updated @ 12:11 AM IST

एनआरएचएम के तहत बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संविदा पर एमबीबीएस डॉक्टरों समेत 54 पदों की भर्ती मात्र दो दिन में पूरी होगी।

29 जुलाई को अभ्यर्थियों को सीएमओ कार्यालय पहुंचकर पंजीयन कराना होगा और 30 जुलाई को इंटरव्यू के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े संविदा के पदों को भरने का काम आगामी 30 जुलाई तक भरना है। इसके लिए सोमवार को विज्ञप्ति भी जारी हो गई।

इसमें महिला एमबीबीएस के तीन पद, स्त्री रोग विशेषज्ञ के पांच पद, निश्चेतक के छह पद, पार्ट टाइम एमबीबीएस के एक पद, पुरुष एमबीबीएस के एक पद, स्टाफ नर्स के 15 पद, एएनएम के दो पद, काउंसलर के एक पद, जनरल फिजीशियन के 14 पदों समेत 54 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।

वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया के तहत यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है।

सीएमओ डॉ. राकेश कुमार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को 30 जुलाई से पहले पूरा करना है, इसीलिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती शुरू कराई गई है।

- > डिग्री के बाद भी क्यों नहीं मिल रही नौकरी? ये है वजह
- > 51 हजार रुपए की सैलरी वाली नौकरी, क्या आप करना चाहेंगे?
- > नौकरी मांगने में सबसे आगे हैं ये लोग, आप भी जानिए

Clipping-10

The clipping-10 of 28th July 2015 informs regarding the availability of employment in health sector. The news for sure related with the provisions of better health facilities in the district. It informs that how many posts are going to filled by the health department after through interview. The statement of CMO mentioned that this is a walk-in interview in which any candidate with desired qualification will come. The reason of walk in was to complete this recruit before 30th July as mentioned by the CMO.

निधि से जगमग करेंगे 838 स्थान

रायबरेली

अमर उजाला ब्यूरो

शुक्रवार, 31 जुलाई 2015

Updated @ 11:58 PM IST

गांवों में सोलर लाइट लगवाने की होड़ सी लग गई है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, विधायक, एमएलसी सहित अन्य जनप्रतिनिधि गांवों को जगमग करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। राज्यसभा सदस्य कैप्टन सतीश शर्मा ने भी 838 स्थानों पर सोलर लाइट लगवाने की संस्तुति की है।

एक करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से लाइट लगवाने के लिए डीआरडीए को प्रस्ताव पास होने के लिए दिया गया है। इसके अलावा 474 स्थानों पर एक करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से हैंडपंप लगवाने का भी प्रस्ताव दिया है।

राज्यसभा सदस्य कैप्टन सतीश शर्मा को विकास कार्य कराने के लिए लोकसभा चुनाव के बाद निधि में बजट नहीं मिला है। अब बजट मिलने की उम्मीद है।

राज्यसभा सदस्य ने जिले के गांवों में 838 स्थानों पर सोलर लाइट निधि से लगवाने की संस्तुति की है। इस संबंध में उन्होंने प्रस्ताव भी पास करके डीआरडीए को उपलब्ध करा दिया है।

आशा जताई है कि प्रस्ताव पास होने तक निधि में बजट आ जाएगा। पीडी इंद्रसेन सिंह ने बताया कि प्रस्ताव आ गए हैं। उन्हें पास कराने का काम शुरू हो गया है। निधि के लिए डिमांड भी भेजी गई है।

Clipping-12

The clipping-12 of 31st July 2015 is related with the development of villages. In the clipping it is mentioned that the funds will be provided by the government for the welfare to make proper lighting in their areas. It also informs that captain Satish Sharma, Member of Parliament have not received their budget for the welfare and development but hopes that the funds will be received soon. 838 paces have been chosen for solar lights and proposals were send to the DRDO for implementation.

मेरा रंग दे बसंती चोला... ने बांधा समां

रायबरेली

अमर उजाला ब्यूरो

शुक्रवार, 14 अगस्त 2015

Updated @ 11:13 PM IST

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को डिग्री कॉलेज चौराहा स्थित शहीद चौक पर हुए शहीद संध्या कार्यक्रम में देशभक्ति के गीतों ने लोगों में जोश और उल्लास भर दिया।

सभी ने शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। आज्ञादी के जश्र में शहीद चौक, प्रमुख चौराहे और इमारतें बिजली की झालरों से जगमगा उठीं।

पालिका की ओर से हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय, डीएम प्रेम नारायण, सीडीओ अनूप श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन एससी श्रीवास्तव, एसडीएम राकेश गुप्ता, नगर पालिका चेयरमैन इलियास, ईओ पीएन सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

मंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर देश को एक नया मुकाम दें, यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने मेरा रंग दे बसंती चोला..., देश रंगीला..., अपनी आज्ञादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं..., यह देश है वीर जवानों का... आदि भक्ति गीतों पर डांस किया।

संचालन सभासद सबिस्ता ब्रजेश ने किया। सोनू सिंह, रामखेलावन, अनिल कुमार, शत्रोहन, गया प्रसाद मौजूद रहे। शहीद चौक, सिविल लाइन, कलेक्ट्रेट, सुपर मार्केट, सरकारी व गैर सरकारी भवन बिजली की झालरों की रोशनी में जगमगा उठे।

- > तस्वीरें: स्वतंत्रता दिवस के जश्र से पहले चमचमाई दिल्ली
- > फहराएंगे तिरंगा, मनाएंगे आज्ञादी का जश्र
- > देखिए, एडवाइजर से सम्मानित 15 विशेष हस्तियों का पूरा प्रोफाइल

Clipping-12

The clipping no. 12 of 14th August 2015 is persuading for the coming Independence Day and informs about the preparation going in the district to celebrate Independence Day. The place chosen for the organization was Degree College. In the clipping many messages for the country are given by the important personalities. Overall the clip reflects the harmony in the district.

रैली निकाल गंगा सफाई के लिए किया जागरूक

रायबरेली

अमर उजाला ब्यूरो

सोमवार, 26 अक्टूबर 2015

Updated @ 11:39 PM IST

छात्र-छात्राओं ने लोगों को अभियान में शामिल होने की अपील की। रानी शिवाला समेत अन्य घाटों की सफाई कर लोगों को जागरूक किया। आईटीबीपी के दल ने शुद्धता की जांच के लिए गंगा नदी के पानी का सैंपल भी लिया।

आईटीबीपी की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 2 अक्टूबर को इलाहाबाद के देवप्रयाग से शुरू हुआ। इसमें आईटीबीपी का 46 सदस्यीय दल शामिल है।

जो न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहा है, बल्कि गंगा नदी की शुद्धता की जांच भी करा रहा है। सोमवार को दल के डलमऊ पहुंचने के बाद यहां भी रैली निकाली गई।

इसमें कई विद्यालयों के छात्र-छात्राओं और कस्बे के लोगों ने भाग लिया। रैली कस्बे के आदर्श नगर, शंकर नगर, मियां टोला, चौहड़ा समेत अन्य मोहल्लों और प्रमुख मार्गों से होते हुए रानी शिवाला घाट पर समाप्त हुई।

यहां जागरूकता गोष्ठी भी हुई। गोष्ठी में दल की अगुवाई कर रहे आईटीबीपी के कमांडेंट सुरेंद्र खत्री ने कहा कि गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। इसे स्वच्छ बनाना सभी की जिम्मेदारी है।

एसडीएम राम अक्षयवर और ईओ नगर पंचायत सुरेश कुमार मौर्य ने लोगों से अभियान में सहयोग की अपील की। तरुण कुमार, डॉ. पराग, सतीश कुमार, अशोक कुमार ने नदी में कूड़ा-कचरा न फेंकने व नदी में नाले न गिराने की अपील की। इस मौके पर सुनील श्रीवास्तव, जय प्रकाश सिंह, राकेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

> गंगा बैराज पर ट्रक्टर बोलेरो की भिड़ंत में पांच की जान गई

> अंग्रेजों के जमाने का समझौता टूटा, गंगाजल से सूनी हुई हरकी पैड़ी

Clipping-13

The clipping-13 of 26th October 2015 is related to the awareness program to students of the district related to their participation in the Clean Ganga Mission. Students from different schools participated in this and persuade to do something for the clean Ganga Abhiyan. The overall motto was to aware people about the importance of cleanliness through newspaper.

383 स्कूलों में रसोइए मतदान कर्मियों के लिए बनाएंगे लजीज व्यंजन

रायबरेली

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुवार, 26 नवंबर 2015

Updated @ 11:28 PM IST

इसके लिए 383 स्कूलों की रसोइयों के 27 नवंबर को ही पोलिंग पार्टिया पहुंचने से पहले ही स्कूलों में मौजूद रहने के आदेश दिए गए हैं। कर्मचारियों से भुगतान लेकर उनकी पसंद का व्यंजन बनाया जाएगा।

मतदान कराने वाले कर्मचारियों को खाने पीने की समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन सभी रसोइयों को स्कूलों में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं।

जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा शिक्षा अधिकारियों को 27 नवंबर से ही स्कूलों में रसोइयों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं।

बीएसए ने निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों से भुगतान लेकर उनकी पसंद का भोजन मतदान केंद्रों पर बनाया जाएगा। मतदान समाप्त होने से पहले तक भोजन और चाय नाश्ते की व्यवस्था रसोइयों करेगी।

बीएसए रामसागर पति त्रिपाठी ने बताया कि संबंधित बीईओ को निर्देश दिए गए हैं। जिन स्कूलों में रसोइयों के न पहुंचने की शिकायत आएगी, उन रसोइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

- > प्रथम चरण के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां
- > अनाधिकृत व्यक्ति नहीं कर सकेंगे प्रवेश
- > मतदान के दिन भारी पड़ सकती है दबंगई
- > सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला, सेना के मुस्लिम जवान दाढ़ी रखें या नहीं?

Clipping-14

The clipping-14 of 26th November 2015 informs about proper utilization of the resources. The midday meal workers of 383 schools are selected to cook food for the official deployed polling duty. In his order DM clearly mentioned that the entire concerned are instructed to present on 27th November to serve the food to the officials. This news shows the facilities provided by the DM for the smooth polling.

विकास न होने से खफा ग्रामीण करेंगे मतदान का बहिष्कार

रायबरेली

सोमवार, 30 नवंबर 2015

अमर उजाला ब्यूरो

Updated @ 11:33 PM IST

प्रदर्शनकारियों ने प्रधान और सदस्य पद के प्रत्याशियों के परचे फाड़ कर जला दिए। अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

सभी ने एलान किया कि जब तक गांव की समस्याएं दूर नहीं होंगी तो मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद से गांव में विकास नहीं कराया गया है।

ग्राम प्रधान से लेकर जिले के अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रामस्वरूप, राम नरेश यादव ने बताया कि बारिश में गांव में जलभराव हो जाता है। आने-जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है।

गांव में लगा राजकीय नलकूप कभी नहीं चला। गंगा प्रसाद ने बताया कि ग्रामीणों को विद्युतीकरण योजना का लाभ नहीं मिला। बिंदाचरण ने कहा कि गांव में प्राथमिक व जूनियर विद्यालय होते हुए भी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है।

शिक्षक कभी कभार आते हैं। रामपुर राजस्व गांव होते हुए भी पंचायत चुनाव में बूथ नहीं बनाया गया। जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बूथ बनाया जाता है।

अभी तक पात्रों को पेंशन व किसानों को फसल बर्बादी का मुआवजा नहीं मिला है। वहीं एसडीएम लालगंज दिलीप कुमार ने बताया कि ग्रामीणों को समझा-बुझाकर मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। चुनाव के बाद सभी समस्याओं का निदान कराने का प्रयास किया जाएगा।

- > छह लाख वोटर चुनेंगे गांव की सरकार
- > 3 लाख मतदाता आज चुनेंगे गांव की सरकार
- > 380 बूथों पर डाले जाएंगे वोट
- > 500 में बेचते थे फर्जी वोटर कार्ड
- > वोट न देने पर जान की धमकी दी

Clipping-15

The clipping-15 of 30th November 2015 shows that newspaper is the best way to express views of peoples. In the clipping it is shown that peoples in the village will skip the polling because there are no development work was done in the Area. With the help of newspaper the whole problems are mentioned that are facing by the villagers especially on development issues. The villagers said that teachers are not regular to schools, electrification schemes failed; water logging problems are some big issue.

मेले से मजबूत होता सामाजिक सद्भाव

रायबरेली

मंगलवार, 8 दिसंबर 2015

अमर उजाला ब्यूरो

Updated @ 11:49 PM IST

यह बात एनटीपीसी उत्तरी क्षेत्र के अधिशासी निदेशक सप्तर्षि राय ने मंगलवार को ऊंचाहार परियोजना में हुए शरद मेले के उद्घाटन के दौरान कही।

मेले का उद्घाटन उत्तरी महिला मंडल की अध्यक्ष महुआ राय ने किया। मुख्य अतिथि का प्रियदर्शिनी महिला क्लब की अध्यक्ष प्रतिमा सेमुएल ने स्वागत किया।

मेले के विशिष्ट अतिथि सप्तर्षि राय का समूह महाप्रबंधक राकेश सेमुएल, विभागाध्यक्षों ने अभिनंदन किया। अतिथिजनों ने मेला परिसर में पूजा-अर्चना की एवं मेले का अवलोकन किया।

इसके अलावा फन राइड्स, हाउजी, फन गेम्स, लकी ड्रा तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं वाहन उत्पाद के दुकानों में भारी भीड़ जमी रही। इस दौरान अधिकारियों ने पौधरोपण किया।

- > फरवरी में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया फेयर
- > शरद मेले में छाई रही भदोही की कालीन

इस दौरान सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई, जिसका प्रस्तुतिकरण मनोहारी रहा। मेला परिसर में जरूरतमंदों को सिलाई मशीन तथा श्रवण यंत्र का वितरण किया गया।

मेले में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान तथा उद्यान विभाग के सौजन्य से संचालित किये गए प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौंदर्य के प्रस्तुतिकरण को सभी की सराहना मिली।

ऊंचाहार प्रवास के दौरान क्षेत्रीय अधिशासी निदेशक सप्तर्षि राय ने प्लांट का भ्रमण किया और निर्माणाधीन विद्युत इकाई की साइट का निरीक्षण किया।

समीक्षा बैठक में महाप्रबंधक परियोजना संजय मदान, महाप्रबंधक अनुरक्षण एवं प्रचालन लक्ष्मीधर साहू, कंचन नाथ मौजूद रहे।

Clipping-16

The clipping-16 of 8th December 2015 is favoring and promoting the Sharad Mela. This clipping informs about the importance of the fairs as is the way gather people together which promoted communal harmony.

सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता का दिया संदेश

रायबरेली

अमर उजाला ब्यूरो

शनिवार, 12 दिसंबर 2015

Updated @ 11:35 PM IST

वहीं सांस्कृतिक अभियान के तहत कलाकारों ने सभी को आपसी सामंजस्य बनाने के लिए प्रेरित किया। दोपहर बाद सुपर मार्केट में जुलूस प्रारंभ हुआ।

इसमें जिले के कवि, शायर, लेखक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, शिक्षक, अधिवक्ता और कलाकार शामिल हुए। जुलूस सुपर मार्केट से प्रारंभ होकर हाथी पार्क, डिग्री कॉलेज चौराहा होते हुए शहीद चौक पर पहुंचा।

यहां पर कलाकारों ने सांस्कृतिक अभियान को गति प्रदान करते हुए नुक्कड़ नाटक अथक कथा का मंचन प्रस्तुत किया। इसमें सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता और जनतांत्रिक पक्ष को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया गया।

कमेटी सदस्य दुर्जय सोम ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक साहित्यिक संगठनों के साझा अभियान का नाम साझा संघर्ष-साझी विरासत है। इसका संयोजन इप्टा ने राष्ट्रीय स्तर पर किया।

कमेटी के जनार्दन मिश्र ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत 6 दिसंबर को पूरे देश में हो गई है। इसके तहत सांस्कृतिक यात्राएं, सभा, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, काव्य पाठ, फिल्म प्रदर्शन आदि कार्यक्रम होंगे।

संतोष चौधरी ने कहा कि अभियान का दूसरा चरण गांव में केंद्रित होगा। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल से होगी। इस मौके पर डॉ. आरबी वर्मा, डीपी पाल, किरन शुक्ला आदि मौजूद रहे।

- > ओवरलोड पर परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा
- > ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन कर की नारेबाजी
- > फायरिंग का मौका मिला तो खुश दिखीं गर्ल्स कैडेट्स
- > चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी
- > स्टांप चोरी में भाजपा जिलाध्यक्ष समेत सात पर जुर्माना

Clipping-17

The clipping-17 of 12th December 2015 is messaging on the Social Justice as well as on cultural promotion. By the performances made by various artist the communal harmony and peace was promoted among the masses. This news also informs about the cultural programs organized in the district are meaningful and able to aware masses.

263 प्रधानों ने संभाली विकास की कमान

रायबरेली

रविवार, 20 दिसंबर 2015

अमर उजाला ब्यूरो

Updated @ 11:13 PM IST

सभी में जिम्मेदारी लेने का विश्वास दिखा तो आम जनता की कसौटी पर खरा उतरने की चिंता भी। रायबरेली और अमेठी जिले के छह ब्लॉकों में शपथ ग्रहण समारोह हुआ।

इसमें रायबरेली में प्रधान के 116 व पंचायत सदस्य के 1429 और अमेठी में प्रधान के 147 और 1897 ग्राम पंचायत सदस्यों ने शपथ ली। इसी के साथ ही नवनिर्वाचित प्रधानों ने गांव के विकास की बागडोर संभाल ली।

ऊंचाहार ब्लॉक सभागार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने 47 प्रधानों और 602 ग्राम पंचायत सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

नवनिर्वाचित बृजेश यादव, राजेश कुमार सिंह, आनंद पांडेय, अमरनाथ, केतकी मौर्या, रन बहादुर सिंह, ऊषा, बिंदादीन, अरुण यादव ने शपथ ली। कोरम पूरा न होने के कारण नौ गांवों के प्रधान शपथ नहीं ले सके।

रोहनिया ब्लॉक सभागार में भी मंत्री डॉ. मनोज पांडेय ने 21 प्रधानों और 283 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

नवनिर्वाचित प्रधान राजकिशोर तिवारी, विवेक यादव, संगीता, रामलाल, रामलाल, राकेश कुमार, कांती देवी ने शपथ ली। इस मौके पर बीडीओ जेएन राव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सरेनी प्रतिनिधि के अनुसार ब्लॉक सभागार में सुबह बीडीओ एमपी शुक्ला ने 48 प्रधान और 544 ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई गई।



- > 454 प्रधानों ने संभाली गांवों की सत्ता
- > 629 प्रधानों ने संभाली गांवों की बागडोर
- > 260 नवनिर्वाचित प्रधानों ने ली शपथ

Clipping-18

The clipping-18 of 20th December 2015 is news related to the newly elected Gram pradhans. The pradhans are important as they are supposed to rejuvenate the development programs and schemes launched by the governments and funds are directly provided to them. The elected pradhans were taken oath and started work.

Summary of content of clippings- The clippings revealed that newspapers giving due importance to the news related to the development. On regular basis coverage was given on issues related to the Various schemes of the government, MGNREGA, Infrastructure (Smart city), Rural Development, Health (AIIMS), Education, Electricity, Non-conventional Energy, Sanitation and cleanliness, Human Values, Good Governance, Popularization of ICT, Safe Drinking Water, Agriculture, Use of Pesticide in agriculture, Natural Resource management, Training and many more.

The clippings also revealed that newspaper cover all the aspect related to the development and role of press to encourage various its sphere. Newspaper clipping indicated that Social Integration, Social Justice, Political Awareness, Cleanliness, Environment, Human Resource Development, Tainting, Education, Monitoring of Development, Rural Electrification, Panchayti Raj, Micro Finance, Science Exhibition, Postal Services, Housing for Poor, Road, Employment Schemes, Employment Fair, Community Development, Portrayal of issues related to scheduled caste, Industrial Development, Social Responsibility, were the key points of the coverage with reference to the Raebareli. These clippings equally portrait the coverage related to the Social Development, Political Development and Economic Development. The newspaper give appropriate coverage to the news related with the development and role of press in awareness, education and dissemination of information.

5.2 Attitude of Newspaper Reader

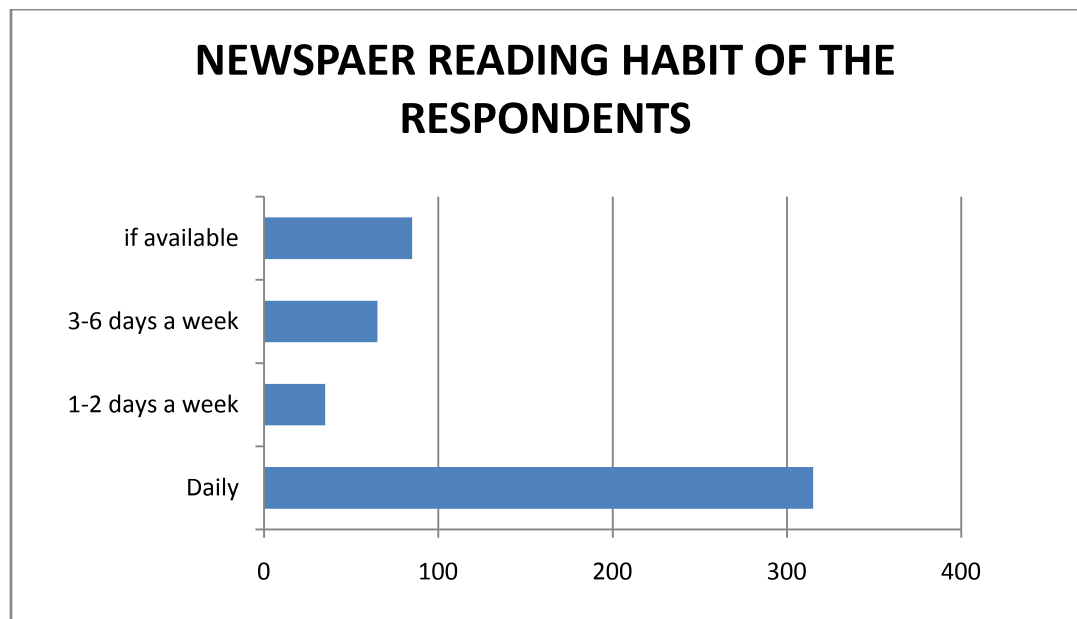
Section (B)

5.2.1 NEWSPAPER READING HABIT OF THE RESPONDENTS:

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	Daily	315	63.0
2	1-2 days a week	35	7.0
3	3-6 days a week	65	13.0
4	if available	85	17.0
	Total	500	100

Table-5.2.1

Table no. 5.2.1 indicates Newspaper reading habit of the respondents, graph above shows that readers who read newspaper daily have majority with 63.0% followed by 7.0% reading 1-2 days in a week, 13.0% reading newspaper 3-6 days a week and 17.0% respondents reads newspaper as per its availability.



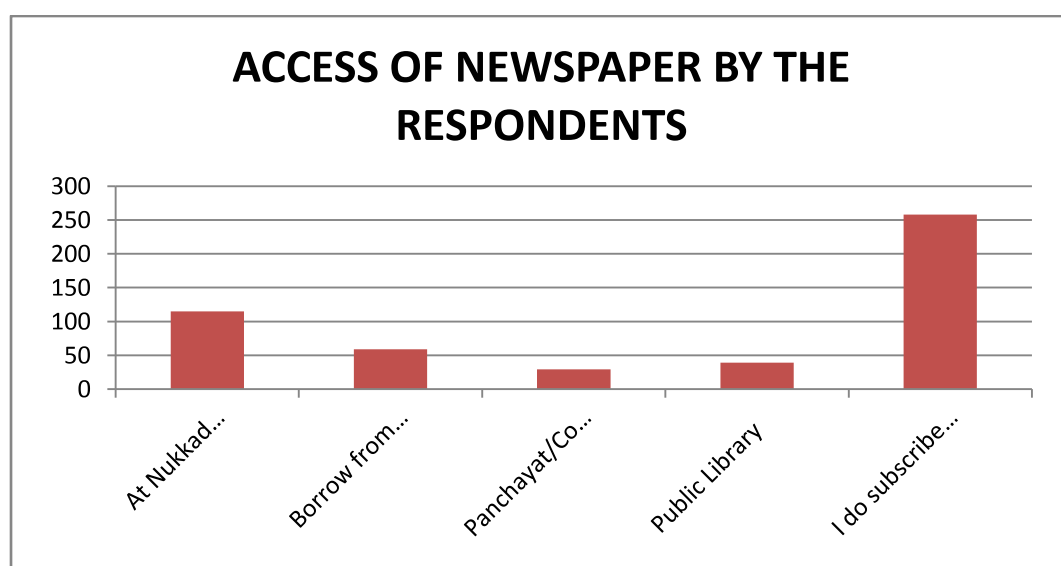
Graph-5.2.1

5.2.2 ACCESS OF NEWSPAPER BY THE RESPONDENTS:

Sl.	Access of Newspaper	Frequency	Percentage (%)
1	At nukkad paanwala	115	23.0
2	Borrow from Neighbor	59	11.8
3	Panchayat Bhawan/ Community Centre	29	5.8
4	Public Library	39	7.8
5	I do subscribe newspaper	258	51.6
	Total	500	100

Table-5.2.2

Newspaper access is also a point to be assess as table no.5.2.2 reveals that respondents reading newspaper at various places like nukkad paan shop where 23.0% of the respondents are reading newspaper followed by 11.8% reading by borrowing it from the neighbor, 5.8% reading at Panchayat Bhawan, 7.8% in Public Library and majority of 51.6% respondents reading newspaper by subscription.



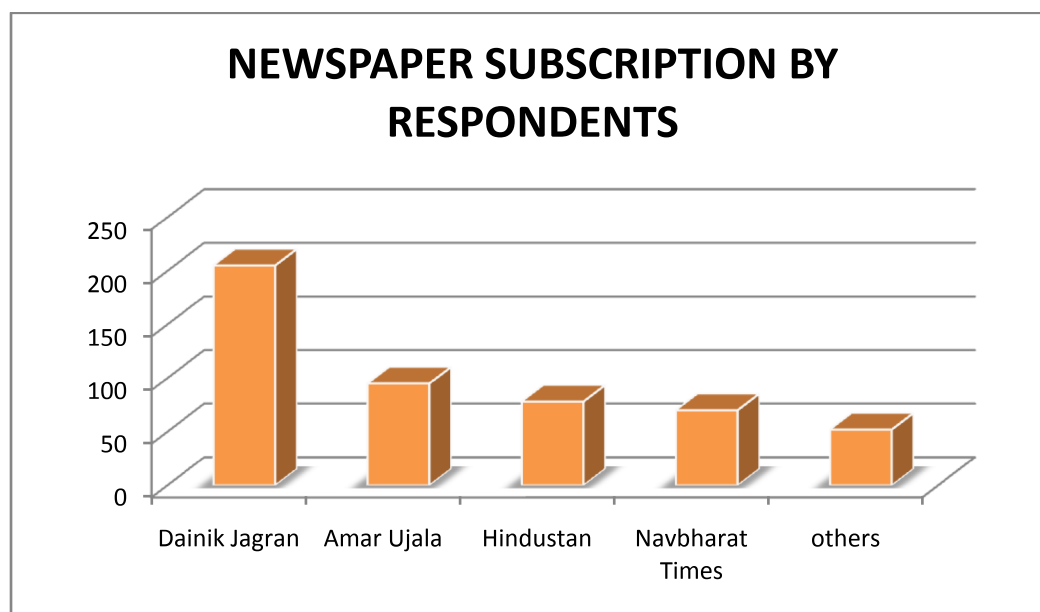
Graph-5.2.2

5.2.3 NEWSPAPERS SUBSCRIBED BY THE RESPONDENTS:

Sl.	Newspaper	Frequency	Percentage (%)
1	Dainik Jagran	205	41.0
2	Amar Ujala	95	19.0
3	Hindustan	78	15.6
4	Navbharat Times	70	14.0
5.	Others	52	10.4
	Total	500	100

Table-5.2.3

The brand which was preferred by the respondent is also an important element which was shown by a Graph below. The Table above reveals that 41.0% of the respondent reading Dainik Jagran followed by 19% readers reading Amar Ujala, 15.6% reading Hindustan, 14.0% Navbharat Times and rest 10.4% reading other newspapers.



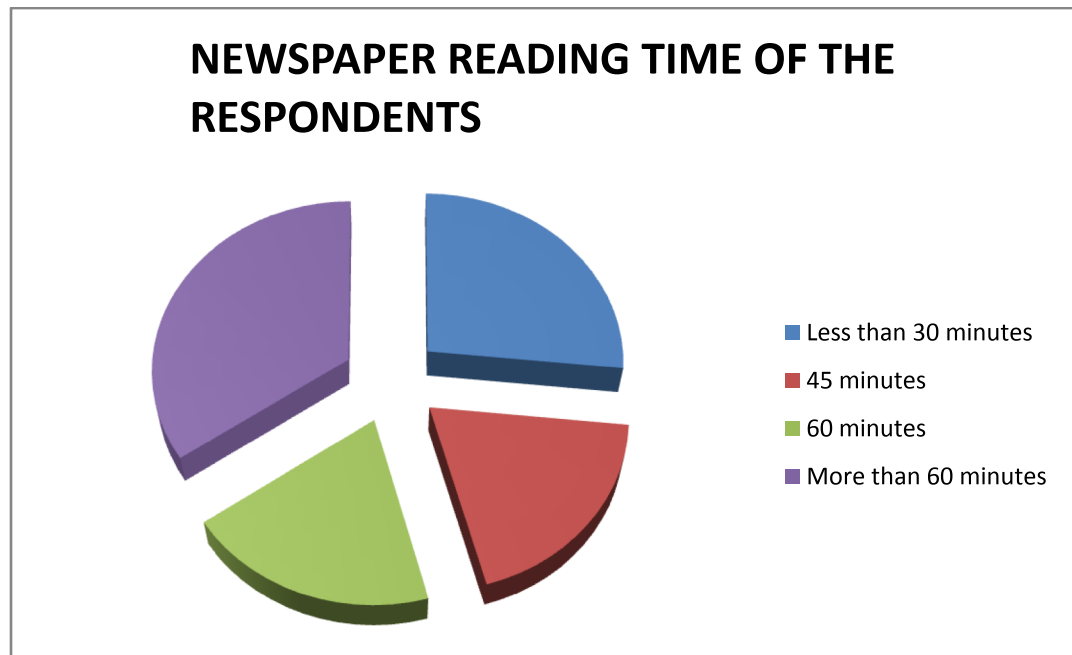
Graph-5.2.3

5.2.4 AVERAGE NEWSPAPER READING TIME OF THE RESPONDENTS:

Sl.	Reading time	Frequency	Percentage (%)
1	Less than 30 minutes	133	26.6
2	45 minutes	96	19.2
3	60 minutes	98	19.6
4	More than 60 minutes	173	34.6
	Total	500	100

Table-5.2.4

Table no.5.2.4 reveals about average newspaper reading time of the respondents. 26.6% spend less than 30 minutes, 19.2% spend 45 minutes, 19.6% spend 60 minutes followed by 34.6% of respondents spend more than 60 minutes for reading newspapers.



Graph-5.2.4

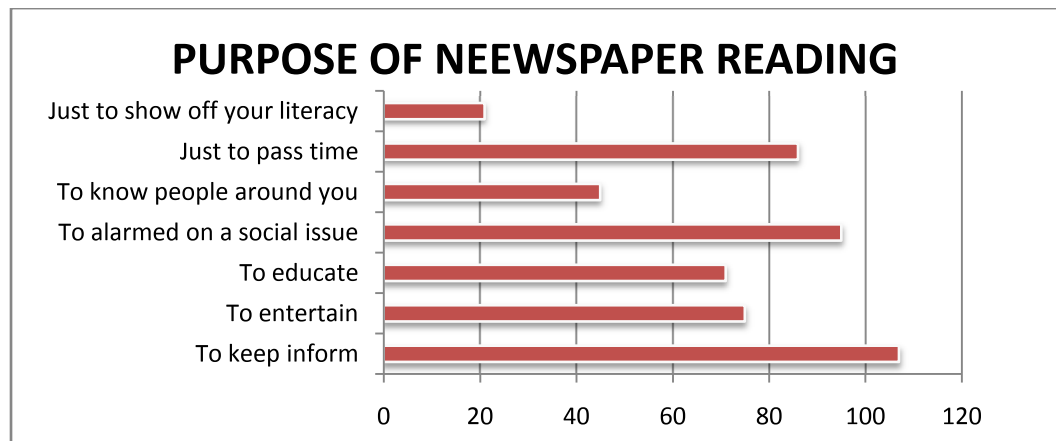
Section (C)

5.2.5 PURPOSE OF NEWSPAPER READING OF THE RESPONDENTS:

Sl.	Purpose of Reading	Frequency	Percentage (%)
1	To keep inform	107	21.4
2	To entertain	75	15.0
3	To educate	71	14.2
4	To alarmed on a social issue	95	19.0
5	To know people around you	45	9.0
6	Just to pass time	86	17.2
7	Just to show off your literacy	21	4.2
Total		500	100

Table-5.2.5

Table 5.2.5 reveals that 21.4% respondent reading newspaper to keep them inform about the happenings around, 15.0% reading for entertainment, 14.2% are reading for educational purposes, 19.0% consider it use to alarm on a social issue, 9.0% reading newspaper just to know people around them however 17.2% reading it just to pass time and least 4.2% believe that reading newspaper is just to show off that indicates towards literacy.



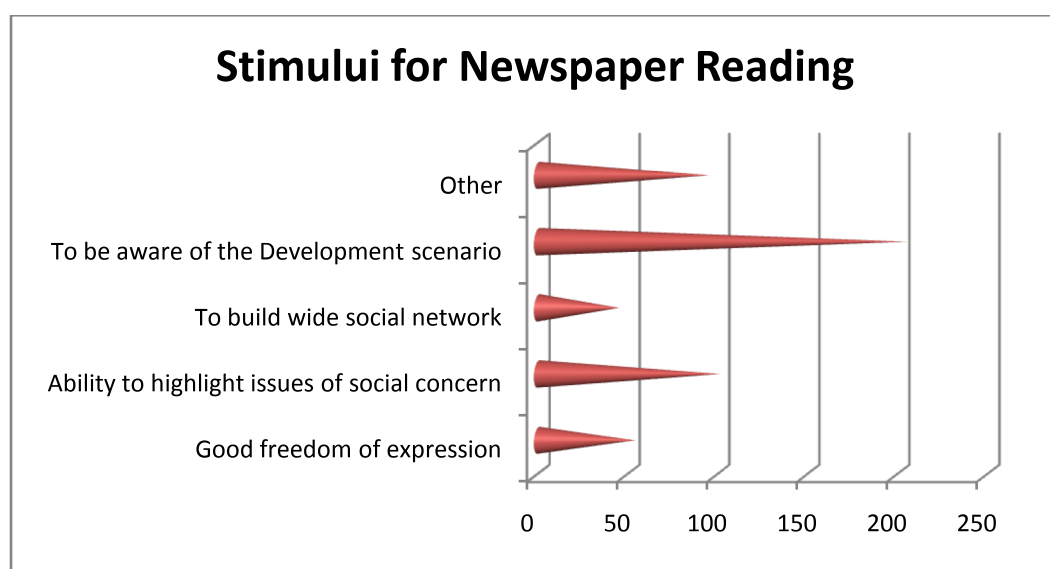
Graph-5.2.5

5.2.6 STIMULI BEHIND NEWSPAPER READING OF THE RESPONDENTS:

Sl.	Motivation behind reading newspaper	Frequency	Percentage (%)
1	Good freedom of expression	54	10.8
2	Ability to highlight issues of social concern	101	20.2
3	To build wide social network	45	9.0
4	To be aware of the Development scenario	205	41.0
5	Other	95	19.0
	Total	500	100

Table-5.2.6

Respondent were questioned about their motivational factor behind reading newspaper and 41.0% of respondent replied that they like newspapers because they aware masses on development followed by 20.2% respondent to highlight the issues of social concern, 9.0% reading it just to build wide social network, 10.8% reading newspapers for good freedom of expression and 19.0% respondent believe that they reading for other purposes.



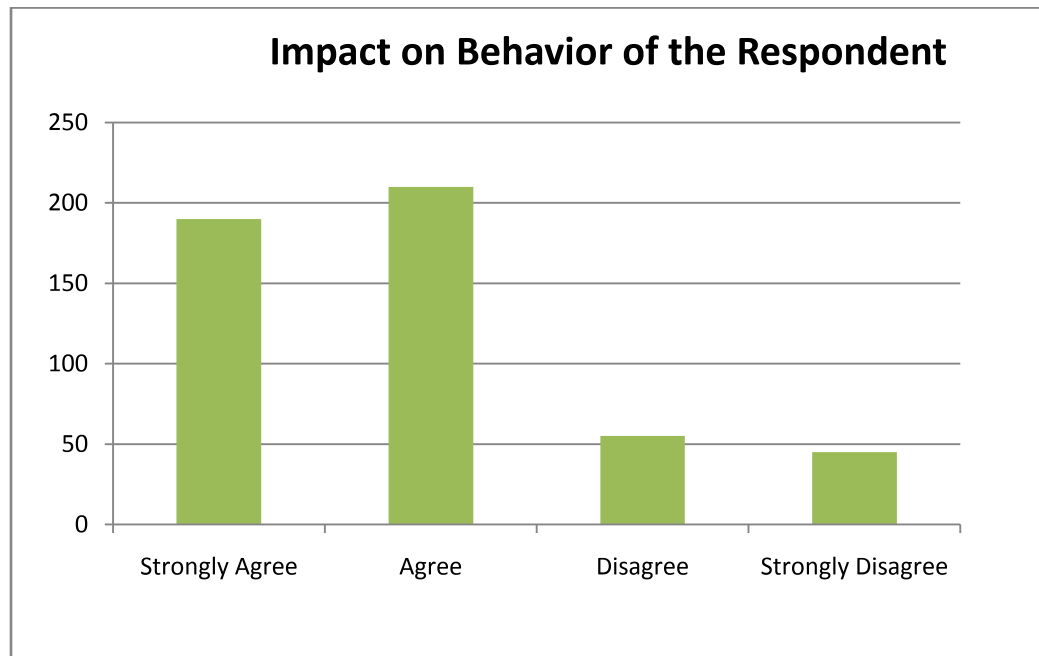
Graph-5.2.6

5.2.7 IMPACT ON BEHAVIOR AND CHANGES IN RESPONSES OF THE RESPONDENTS AFTER READING NEWSPAPER:

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	Strongly Agree	190	38.0
2	Agree	210	42.0
3	Disagree	55	11.0
4	Strongly Disagree	45	9.0
	Total	500	100

Table-5.2.7

Table 5.2.7 reveals that 42.0% respondent agreed that newspaper force readers to interact/reinforce the changes happening around along with 38% respondent who strongly agreed upon followed by 11.0% respondent not agree to it and 9.0% strongly disagreed.



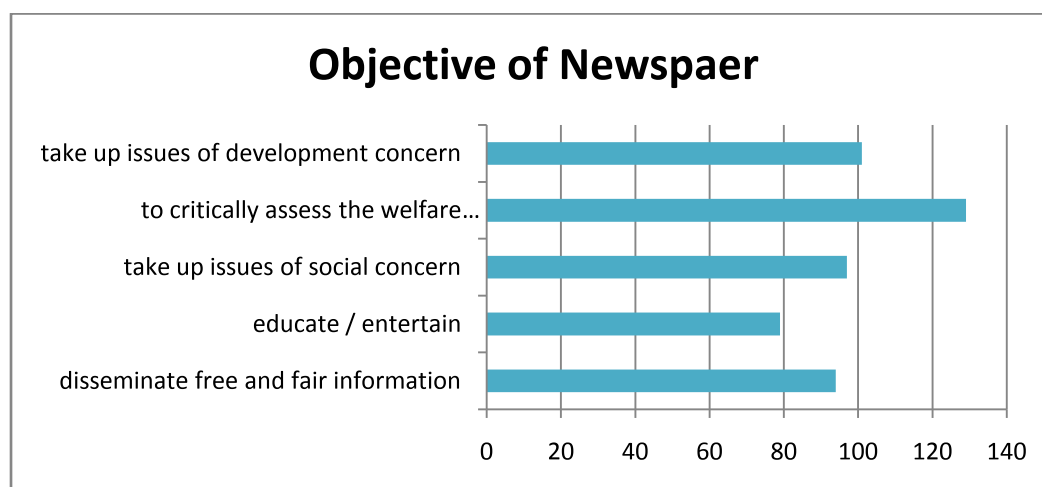
Graph-5.2.7

5.2.8 KEY OBJECTIVES THE NEWSPAPER AS CONSIDERED BY THE RESPONDENT:

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	disseminate free and fair information	94	18.8
2	educate / entertain	79	15.8
3	take up issues of social concern	97	19.4
4	to critically assess the welfare programmes of the government	129	25.8
5	take up issues of development concern	101	20.2
	Total	500	100

Table-5.2.8

The respondent were questioned about the key objectives of the newspaper and it was revealed that 18.8% believes that newspapers disseminate free and fair information, 15.8% think it for educational and entertainment purposes, 19.4% found it to take up issues of social concern, 25.8% believes that newspapers critically assess the welfare programmes of the government and 20.2% responded that the objective of the newspapers are to take up issues of development concern.



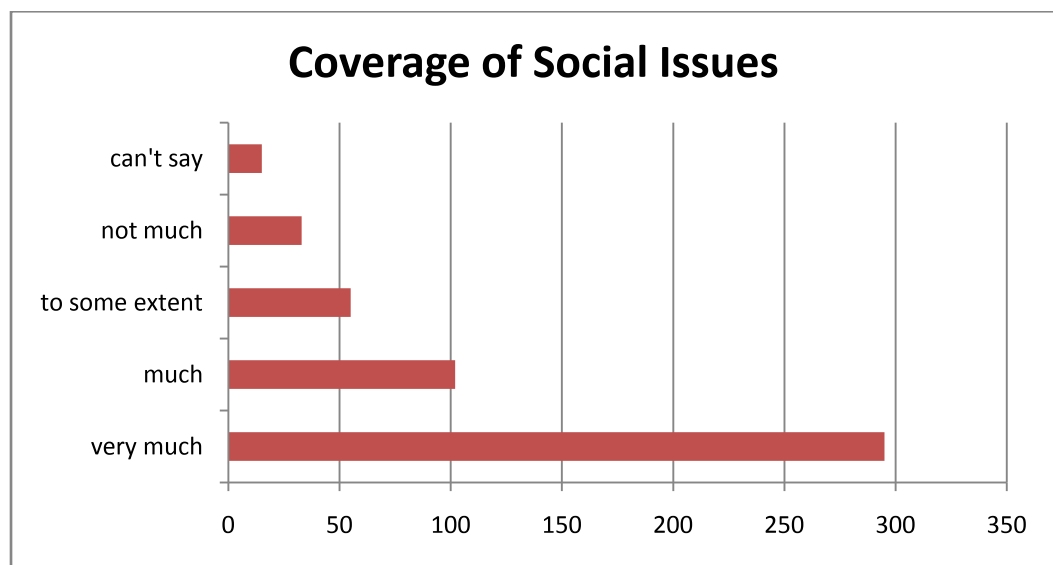
Graph-5.2.8

5.2.9 COVERAGE OF SOCIAL ISSUES LIKE EDUCATION, HOUSING, EDUCATION, HEALTH AND EMPLOYMENT BY THE NEWSPAPERS:

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	very much	295	59.0
2	Much	102	20.4
3	to some extent	55	11.0
4	not much	33	6.6
5	can't say	15	3.0
	Total	500	100

Table-5.2.9

Table 5.2.9 above reveals that newspapers are concerned to cover social issues like education, housing, education, health, employment and in this regard 59.0% (majority) respondent responded that newspaper are very much concerned to it followed by 20.4% responded much concern, 11.0% express it some extent, 6.6% believes not much concerned and 3.0% respondent can't say about this aspect of newspapers.



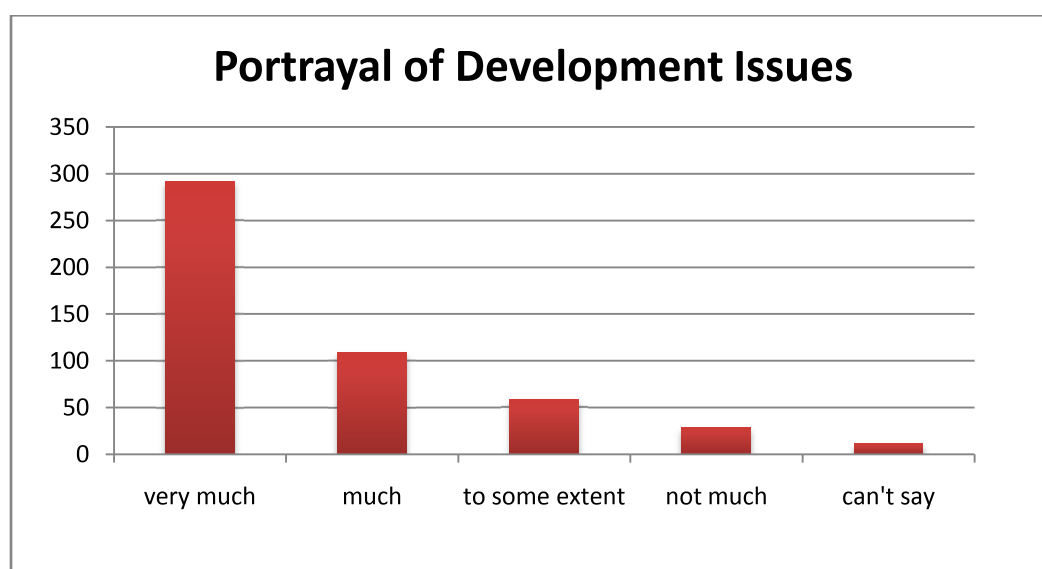
Graph-5.2.9

5.2.10 PORTRAYAL OF DEVELOPMENT ISSUES LIKE HOSPITAL, SAFE DRINKING WATER, PUBLIC TRANSPORT, BANKING, SANITATION BY THE NEWSPAPERS:

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	very much	292	58.4
2	much	109	21.8
3	to some extent	59	11.8
4	not much	29	5.8
5	can't say	11	2.2
	Total	500	100

Table-5.2.10

Table no. 5.2.10 reveals the ability of newspapers for portraying issues of development like Hospitals, safe drinking water, Public Transport, Banking and Sanitation, the majority of respondent 58.4% responded that very much in this regard followed by 21.8% much, 11.8% to some extent, 5.8% not much and only 2.2% respondent were unable to respond on that.



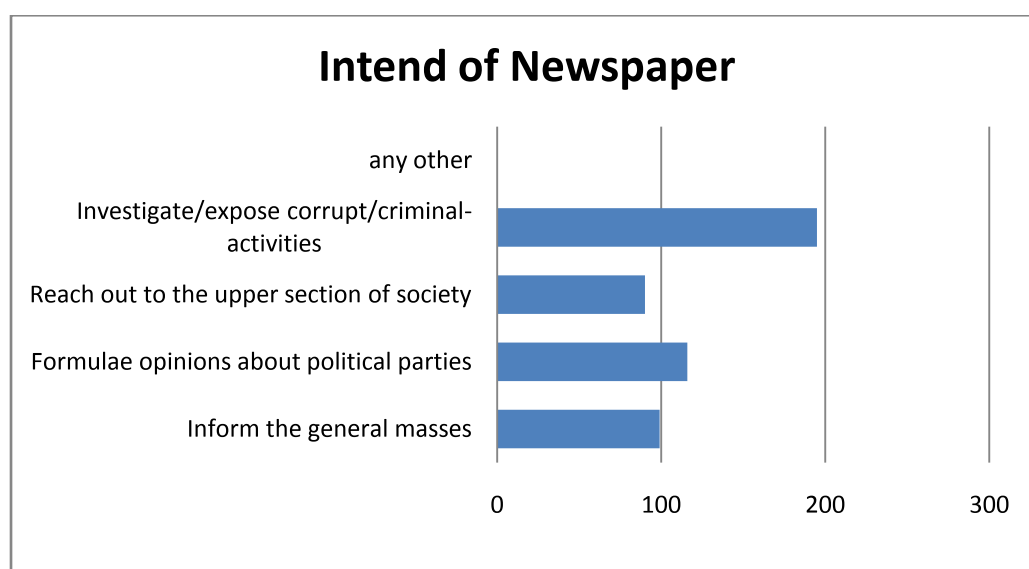
Graph-5.2.10

5.2.11 RESPONDENTS CONSIDERATION TOWARDS INTEND OF NEWSPAPERS:

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	Inform the general masses	99	19.8
2	Formulae opinions about political parties	116	23.2
3	Reach out to the upper section of society	90	18.0
4	Investigate/expose corrupt/criminal-activities	195	39.0
5	any other	00	00
	Total	500	100

Table-5.2.11

Table no. 5.2.11 shows the responses on intent of newspapers and 19.8% respondent replied that newspapers are key source of information to general masses, 23.2% express that newspaper formulate opinions about political parties, 18.0% believes that the reach out the upper section of the society, 39.0% believes that newspapers key intend is to Investigate/expose corrupt/criminal-activities.



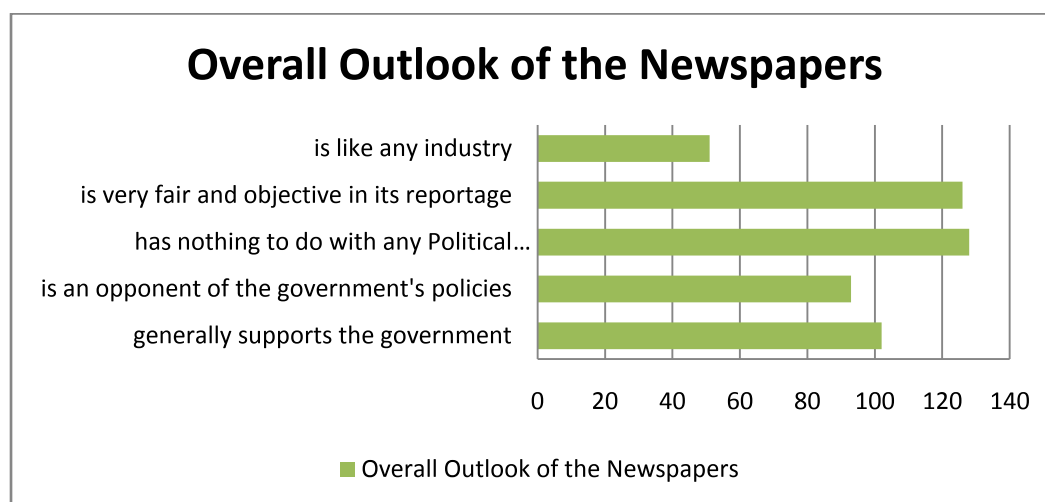
Graph-5.2.11

5.2.12 OBSERVATION AND OPINION OF RESPONDENT FOR OVERALL OUTLOOK OF THE NEWSPAPERS:

Sl.	Response	Frequency	Percentage
1	generally supports the government	102	20.4
2	is an opponent of the government's policies	93	18.6
3	has nothing to do with any Political party/government	128	25.6
4	is very fair and objective in its reportage	126	25.2
5	is like any industry	51	10.2
	Total	500	100

Table-5.2.12

The overall outlook of the respondent in shape of their observation and opinion was also analyzed as per the table no. 5.2.12 given above which reveals that 20.4% of respondents express that newspapers generally support the government direct or indirect way, however 18.6% of total respondent believes that it is an opponent of the government policy, 25.6% indicated that newspapers has nothing to do with any Political party/government, 25.2% said newspapers are very fair and objective in its reportage and 10.2% depicts that newspaper is like any industry.



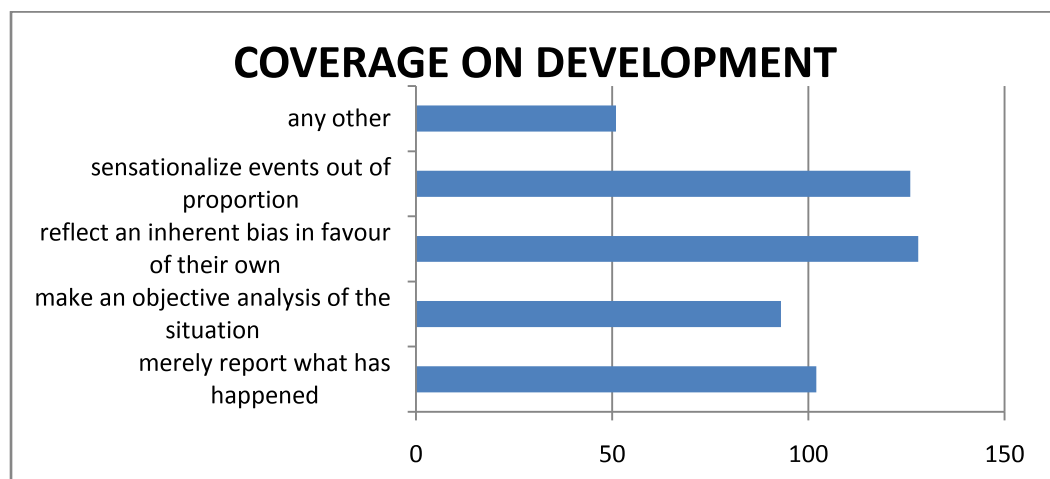
Graph-5.2.12

5.2.13 OBSERVATION AND OPINION OF RESPONDENT ON SPECIFIC NEWS COVERAGE ON DEVELOPMENT BY THE NEWSPAPERS:

Sl.	Response	Frequency	Percentage
1	merely report what has happened	102	20.4
2	make an objective analysis of the situation	93	18.6
3	reflect an inherent bias in favor of their own	128	25.6
4	sensationalize events out of proportion	126	25.2
5	any other	51	10.2
	Total	500	100

Table-5.2.13

As per table no.5.2.13, 20.4% of the total respondent believes that newspaper merely report what has happened, 18.6% newspaper make an objective analysis of the situation, 25.6% reflect an inherent bias in favor of their own, 25.2% newspapers sensationalize events out of proportion however only 10.2% respondent believes that newspaper specifically report news of development relected representatives for any other reason.



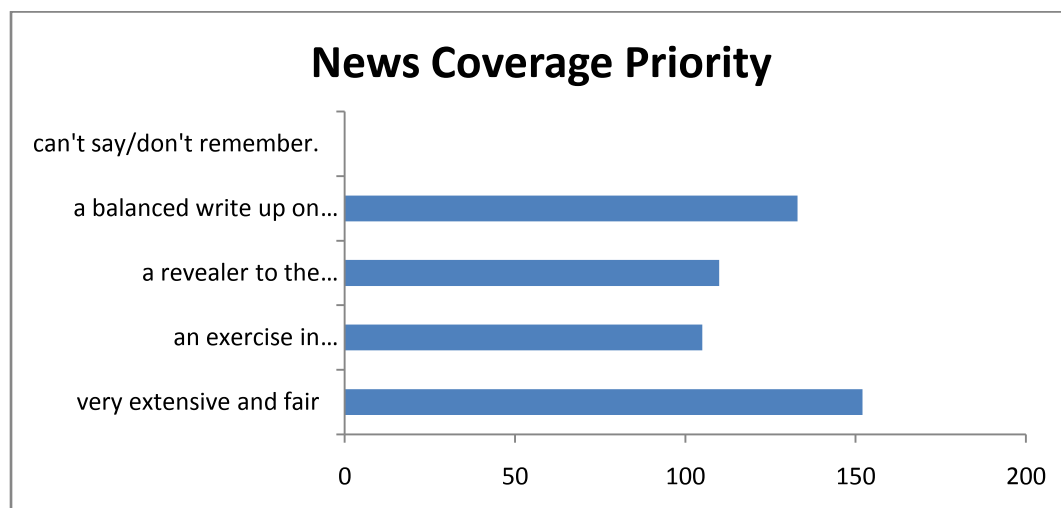
Graph-5.2.13

5.2.14 PRIORITY TO INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL DEVELOPMENT RELATED COVERAGE BY THE NEWSPAPERS:

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	very extensive and fair	152	30.4
2	an exercise in sensationalization	105	21.0
3	a revealer to the possibilities of industrial disasters	110	22.0
4	a balanced write up on development	133	26.5
5	Can't say/don't remember.	00	00
	Total	500	100

Table-5.2.14

Respondents reply on coverage of news related to industrial/institutional development covered by newspaper is represented as shown in the Table-5.2.14 and according to that 30.4% of the respondent believes that coverage is very extensive and fair, 21.0% said it is an exercise in sensationalization, 22.0% think that newspaper are revealer to the possibilities of industrial disasters and 26.5% opines that coverage is balanced write up on development.



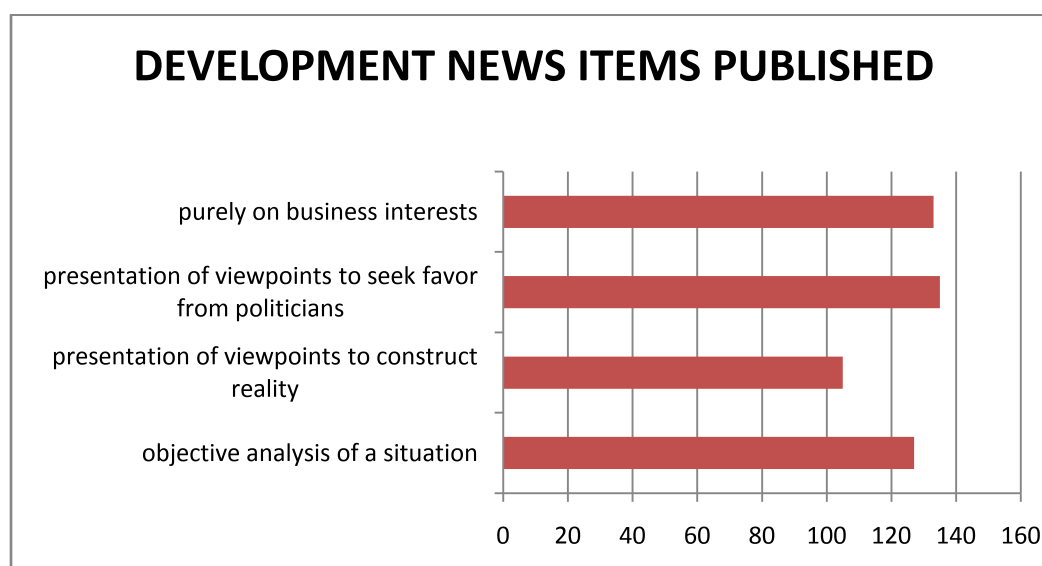
Graph-5.2.14

5.2.15 RESPONDENTS VIEWPOINT ON DEVELOPMENT NEWS ITEMS PUBLISHED BY THE NEWSPAPERS:

Sl.	Response	Frequency	Percentage
1	objective analysis of a situation	127	25.4
2	presentation of viewpoints to construct reality	105	21.0
3	presentation of viewpoints to seek favor from politicians	135	27.0
4	purely on business interests	133	26.6
	Total	500	100

Table-5.2.15

Table no.5.2.15 indicated that 25.4% respondent opine that news of development issue published in a newspaper reflects its objective analysis of a situation, 21.0% indicated that presentation of viewpoints to construct reality, 27.0% expressed that presentation of news shows its viewpoints to seek favor from politicians and 26.6% of the total respondent believes that newspaper do it purely on business interests.



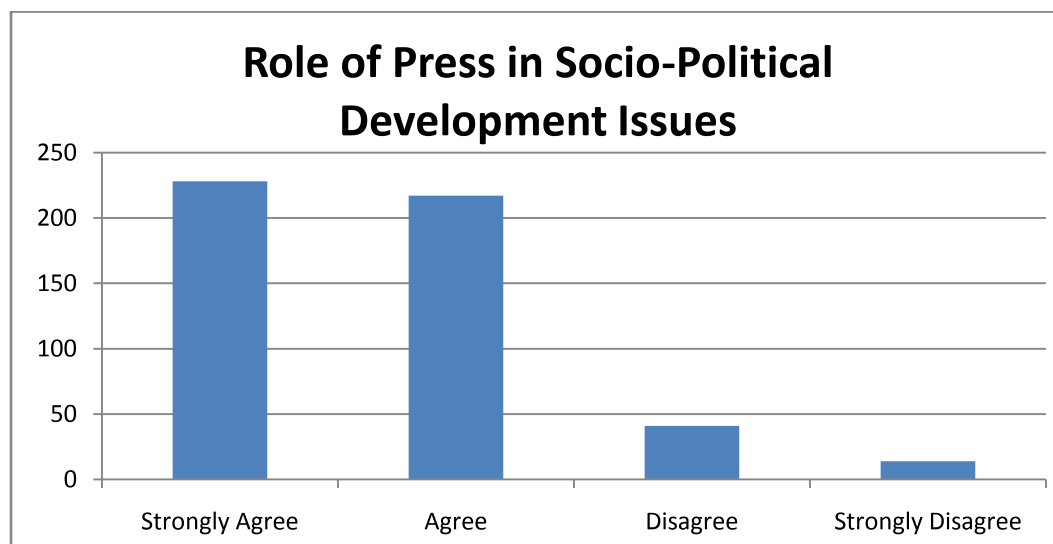
Graph-5.2.15

5.2.16 RESPONDENTS VIEWPOINT ON ROLE OF PRESS IN SOCIO-POLITICAL DEVELOPMENT ISSUES SUGGESIONS TO POLITICAL REPRESENTATIVES:

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	Strongly Agree	228	45.6
2	Agree	217	43.4
3	Disagree	41	8.2
4	Strongly Disagree	14	2.8
	Total	500	100

Table-5.2.16

Respondent were asked to reply on their consideration that the role of press is to convey socio-development issues to your political representative- as table no. 5.2.16 reveals that 45.6% respondent are strongly agree to it along with 43.4% respondent agreed to it however merely 8.2% disagreed and 2.8% strongly disagreed on this point.



Graph-5.2.16

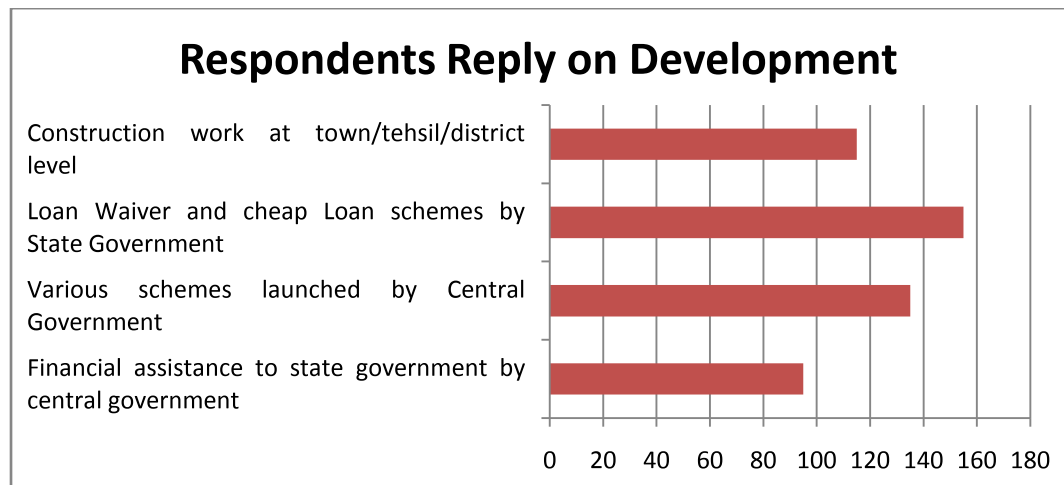
Section (D)

5.2.17 RESPONDENTS REPLY ON THEIR UNDERSTANDING ON WHAT DEVELOPMENT IS:

Sl.	Response	Frequency	Percentage
1	Financial assistance to state government by central government	95	19.0
2	Various schemes launched by central government	135	27.0
3	Loan waiver and cheap loan schemes by state government	155	31.0
4	Construction work at town/tehsil/district level	115	23.0
	Total	500	100

Table-5.2.17

Table no 5.2.17 reveals about understanding of respondent about what is development and 31.0% expressed that development is loan waiver and cheap loan schemes by State Government, 19.0% said that development is Financial assistance to state government by central government, 27.0% observed it as various schemes launched by central government and 23.0% understood that development is construction work at town/tehsil/district level.



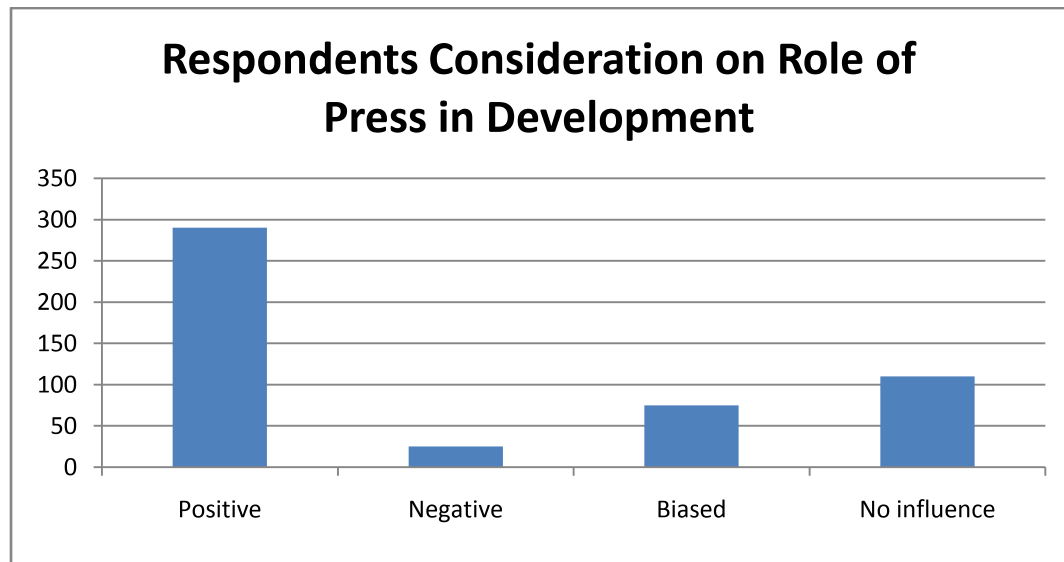
Graph-5.2.17

5.2.18 RESPONDENTS REPLY ON THEIR CONSIDERATION THE ROLE OF PRESS IN DEVELOPMENT:

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	Positive	290	58.0
2	Negative	25	5.0
3	Biased	75	15.0
4	No influence	110	22.0
	Total	500	100

Table-5.2.18

About role of press in development, as per table no. 5.2.18 it is depicted that 58.0% (majority) of respondent believes positive role of press in development, 22.0% consider it has no influence, 15.0% consider it biased and only 5.0% respondent believes that role of press in development is negative.



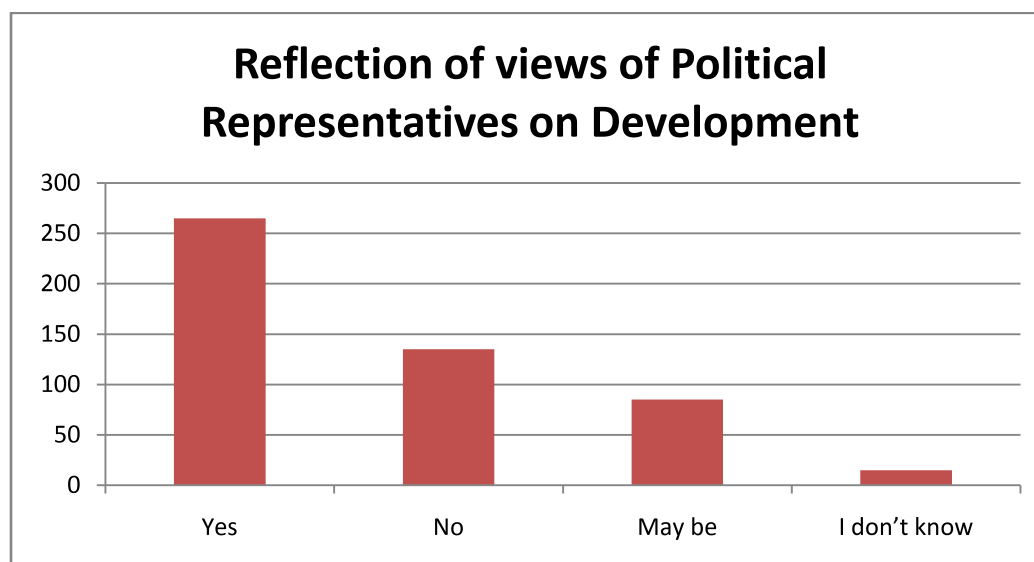
Graph-5.2.18

5.2.19 REFLECTION OF VIEWS OF POLITICAL REPRESENTATIVES ON DEVELOPMENT BY THE NEWSPAPER:

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	Yes	265	53.0
2	No	135	27.0
3	May be	85	17.0
4	I don't know	15	3.0
	Total	500	100

Table-5.2.19

Table no. 5.2.19 clearly indicated that news published in newspaper has been seriously considered by the political representatives as 53.0% (majority) of the respondent affirmed to this and 27.0% was against however 17.0% replied it's may be and 3.0% were don't know much about it.



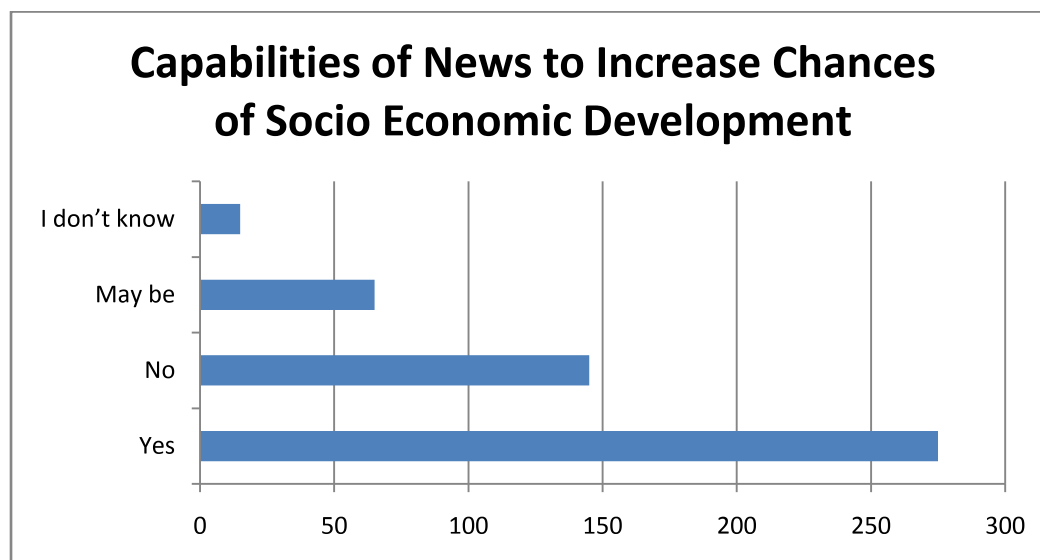
Graph-5.2.19

5.2.20 RESPONDENTS REPLY ON SPECIFIC NEWS ITEMS CAPABLE TO INCREASE THE CHANCES OF SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT:

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	Yes	275	55.0
2	No	145	29.0
3	May be	65	13.0
4	I don't know	15	3.0
	Total	500	100

Table-5.2.20

Respondent were asked to submit their opinion on socio-economic development on specific issues and role of newspaper. Table no. 5.2.20 clearly indicated that 55.0% (majority) of the respondent were positively affirmed, 29.0% denied about any role, 13.0% opted may be and 3.0% didn't know about it.



Graph-5.2.20

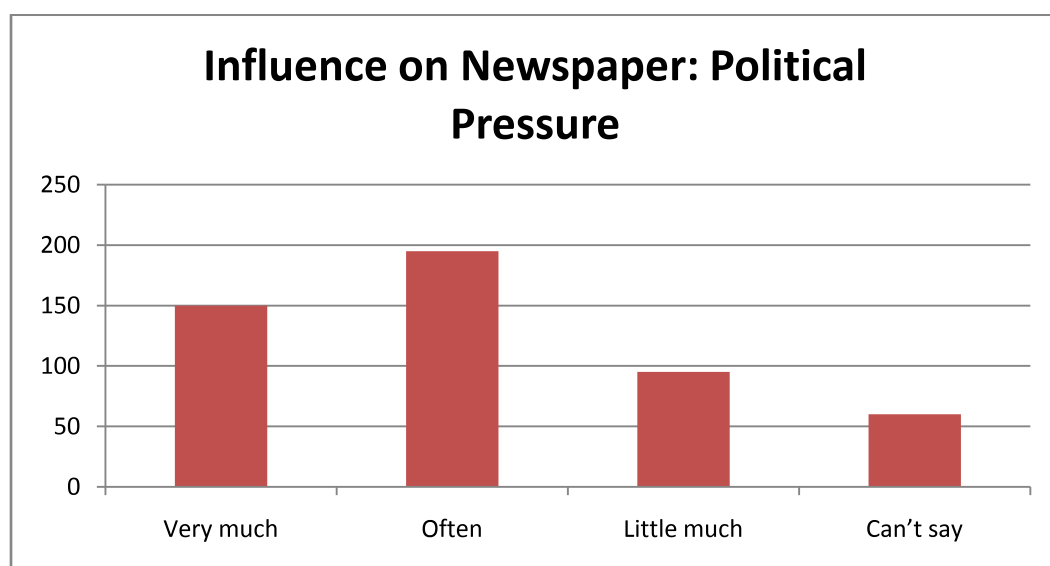
5.2.21 RESPONDENTS REPLY ON THE INFLUENTIAL ELEMENTS TO THE NEWSPAPER LIKE POLITICAL PRESSURE, PROFIT MITIVE, CREATIVE CAPABILITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY:

5.2.21 A)Political Pressure

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	Very much	150	30.0
2	Often	195	39.0
3	Little much	95	19.0
4	Can't say	60	12.0
	Total	500	100

Table-5.2.21

Respondent were questioned about the role performed by the newspaper which politically influenced, Table no. 5.2.21 depicted that 30.0% of the total respondent opted very much political influence, 39.0% found it often, 19.0% observed a little much of political influence however 12.0% respondent can't say on that.



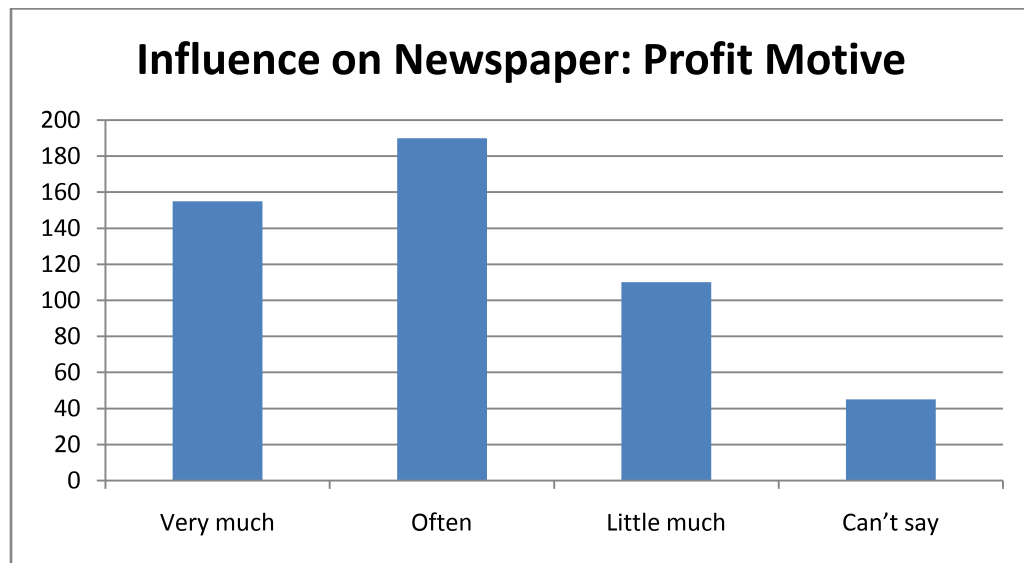
Graph-5.2.21

a) Profit Motive

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	Very much	155	31.0
2	Often	190	38.0
3	Little much	110	22.0
4	Can't say	45	9.0
	Total	500	100

Table-5.2.22

Table 5.2.22 indicated that 31.0% of total respondents replied that newspapers have profit motive, 38.0% replied often, 22.0% find it little much and 9.0% can't say on the question of profit motives by the newspapers.



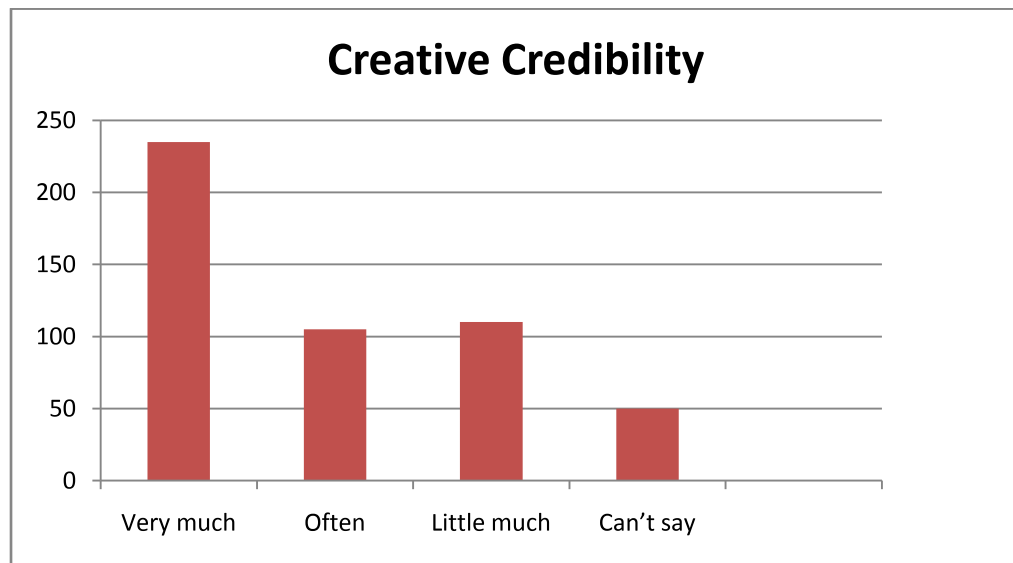
Graph 5.2.22

b) Creative Credibility

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	Very much	235	47.0
2	Often	105	21.0
3	Little much	110	22.0
4	Can't say	50	10.0
	Total	500	100

Table-5.2.23

Table 5.2.23 indicated the responses on the creative credibility of the newspapers 47.0% respondent replied very much, 21.0% found it often, 22.0% replied little much and 10.0% can't say on this question.



Graph-5.2.23

c) Social Responsibility

Sl.	Response	Frequency	Percentage (%)
1	Very much	235	47.0
2	Often	125	25.0
3	Little much	120	24.0
4	Can't say	20	4.0
	Total	500	100

Table-5.2.24

On the degree of role performed by the newspapers for Social Responsibility, 47.0% respondent found it very much, 25.0% considered it often, 24.0% responded it little much and 4.0% can't say about as mentioned in table 7.30 above

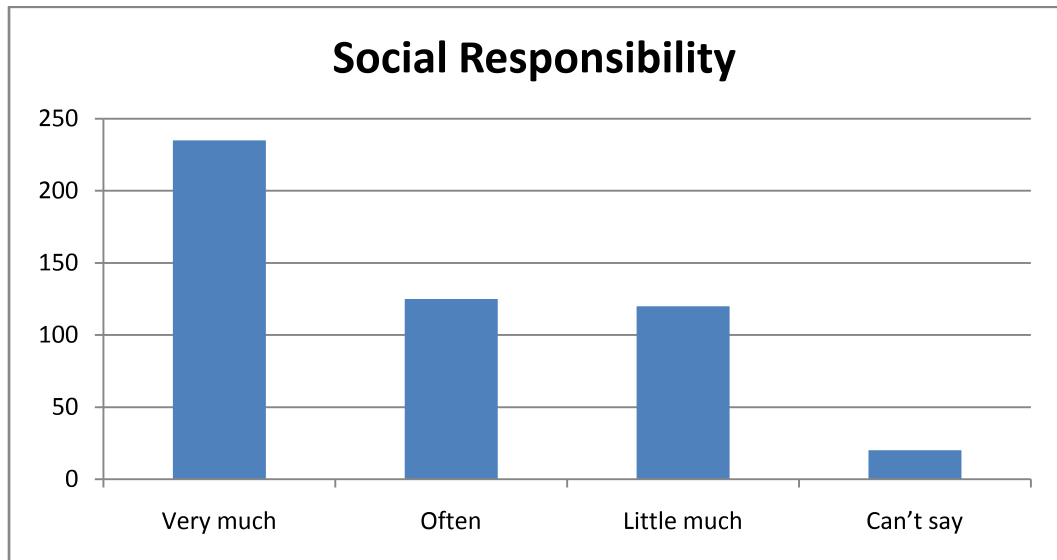


Table-5.2.24